छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा | चतुर्थ सत्र

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 26, शक सम्वत् 1946)

[अंक 02]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 26, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप एकदम सिविल ड्रेस में हैं। (हंसी)

जल जीवन मिशन के कार्यों में प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 225) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विगत 2 वर्षो में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किन-किन ठेकेदारों/संस्थाओं के विरूद्ध किस आधार पर नोटिस जारी किये गए हैं? किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें, किसके द्वारा, कब-कब की गई व इसमें क्या जांच की गई और कौन दोषी पाया गया? (ख) कंडिका 'क' अनुसार फर्जी दस्तावेज व गलत अनुभव प्रमाण पत्र व अपूर्ण जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने वाले किन-किन संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया, कार्यवाही की गई, प्रतिबंधित किया गया या राशि वसूल की गई? संस्थावार, कार्यवाहीवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) विगत 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेकेदारों/संस्थाकओं के विरूद्ध नोटिस जारी किये जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। ठेकेदारों/संस्थाओं के विरूद्ध की गई शिकायतें, शिकायतकर्ता का नाम, दिनांक, की गई जांच एवं जांच में पाये गये दोषी की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) कंडिका 'क' अनुसार फर्जी दस्तावेज व गलत अनुभव प्रमाण पत्र व अपूर्ण जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने वाले संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया, कार्यवाही की गई, प्रतिबंधित किया गया या राशि वसूल की गई की संस्थावार, कार्यवाहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, इसमें जो अनियमितता की गई है, उसके सम्बन्ध में कितने प्रकार की कितनी शिकायतें हैं और जो नोटिस जारी किया गया है, उसका आधार क्या है ? उसमें मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि 2,918 नोटिस जारी किए गए हैं। अब जिनकों नोटिस जारी किया गया है, उसमें 2-3 बिन्दु हैं। पहला, एक तो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। दूसरा, कार्य में गति धीमी है। तीसरा, आनुपातिक कार्य है। मैं इस प्रश्न में माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि अभी जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्ययोजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसे स्वीकृत किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार पूर्व सरकार का रवैया रहा है उसके कारण कार्य अभी भी प्रारंभ नहीं हुए हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इन शिकायतों पर निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर निराकरण की कोई समय अवधि निर्धारित करेंगे ? आप इस पर कब तक निर्णय लेंगे, इसकी समयावधि बतायेंगे ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धरम लाल कौशिक जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है। हमने बहुत विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की है। विगत 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ठेकेदार और संस्थाओं के विरूद्ध 2,918 नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस किन-किन कार्यों के लिए जारी किया गया, तो इसमें 13 अलग-अलग प्रकार के अनियमितताएं थीं, कमियां थीं, उसके कारण नोटिस जारी किए गए हैं। कार्य की गति धीमी होने के कारण, कार्य जारी होने के उपरांत निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण, तत्काल कार्य प्रारंभ करने बाबत, अनुबंध समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण, जलागार निर्माण कार्य में प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण, शेष कार्य को पूर्ण कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के कारण, कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं होने के कारण, अनुबंध में शेष बचे कार्य पूर्ण कर अंतिम देयक प्रस्तुत करने बाबत, वार्षिक टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र नियमानुसार नहीं होने पर, कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, कार्यों की धीमी प्रगति और अमानक स्तर के कार्यों के सम्पादन, आई.एस. सम्बन्धी प्रचार प्रसार में विलंब होने के कारण, कार्य बंद होने पर पुन: प्रारंभ करने बाबत, ये 13 अलग-अलग बिन्दु हैं, जिनके आधार पर 2,918 नोटिस जारी किए गए हैं। विगत 2 वर्षों में 72 ठेकेदारों के विरूद्ध 72 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जांच अलग-अलग स्तर पर की गई। जांच में जो संस्था दोषी पाये गये हैं, उन पर कार्रवाई की गई हैं। ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रित की गई। पाईप लाईन बिछाने हेतु खोदे गए सड़क मरम्मत हेतु निर्देशित किए गए। गुणवत्ता विहीन कार्य को तोड़ने की कार्यवाही की गई। चयनित स्त्रोत में जल की कमी के कारण नवीन स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही की गई। निविदा निरस्तीकरण एजेंसी को ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एजेंसी को ब्लेक लिस्ट भी किया गया, एजेंसी को डिबार भी किया गया। एजेंसी को अपात्र घोषित किया गया। शिकायत

तथ्यहीन, आधारहीन पाये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध भी किया गया है। विगत 2 वर्षों में फर्जी दस्तावेज, अनुभव प्रमाण-पत्र, अपूर्ण जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने वाले संस्थाओं को 26 नोटिस जारी किए गए हैं। आगे कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। एजेंसी को ब्लेक लिस्ट भी किया गया है, अलग-अलग एजेंसी को दो वर्ष के लिए डिबार भी किया गया है। अलग-अलग एजेंसी को दो वर्षों के लिए डी-बार भी किया गया है, उनको निविदा के लिए अपात्र भी घोषित किया गया है और कुछ संस्थाओं के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुबंध निरस्त किए जाने की अनुशंसा की है। यह राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी सभी कार्यवाही कर चुके हैं। अब क्या प्रश्न है?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- इतना व्यापक जवाब आया है। आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि इसमें जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है, उसके आधार पर जांच हुई है। जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, वह सही पाया गया है और सही पाने के बाद में केवल उनका अनुबंध निरस्त किया गया है। क्या यह कोई कार्रवाई है? उसके बाद भी उनको भुगतान किया गया है। अब मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर काम लिया गया है। यह काम थोड़ा-बहुत रूपये का नहीं बल्कि करोड़ों-अरबों रूपये का काम है। काम लेने के बाद में जब उनकी जांच की गई तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि फर्जी दसतावेज के आधार पर, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वे इनटाईटल नहीं थे। उनको आपने काम दिया। आपके अधिकारियों ने उनको जानबूझकर काम दिया। उसके बाद में जो जांच हुई है, उसमें आपने लिखा है कि उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। यह तो चार सौ बीसी का मामला है। आपने उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं कराया? यह तो ई.डी. का मामला है। यह 100-100 करोड़ रूपये का मामला है। इसमें जांच होनी चाहिए थी। आपने उनको ब्लैकलिस्ट किया था। उनको ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी आपके अधिकारियों ने उनको पेमेंट कर दिया। यह तो चार सौ बीसी का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जान-बूझकर फर्जी दस्तावेज लगाया, चार सौ बीसी का काम किया, उनके खिलाफ में आप एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगे क्या? दूसरी बात, यह बड़ा मामला है, यह कोई छोटा मामला नहीं है तो क्या आप इन समस्त मामले को ई.डी. से जांच करायेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जल जीवन मिशन को फर्जी दस्तावेज, फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर काम प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। उस पर प्रारंभिक जांच की गई है। जांच करने के बाद राज्य स्तरीय

उच्च पॉवर समिति को अनुशंसा की गई है। समिति विचार करके जो भी निर्णय करेगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समिति द्वारा एफ.आई.आर. करने की भी अनुशंसा हुई तो निश्चित रूप से एफ.आई.आर. करेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम लिया गया है। यह अभी का मामला नहीं है, यह पुराना मामला है। आप इस मामले को कब तक लंबित रखेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धरम लाल जी, मंत्री जी ने बता दिया है कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उनकी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई होगी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शिकायत को स्वीकार किया है। जांच हुई है तभी तो इन्होंने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटा प्रश्न कर लीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जांच हुई है तभी इन्होंने स्वीकार किया है तो क्या मंत्री जी उनके खिलाफ में एफ.आई. दर्ज करायेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो टेण्डर है, वह समूह जल प्रदाय योजना के टेण्डर थे, जो राज्य की समिति के द्वारा स्वीकृत टेण्डर थे। जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है, उसके पास जांच करके प्रतिवेदन भेजा गया है और वहां से जैसे ही जो भी कार्रवाई करने का निर्णय होगा, वह निश्चि रूप से कठोर कार्रवाई होगी। जल जीवन मिशन के काम में कोई भी लापरवाही करेगा तो उनको खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। मंत्री जी ने कितना कठोरता से बोला है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। क्या इसमें 10-20 साल बाद कठोर कार्रवाई होगी?

अध्यक्ष महोदय :- आप समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या 20 साल बाद कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि आप उसमें समय-सीमा बता दीजिये। आप दो महीने, तीन महीने या आपको सालभर लगे, यह सुनिश्चित तो हो जाये?

अध्यक्ष महोदय :- वह यथाशीघ्र बोल देंगे। श्री अजय चन्द्राकर जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्मार्ट सिटी परियोजना रायपुर अंतर्गत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (*क्र. 125) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** स्मार्ट सिटी परियोजना रायपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कौन-कौन से कार्य के लिये, किन-किन मदों से, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? इनमें से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण व निरस्त हुये तथा वर्तमान में इनकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? **(ख)** क्या उक्त परियोजना अंतर्गत 24*7 जल एवं बिजली आपूर्ति प्रदाय करने हेतु कार्ययोजना में शामिल किया गया है? यदि हां, तो कब और कितनी लागत आयी व भौतिक स्थिति क्या है? **(ग)** उक्त परियोजना व वित्तीय वर्ष अंतर्गत बूढ़ा तालाब, नगर निगम रायपुर में क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए कितने निरस्त किये गये और कितने का पुनः टेंडर किया गया तथा उसकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? कितने पूर्ण/अपूर्ण हैं और अपूर्ण के कारण क्या हैं तथा विलंब करने वाले एजेंसी के खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2024-25 तक रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत राशि एवं कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की संख्या 230 है जिनमें से 204 कार्य पूर्ण है, 18 कार्य प्रगतिरत है, 05 कार्य निरस्त एवं 03 कार्य फोर क्लोज हुये है। कार्यो की वर्तमान वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है।(ख)** जी हॉ। 24x7 जल आपूर्ति योजना स्वीकृत स्मार्ट सिटी प्लान वर्ष 2016 की कार्य योजना में शामिल है। 24x7 बिजली आपूर्ति का कोई भी प्रोजेक्ट रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नही किया गया है। अपितु रायपुर शहर के 11 मार्गों पर भूमिगत विद्युत केबल बिछाने की परियोजना रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की गई है। भूमिगत विद्युत केबल परियोजनाएं भी स्मार्ट सिटी प्लान अंतर्गत स्मार्ट रोड के घटक के रूप में स्वीकृत है। 24x7 जल आपूर्ति योजना के लिए राशि रू.158.59 करोड़ की राशि स्वीकृत है। अद्यतन राशि रू.109.61 का व्यय किया गया है। योजनांतर्गत 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। जिसमें पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण है तथा घरेलू नल कनेक्शन, ट्रायल एंड रन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। भूमिगत विद्युत केबल परियोजना अंतर्गत रायपुर शहर के 11 मार्गों पर भूमिगत विद्युत केबल बिछाने हेतु राशि रू.56.79 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अद्यतन राशि रू.52.90 करोड का व्यय हुआ है। योजनांतर्गत स्वीकृत समस्त 11 कार्य पूर्ण कर लिए गए है। सभी भूमिगत केबल परियोजनाएं पूर्ण होने के पश्चात सी.एस.पी.डी.सी.एल. को हैण्डओवर की जा चुकी है। **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' है।(ग)** वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2024-25 तक स्मार्ट सिटी

मद अंतर्गत बुढ़ातालाब रायपुर में कुल 30 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 29 कार्य पूर्ण है, 01 कार्य माननीय उच्च न्यायालय वाद क्र.WP(C)1844 एवं 2479 में पारित निर्णय दिनांक 12/05/2022 के परिपालन में फोर क्लोज किया गया है। कोई भी कार्य निरस्त नहीं किया गया है, तथा किसी भी कार्य का पुनः टेंडर नहीं किया गया है। कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी तथा विलंब के कारण एजेंसी पर की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार है।**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा प्रश्न शुरू करने के पहले माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण, माननीय मंत्री जी से ...। माननीय मंत्री जी, आपने जो परिशिष्ट मुझे दिया है और प्रगतिरत् कामों की सूची दी है, उसमें 212, 213, 214, 215, चार काम ऐसे हैं, जिसमें आपने लिखा है कि 100 प्रतिशत पूरा हो गया है और उसको प्रगतिरत् लिखे हैं तो 110-120 प्रतिशत जायेगा तो वह काम क्या होगा, यह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ समझ में आये तो कुछ पुछूँ ? 100 प्रतिशत पूरा लिखा है और प्रगतिरत् भी लिखा है, आपको परिशिष्ट में नंबर बता दिया है कि 212, 213, 214, 215, यहां प्रतिशत में काम 100 प्रतिशत पूरा है और स्थिति में प्रगतिरत् लिखा है । यह प्रश्न नहीं है भई ? पहले स्पष्ट कर दीजिए क्या है, फिर उसके आधार पर प्रश्न करूंगा ?

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाईये ना, अब सुन लीजिए ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भौतिक प्रगति है, वह 100 प्रतिशत है, भुगतान लंबित है, इसलिये वह प्रगतिरत् दिख रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 100 प्रतिशत पूरा होने के बाद और क्या लंबित रहेगा साहब ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान नहीं हुआ है, हिसाब-किताब नहीं हुआ है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने भौतिक प्रगति लिखा है, हिसाब-किताब नहीं लिखा है । कॉलम को ही पढ़ रहा हूँ भई । भौतिक प्रगति में 100 प्रतिशत पूरा हो गया है, वह तो हिसाब-किताब का विषय नहीं है और उसके बाद आपने कार्य की स्थिति पूर्ण-अपूर्ण में प्रगतिरत् लिखा है ।

श्री अरूण साव :- देखिये, जो मूल काम है, वह पूरा हो गया है, अतिरिक्त काम की आवश्यकता है, इसलिये प्रगतिरत् दिखा रहा है और इसीलिए राशि बची हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में पहले पूछ लेता हूँ कि 212, 213, 214, 215 में कौन-कौन से अतिरिक्त काम कर रहे हैं, इसी को बता दीजिए ? फिर आगे बढ़ूंगा ।

श्री अरूण साव :- जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसी को बता दीजिए कि अतिरिक्त काम कौन-कौन सा ले रहे हैं और जिसके कारण प्रगतिरत् बताया जा रहा है, उसको बता दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ ।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, वह जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आश्वासन समिति या किसी से भी साल भर में या इससे पहले पांच सालों में एक बात की जांच कीजिएगा, माननीय मंत्री जी में से किसी ने कहा है कि उपलब्ध करवा दूंगा तो किसी भी सदस्यों से पूछ लीजिए कि उपलब्ध हुआ है क्या ? यह किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए । उपलब्ध में भी आश्वासन बनता है तो उसकी अवधि होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न में आ जाईये । मैं समझ गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं प्रश्न कर लेता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न (क) में पूछा है, वह प्रिंटेड है, उसमें यह जानना चाहता हूँ कि कितने कार्यों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई ? जो भी कार्य आपने किये, उसकी कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई ? कौन-कौन से कार्यों की हुई ? कितने कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति हुई ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक बार प्रश्न पढ़ता हूँ । स्मार्ट सिटी परियोजना रायपुर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2024-2025 तक कौन-कौन से कार्य लिये ? किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हुई, इसमें कितने कार्य पूर्ण-अपूर्ण और निरस्त हुये ? वर्तमान में इसकी वित्तीय और भौतिक स्थिति क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध कराया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय महोदय, मैं पूरे विस्तार से पढ़ा हूँ, जो आपने काम करवाया है, मैं बहुत संक्षिप्त में पूछना चाहता हूँ, मुझे गोल-गोल घुमाने की आदत नहीं है । आपने कितने कार्यों की कितनी पुनरीक्षित स्वीकृति दी है, माननीय मूल मसला यहीं पर हैं । आप इसको भी बाद में दे देंगे तो आगे बढ़ जाऊंगा । मेरे लिये यह कोई प्रेस्टिजियस नहीं है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 230 कार्यों में से 56 कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितनी बार ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, आप बाद में उत्तर दे देंगे, मैं तो प्रेस्टीजियश नहीं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मूल प्रश्न में आईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ही तो है, मैंने पहला ही प्रश्न है कि कौन-कौन से कामों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है ? आपने बताया कि 56 कामों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, पर कितनी बार दी गई है, मैं यह प्रश्न पूछ रहा था । उसका उत्तर बाद में दे देंगे तो चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मंत्री जी बाद में उत्तर दे देंगे, आप आगे बढ़िए ।

श्री अरूण साव :- ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आप रायपुर को 24x7 जल आपूर्ति कर रहे हैं । यह परियोजना 2016 से लागू है तो यह परियोजना कब तक पूरी होगी, कब तक कितने घरों को आप पानी 24x7 देंगे और अभी कितने प्रतिशत काम पूरे हुए हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी प्लान के अंतर्गत 24x7 जल आपूर्ति योजना 2016 में शामिल है । इसके लिए 158.59 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत है, जिसमें 4.36 करोड़ रूपए ओएण्डम के लिए है । कार्यादेश 31.3.2022 को जारी किया गया है । आज की तिथि में 109.6 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं । 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए हैं और कार्य प्रारंभ होने के बाद भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ करने पर प्वाइंट की लंबाई प्रारंभिक रूप से 162.3 ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैंने उतना डिटेल पूछा ही नहीं है । मैंने यह पूछा है कि वह योजना कब पूरी होगी, आप कब तक 24x7 पानी दे देंगे ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, हम मार्च, 2025 तक पूरा कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप मार्च, 2025 तक देंगे । मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी, मैंने प्रश्न (ग) में पूछा है कि बूढ़ा तालाब में कौन-कौन से मद में आपने कितने काम कराये हैं और सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी या नगर निगम थी या कौन सी एजेंसी थी और कितने कार्य अधूरे हैं और कितने कार्य बंद हैं या चालू हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बूढ़ा तालाब जिसे स्वामी विवेकानंद परिसर भी कहते हैं, इसमें 35.07 करोड़ रूपए के 30 कार्य स्वीकृत हुए थे, 30 कार्य में से 29 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं । एक काम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फोर क्लोज किया गया । इतनी जानकारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह उत्तर में है । मैंने पूरक प्रश्न पूछा है, आपने उसका उत्तर नहीं दिया । बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण या जिसको आपने विवेकानंद परिसर कहा, उसके सौंदर्यीकरण में कौन-कौन से मद की राशि उपयोग की गई और सबकी एजेंसी क्या स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी या और कोई एजेंसी ने वहां काम किया ? आपने जो राशि व्यय की है, वह राशि मैं अलग-अलग पूछ रहा हूं ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बूढ़ा तालाब के पूरे काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही हुए हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पूरा करने के बाद 19.12.2023 को ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं इंट्रप्शन कर रहा हूं । कौन-कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब में किया गया और क्या सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी या कौन सी एजेंसी थी ? कौन-कौन सी मद थी या सिर्फ स्मार्ट सिटी मद थी या और कोई दूसरे मद थे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत काम हुए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मद नहीं बता सकते तो उसको रहने दीजिए, मैं आखिरी प्रश्न कर लेता हूं ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं । मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है । 30 कार्यों में से 11 काम रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 4 के द्वारा और शेष कार्य स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मद पूछा है । कौन-कौन से मद को आपने बूढ़ा तालाब में व्यय किया है । पर्यटन मण्डल का मद खर्च किया होगा, निगम का मद खर्च किया होगा, स्मार्ट सिटी का मद खर्च किया होगा, 15वें वित्त आयोग का किया होगा, अधोसंरचना मद का किया होगा?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे मद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बता रहा हूं कि उसमें विभिन्न मदों का उपयोग हुआ है। पर्यटन मंडल की राशि, स्मार्ट सिटी की राशि, निगम की राशि का भी उपयोग हुआ है। उसमें कई मदों की राशि का उपयोग हुआ है, यही तो मुख्य विषय है। मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसकी जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे, क्योंकि मेरे पास जो दस्तावेज हैं, उसके अनुसार आपने जितने काम पूरे बताए हैं, वह सब अधूरे हैं। अलग-अलग दस्तावेज हैं, जिन्हें मैं समय पर प्रस्तुत करुंगा, यह बाद की बात है, लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि आपने बताए हैं कि सारे काम पूरे हैं, तो क्या आपका कोई अधिकारी, आपका सिचव या आप काम पूरे हुए हैं, इस बात को देखे हैं? मैं नरैया तालाब बता देता हूं, मटन मार्केट बता देता हूं, महाराजबंध बता देता हूं और इस प्रकार के कामों की श्रृंखला बता देता हूं, जो कि अधूरे पड़े हैं, जिन्हें कि आपने पूरा कहा है। क्या उसका मेरे साथ निरीक्षण करवायेंगे? मैं अभी कोई भी भ्रष्टाचार, corruption या इधर-उधर के शब्द नहीं बोला हूं। जिन स्थलों को आप पूरा बोल रहे हैं, उसे क्या मेरे सामने या मुझे छोड़ दीजिए बल्कि रायपुर शहर के विधायकों के सामने उसकी जांच करवायेंगे कि क्या वह पूरे हो गए हैं?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर स्मार्ट सिटी के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है और स्मार्ट सिटी ने ये काम करने के बाद 19.12.2023 को इसे टूरिज्म बोर्ड को हैंडओवर किया है, जिसका तब दिनांक 20.12.2023 से संचालन, संधारण टूरिज़्म बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछा दूसरी चीज़ हूं। मैंने यह पूछा है कि आपने सब कामों को पूरा बताया है, जबकि मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी के अधिकांश काम अधूरे पड़े हुए हैं। उसे मेरे सामने मत करवाइए, रायपुर शहर के विधायकों के सामने करवाइए।

अध्यक्ष महोदय :- अधूरे काम को दिखवा लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, दिखवाना नहीं है। वह कह रहे हैं कि पूरे हो गए हैं और मैं कह रहा हूं कि पूरे नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वही तो वह देखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो क्या आप इसकी जांच/परीक्षण मेरे सामने या रायपुर शहर के चारों विधायकों के सामने करवायेंगे क्या?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कामों का परीक्षण करा लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्वासन में समय सीमा आ जाए, क्योंकि वह indefinite रहता है। आप आश्वासन समिति देख लीजिए, आपके पहले सत्र के आश्वासन अधूरे पड़े हुए हैं, इसलिए आश्वासन की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- शीघ्र बोल दिए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि कोई समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि यह निर्माण कार्य चल रहे हैं, अन्यथा यह पूरा हो जाएगा। आज विधान सभा चल रही है, तीन महीने, 15 दिन, 20 दिन में एजेंसियों में जिन स्तरों पर काम है, indefinite में तो वह पूरे हो जाएंगे और indefinite दिखवा लेंगे का कोई मतलब नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश मूणत जी, एक छोटा सा प्रश्न कीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उपमुख्यमंत्री जी से छोटा सा प्रश्न किया था। उसमें एक ही प्रश्न है कि बूढ़ातालाब में तीन एजेंसियों ने काम किया है। जब स्मार्ट सिटी ने काम कम्प्लीट कर लिया, तो मैं आपके संज्ञान में लाते हुए आपके माध्यम से केवल इतनी ही जानकारी चाहता हूं कि 6 करोड़ रुपए का फौव्वारा लगा, वह आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया और जब वह चालू नहीं हो पाया तो किस आधार पर जो पूर्व एजेंसी ने काम किया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसमें सबसे पहले पर्यटन मंडल ने काम किया, नगर निगम ने काम किया और उसी में स्मार्ट सिटी ने भी काम किया, यानी एक तालाब में सिर्फ एक काम को लेकर इतनी एजेंसियों ने काम किया, तो क्या इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेंगे और इन तीनों एजेंसियों ने कौन-कौन से काम किए हैं, स्पेशिफिक, क्या उन अधिकारियों ने अगर उसमें लीपापोती की है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? यह एक छोटा सा संक्षिप्त प्रश्न है। दूसरा, वहां पर जो फौव्वारा लगा है।

अध्यक्ष महोदय :-बस, पहले प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर-02 में यह प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, उद्भुत नहीं होता।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है। मूल प्रश्न में यह बूढ़ापारा का प्रश्न है। इसमें क्लीयर लिखा हुआ है कि उक्त परियोजना व वित्तीय वर्ष अंतर्गत बूढ़ा तालाब, नगर निगम रायपुर में क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए, कितने निरस्त किए गए और कितने का पुन: टेंडर किया गया। कितने-कितने हुए, यह तो मूल प्रश्न में ही स्पष्ट लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी की एजेंसी, आज मेरे अतारांकित प्रश्न में इसका उत्तर आया है, मैं आपको बता रहा हूं । विभाग किस प्रकार से निगम के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर काम करता है, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने पूछा था कि क्या नगर निगम ने स्मार्ट सिटी ने कोई एजेंसी तय की ? इस प्रश्न के जवाब में खारिज कर दिया गया कि कोई एजेंसी तय नहीं की गयी है। इनकी यह नोटशीट स्पष्ट है, जिसके अंदर इतने अधिकारी कार्यरत् हैं और जिनको करोड़ों रूपए पेमेंट हो रहा है। मेरे प्रश्न के उत्तर में विभाग ने एजेंसी का होना नकार दिया और यही विभाग माननीय अजय चन्द्राकर जी के प्रश्न के उत्तर में कह रहा है कि एजेंसी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि मैं किसे सही मानूं ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सुनील जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एकदम छोटा-सा प्रश्न पूछिये।

श्री सुनील सोनी (रायपुर-दक्षिण) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा। पांच साल तक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की जो हालत थी, उनके पास टोटी लगाने के लिए पैसा नहीं था। मेरी यह एकमात्र पीड़ा है, क्योंकि मैं दो बार महापौर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पीड़ा बाद में बताईयेगा। प्रश्न करिये।

श्री सुनील सोनी :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कर रहा हूं। हमारी सरकार को अनियमितताओं का भंडार मिला है। क्योंकि मैं भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी का भी सदस्य था। इसकी जांच चल रही है और पूर्व सरकार ने स्मार्ट सिटी का सैकड़ों करोड़ रूपये [xx] का काम किया है। केंद्र सरकार के जो मापदण्ड थे, उस मापदण्ड पर एक भी काम नहीं किये गये। आज मेरा प्रश्न यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, इसकी पूरी जांच होगी तो सारी चीजें सामने आ जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए प्रश्न हो गया। मंत्री जी ने जांच की घोषणा कर दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह निर्माण कार्य के विषय हैं। यह जांच 8 दिन, 15 दिन, 2 महीने या 3 महीने में पूरी हो जायेगी या पूरी करवाने की कोशिश होगी ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, आप उसको समय-सीमा में निगमित कर दीजिये। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। मंत्री जी, समय सीमा निर्धारित कर दीजियेगा।

भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको में कार्यरत स्थानीय कर्मचारी

[वाणिज्य एवं उद्योग]

3. (*क्र. 87) श्री फूलसिंह राठिया :- क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरबा जिला अन्तर्गत भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको में कोरबा जिले के कितने मूल निवासियों को रोजगार दिया गया है ? बालको वेदांता कंपनी में कुल कितने कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत हैं, इनमें से कितने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से हैं ? **(ख)** क्या वेदांता स्किल स्कूल बालको के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाता है? यदि हां, तो उन्हें रोजगार एवं बेरोजगार भत्ता दिए जाने हेतु शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- (क) कोरबा जिला अंतर्गत भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको में कोरबा जिले के 505 मूल निवासियों को रोजगार दिया गया है। बालको वेदांता कंपनी में 1986 कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से 607 छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से हैं। **(ख)** हां, वेदांता स्किल स्कूलबालको के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वेदांता स्किल स्कुल में प्रशिक्षितों को रोजगार एवं बेरोजगार भत्ता दिये जाने हेतु पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है।

श्री फूलसिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि कोरबा जिला के भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको ने कितने लोगों को रोजगार दिया है ? उसमें छत्तीसगढ़ के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं छत्तीसगढ़ के बाहर से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही पूरी जानकारी दे दी है परंतु माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो फिर बता देता हूं कि वेदांता बालको कंपनी में 1986 कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं, जिसमें से 607 छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से हैं और 505 मूल निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

श्री फूलसिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब वेदांता बालको कंपनी में प्रशिक्षण दिया जाता है तो उन लोगों को रोजगार कहां दिया जाता है ? क्या इसमें शासन का कोई नियम है कि जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाये ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, वेदांता बालको कंपनी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे काम सीख जायें और उसके बाद उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। वेदांता बालको कंपनी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रशिक्षण देने के बाद उनको बालको में ही रोजगार दिया जायेगा। उनकी ठेका कंपनी है, जिसमें कुछ लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। बालको कंपनी में पूर्ण रूप से रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान है और बालको द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप एक प्रश्न कर लीजिये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता ही होगा और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे कि भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको का 49 प्रतिशत शेयर, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक नीति है, उसके अंतर्गत उस संस्था में भी काम होना चाहिए। जनाब, एक औद्योगिक नीति वर्ष 2019 से 2024 "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" के नाम से बनी थी, उसमें यह था कि इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत घोषित किये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम में, स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी को अभी माननीय विष्णु देव साय साहब की सरकार ने 4 नवम्बर, 2024 को जारी किया है उसमें बिन्दु 12.19 पर यही है कि औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2024 से 2023 तक जो घोषित किये गये औद्योगिक निवेश अकुशल कर्मचारियों, श्रमिकों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी कोरबा के निवासी हैं और माननीय प्रश्न पूछने वाले विधायक भी कोरबा के ही उस विधान सभा क्षेत्र से आते हैं जहां भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको लगा हुआ है। ऐसे स्थान में जहां मंत्री जी संरक्षण नहीं देंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा ? और जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता तो ऐसे नियमों में संशोधन किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में माननीय मंत्री जी का क्या कहना है?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि अकुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध

कराना अनिवार्य है। उसमें मैनेजमेंट का जो रहता है यह अधिनियम में है। वर्ष 2019-2024 की औद्योगिक विकास नीति में है और अभी वर्ष 2023-2024 औद्योगिक विकास नीति बनी, उसमें भी नियम किया गया है। चूंकि जो भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको की बात हो रही है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत यह कंपनी है। अब आप सबको उस कंपनी के बारे में मालूम है बाकी हम लोग भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वेदांता बालको को सब्सीडी नहीं देते हैं, अनुदान नहीं देते हैं। उसमें इस कारण से इसलिए वह अपने अनुदान हेतु अपात्र घोषित हैं। इस नीति में कोई छूट दी गई है। अत: रोजगार प्रावधान लागू नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप वेदांता बालको को अनुदान देंगे, ऐसी कौन सी नीति है ? छत्तीसगढ़ की सरकार वेदांता बालको को अनुदान क्या देगी ? वेदांता बालको का 49 प्रतिशत शेयर, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का है, वेदांता बालको ने उसमें से अब तक क्या दिया है ? यह तो बड़ा घालमेल है, आपके क्षेत्र में है, यह मुझे पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी विस्तृत जांच करायें जो आपने, विष्णु देव साय साहब, मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक नीति बनायी है । आपकी यह डबल इंजन की सरकार है तो वह भी उधर से आया है। एक इंजन इधर से लगा है और एक इंजन इधर से लगा है। तो उसकी पूर्ण रूप से जांच करवाईये। इसमें कहां घालमेल है, आप कहां पर चुप हैं और मैं कहां पर चुप हूँ। यहां पर उसमें विचार-विमर्श करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी गंभीरता से जांच करवाईये। वह आपका ही विधान सभा क्षेत्र है। आपके क्षेत्र के नवजवानों को नौकरी मिले।

अध्यक्ष महोदय :- जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव है, आप उसको देख लीजिएगा। इनका गंभीर सुझाव है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें बहुत प्रश्न हो गये।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत ही अच्छा सुझाव है। निश्चित तौर पर हम लोग इसमें विचार करेंगे।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भारत एल्युमिनियम कंपनी वेदांता द्वारा कोयला खदान संचालित की जा रही है जो आज बंद पड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है जहां पर भारत एल्युमिनियम कंपनी वेदांता बालको संचालित है। इसके द्वारा कोयला खदान संचालित की जा रही है, परंतु 25 वर्ष संचालित करने के बाद कोयला खदान बंद कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप कोयला में कहां आ गये?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी कंपनी की कोयला खदान है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है?

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- वहां पर जिन युवाओं को रोजगार दिया गया था, कोरोनाकाल में उनका ट्रांसफर किया गया कि कोरोनाकाल की अवधि में इनका पेपर है। वह कोरोनाकाल में कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई जाकर कैसे ज्वाईन करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिए।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें नहीं है। कोयला खदान की जो बात बोल रहे हैं, वह चोटिया कोयला खदान का है। इसके बारे में मेरे को जानकारी उपलब्ध नहीं है, अभी बता पाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- उसके लिए अलग से सूचना देनी पड़ेगी।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से सूचना दे देंगे तो उसको बता देंगे।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री बघेल लखेश्वर जी।

शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सामग्री वितरण में गड़बड़ी होने की शिकायतें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 399) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बस्तर में ऐसी कितनी राशन दुकानें हैं जहां दुकान प्रभारियों ने उन्हें आवश्यकता से कम मात्रा में खाद्यान्न सामग्री प्राप्त होने की शिकायत/जानकारी दी? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या जिला बस्तर में राशन दुकानों द्वारा कम मात्रा में सामग्री प्रदाय करने अथवा सामग्री दिये ही नहीं जाने की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां तो उसकी जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्न "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) बस्तर जिले में वर्ष 2024-25 में अप्रैल से नवंबर 2024 तक उचित मूल्य दुकानों में आवश्यकता से कम मात्रा में खाद्यान्न भण्डारण होने के कारण विकासखण्ड जगदलपुर में 231 उचित मूल्य दुकान, बस्तर में 232 उचित मूल्य दुकान, बकावण्ड में 131 उचित मूल्य दुकान, बास्तानार में 84 उचित मूल्य दुकान, दरभा में 112 उचित मूल्य दुकान, तोकापाल में 96 उचित मूल्य दुकान, लोहण्डीगुड़ा में 93 उचित मूल्य दुकान द्वारा अतिरिक्त आबंटन की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग की गयी। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** [1]अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश "क" के उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न सामग्री के अतिरिक्त आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर संबंधित माह में अतिरिक्त आबंटन जारी कर उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण कराया गया। माह नवंबर 2024 में 100 उचित मूल्य दुकानों में चना का अतिरिक्त आबंटन जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध 13 उचित मूल्य दुकानों में अतिरिक्त आबंटन का भण्डारण कराया गया, प्रदाय केन्द्रों में चना उपलब्ध नहीं होने के कारण 87 उचित मूल्य दुकानों में चना का भण्डारण शेष है। प्रश्नांश "ख" के शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बस्तर जिला की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सामग्री वितरण में गड़बड़ी के संबंध में था। इस गड़बड़ी के संबंध में मेरे द्वारा जिला प्रशासन को, मंत्री जी को जुलाई से लेकर अभी तक कम से कम 15-20 लेटर लिखा गया है लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी। अभी तक प्रदेश स्तर से या जिला स्तर से खाद्य सामग्री शासकीय उचित मूल्य दुकानों में कम से कम 40 से 50 प्रतिशत कम उपलब्ध कराई जाती है, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि इसका क्या कारण है और साथ ही बस्तर जिला में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी की बस्तर जिला के संबंध में शिकायत मिली है, कलेक्टर साहब के माध्यम से भी मिली है। वहां हमने 18 राशन दुकानों की रेन्डम जांच कराई, उन 18 दुकानों में से 17 राशन दुकानों में गड़बड़ी नहीं मिली है, एक राशन दुकान आडावाल में शिकायत सही पाई गई है। उस शिकायत के आधार पर दिनांक 13.12.2024 को अनुविभागीय अधिकारी बस्तर के द्वारा दुकान को निलंबित किया गया है और उस राशन दुकान को करमरी ग्राम पंचायत में अटैच किया गया है। इसके साथ ही साथ बस्तर जिला में अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के दौरान 15 अन्य शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें 14 शिकायत सही पाई गई है और 1 शिकायत गलत मिली है। यह जो 14 राशन दुकानों में जांच हुई है, उसमें 3 राशन दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है और 3 राशन दुकानों का आवंटन निलंबित किया गया है और 8 राशन दुकानों को एस.डी.एम. कोर्ट से नोटिस जारी हुई है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी प्रश्न किया था कि बस्तर जिले में कितनी राशन दुकान हैं?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में 485 राशन दुकानें हैं।

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री बघेल लखेश्वर :- आपके द्वारा इसमें बताया गया है कि बस्तर में 232, जगदलपुर में 231, बकावण्ड में 131, इस प्रकार 979 उचित मूल्य दुकान की अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है। ऐसा उल्लेख किया है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नाम दिया है । उसमें चावल का आवंटन राशन दुकान वाले लोगों ने मांग की है तो जिला को अधिकार है, पुलिस प्रकृत माध्यम से अगर राशन दुकान वाले चावल की मांग करते हैं तो दिया जाये ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह उत्तर नहीं आया कि राज्य स्तर से बस्तर जिला में क्या कम राशन भेजा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप कम राशन का बता दीजिये ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन कम नहीं जाता है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर निर्धारित मांग के अनुसार क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाता है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन कम की जो बात है उसमें दो महीने पूर्व का लिया जाता है, दो महीने पहले का वहां जो राशन बचा रहता है उसको कटौती करके भेजा जाता है यह नियम आप ही लोगों के कार्यकाल का है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीनी लेवल पर जानकारी मंत्री जी नहीं दे रहे हैं लेकिन हर महीने प्रत्येक दुकान में 50 प्रतिशत राशन बिक जाता है । अतिरिक्त मांग की जाती है जो कि समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है । यदि समय पर उपलब्ध नहीं होगा, आप दूसरे महीने में उपलब्ध करायेंगे तो फिंगर कैसे लेंगे ? आपकी मशीन तो लोड ही नहीं लेती है । भारी अनियमितता है, इसको थोड़ी गंभीरता से लीजिये । मैं बार-बार अवगत करा रहा हूं, पूरे प्रदेश की ऐसी ही स्थिति है, विभाग इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है । मेरी मंशा यह है कि व्यवस्था सुधरे । हम लोग इसके लिये ही प्रश्न करते हैं कि हम लोगों को कब तक...?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, क्या बस्तर में व्यवस्था को सुधारेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- जी, हां पूरी व्यवस्था सुधारेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, कवासी जी आप बोलिये ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 और व्यवस्था है । आपकी जो वितरण मशीन है, जो वितरण मशीन उपलब्ध करायी गयी यह कब खरीदी गयी थी और कितने लागत की है ? वह मशीन बार-बार खराब हो रही है, हर महीने में से 8-10 दिन तो मशीन को बनाने में लग जाता है तो उस संबंध में थोड़ा बताईयेगा ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी मशीन खराब है उसको बदल देंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अच्छी मशीन लाईये भई ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी अगर शिकायत हो तो बता दीजिये, हम उसको बदलेंगे ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही राशन दुकानों में कमीशन समय पर वितरण नहीं होता । बारदाना का पैसा 2-3 सालों से अभी तक नहीं मिला है, वितरक कैसे चलायेंगे ? आप कमीशन समय पर नहीं देते हैं ? उसके बाद आप लोग उसको चोरी करने के लिये मजबूर कर देते हैं । समय पर वितरण हो जाये, समय पर सब-कुछ हो जाये तब तो होगा, व्यवस्था सुधरेगी इसलिये राशन वितरण में भारी अनियमितता है, अव्यवस्था है । मेरा आपसे और विभाग से गंभीरता से यह निवेदन है कि इस संबंध में आप थोड़ा विचार करिये, जमीनी स्तर पर भेजिये, यह मेरी मांग है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, गंभीरता से इस पर कार्यवाही करिये । कवासी जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसी में थोड़ा सा पूछना था ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में क्या ? आपका प्रश्न आ गया है ? आप अपने प्रश्न में आ जाईये, इसका जवाब आ गया है ।

सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गाँवों में पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

5. (*क्र. 377) श्री कवासी लखमा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गाँव परिया, नागलगुण्डा एवं मुलेर में पुलिया निर्माणाधीन है या पूर्ण निर्मित हो गयी है? (ख) इनका प्रशासकीय स्वीकृति कब प्रदान की गयी? प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक सहित, स्थलवार, कार्यवार, लागत सहित जानकारी देवें? (ग) उक्त कार्य की निर्माण एजेंसी किसे बनाया गया? ठेका किस ठेकेदार को मिला? (घ) क्या बिना प्रशासकीय स्वीकृति के निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था? क्या इस संबंध में शिकायतें जिला प्रशासन को हुयी थी? अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है? दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) लोक निर्माण विभाग बस्तर मण्डल जगदलपुर के अन्तर्गत जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांव परिया, नागलगुण्डा एवं मुलेर में पुलिया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्माणाधीन था, वर्तमान में (कार्य बंद) निविदा प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी संलग्न[2] प्रपत्र अनुसार है। (ग) उक्त कार्य की कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. सुकमा संभाग सुकमा के द्वारा दिनांक 26.11.2024 को निविदा आमंत्रित, प्राप्ति तिथि 16.12.2024 एवं खोलने की तिथि 17.12.2024 निविदा स्वीकृति प्रश्चात निर्माण एजेंसी नियुक्त किया जावेगा। (घ) जी हां, उक्त क्षेत्र अत्यंत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय एवं पुलिस अधीक्षक सुकमा द्वारा निर्देशित किया गया कि यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करे। जिला प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रुप से लोकल स्तर पर कार्यरत ठेकेदार श्री विनोद सिंह राठौर एवं श्री राम नरेश भदौरिया को राजी किया गया है। जिसके परिपालन में वर्तमान स्थिति में परिया नाला में 01 नग स्लेब पूर्ण एवं मूलेर नाला में सुपरस्ट्रेक्चर का कार्य पूर्ण किया गया है, इस कार्य को पूर्ण करने के लिय पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में कार्य बंद है, निविदा स्तर की कार्यवाही पूर्ण होने एवं ऐजेंसी निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात कार्य पूर्ण कराया जावेगा। जिला प्रशासन के निर्देशानुरूप श्री डी.आर. कोर्राम, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, के द्वारा दिनांक 05/05/2024 को कार्य प्रारंभ कराया गया तथा दिनांक 31.05.2024 को श्री डी.आर. कोर्राम, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सुकमा संभाग सुकमा का सेवानिवृत हो गये। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जारी आदर्श आचार संहिता दिनांक 06.06.2024 तक प्रभावी होने के कारण कलेक्टर महोदय सुकमा द्वारा उनके कार्यालयीन पत्र क्र. 1693/एस.सी.ए./2024 सुकमा दिनांक 27.06.2024 को सामसुली-डोंगिनपारा मार्ग पर परिया नाला पर 8 मीटर 3 स्पॉन माईनर ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु 03 भागों में विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई एवं जिला कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा बडेसट्टी से गंधारपारा मार्ग में मुलेर नाला पर 8 मीटर 3 स्पॉन माईनर ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु 03 भागों में दिनांक 24.07.2024 को खनिज संस्थान न्यास विकास (डी.एम.एफ.) के तहत स्वीकृति प्रदान की गई। जी हां, इस संबंध में जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई है। चूँकि उक्त कार्य जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ किया गया एवं विभाग द्वारा विधि पूर्वक निविदा की कार्यवाही की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो रही है और न ही कोई अधिकारी जिम्मेदार है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था । मेरा प्रश्न था कि सुकमा जिला में जो सड़क बन रही है ।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी आप सुकमा कब से गये हो ?

श्री कवासी लखमा :- मैं क्या पाकिस्तान में रहता हूं ? (हंसी) आप मेरे साथ चलिये ।

[2] परिशिष्ट "दो"

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपके बड़े नेताओं के तो विचार पाकिस्तान वाले ही आ रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- आपके विचार बदलते रहते हैं ।

श्री अनुज शर्मा :- दादी आपके साथ जाने में बड़ा खतरा रहता है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने पहले से यह आदत बना ली कि ये पोल खोलेगा इसलिये थोड़ा बिगाड़ दो इसलिये अजय चंद्राकर जी को थोड़ा सा समझा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आपको कवासी जी को डिस्टर्ब नहीं करना है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से भी आशीर्वाद चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, पूरा है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बहुत गंभीर मामला है । हमारा नक्सलाईट पीड़ित क्षेत्र है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहां रोड बने, पुल बने, विकास हो लेकिन इन दोनों सड़कों में, चूंकि मैं पहले तो यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पहले यह कुबूल किया है कि मैंने ऐसा किया है, अधूरा बन गया, अभी टेंडर डल रहा है । कौन से नियम में पहले पुल बनेगा, अभी टेंडर डलेगा। ये प्रावधान अभी बदल दिया क्या ? ये पहला प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा ये मुलेर वाला रोड दंतेवाड़ा जिला से है पर यह सुकमा जिला का है। ये रोड पी.डब्ल्यू.डी. बना रहा है या प्रधानमंत्री वाला सड़क है? ये दो बातें पहले बोलें, उसके बाद आगे बताएं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो स्थान हैं परिया जो सुकमा राजस्व जिले में आता है और मुलेर नाला जो कि दंतेवाड़ा जिला में आता है, पर लोक निर्माण विभाग के हिसाब से डिवीज़न सुकमा है। परिया और मुलेर में सुरक्षा बलों का कैंप है। मई के महीने में वहां पर पुल निर्माण की आवश्यकता जिला प्रशासन ने महसूस किया कि बरसात में हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, उनकी सामग्री, खाद्य सामग्री आने-जाने में दिक्कत न हो तो दो पुल निर्माण करने के लिए निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि हम बाकी काम की प्रशासकीय स्वीकृति कर देंगे । बरसात से पहले ये पुल का निर्माण करा लो। लोकसभा का आचार संहिता प्रचलनशील था और वह काम दिनांक 05/05/2024 को प्रारंभ किया गया। शिकायत हुई तो वह काम रोक दिया गया। कोई भुगतान उस पर से नहीं हुआ है। आज उन दोनों पुलियों की निविदा खोली जानी है। निविदा में जो एजेंसी निर्धारित होगी, उसके हिसाब से इन दोनों पुलियों का निर्माण किया जाएगा।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, बताइए कि वह रोड पी.डब्ल्यू.डी. वाला है या प्रधानमंत्री वाला है?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में रोड के बारे में नहीं है, केवल पुलिया के बारे में है पर जो मार्ग है, वह पी.डब्ल्यू.डी. बना रहा है। ये मार्ग भारत सरकार द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए. योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। दोनों पुलियों के निर्माण की स्वीकृति पूर्व में कलेक्टर द्वारा दी गई थी ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में तो गड़बड़ी है। ये जो एस.ओ.आर. है, जो प्रधानमंत्री वाले में पुल बनाने में एस्टीमेट ज्यादा पैसा लगता है और पी.डब्ल्यू.डी. में कम लगता है। अगर प्रधानमंत्री सड़क पी.डब्ल्यू.डी. रोड में बनेगा तो प्रदेश से अनुमति लेना पड़ता है। ये अनुमति लिया है क्या? प्रधानमंत्री सड़क का एस्टीमेट कैसा बना? वह 40 है। 40 प्रतिशत में वह एस्टीमेट बना है। तो इसका राज्य स्तर से अनुमति ली है क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि निविदा निकाली गयी है, निविदा आज खोली जाएगी। मैं दोनों पुलियों के बारे में बता रहा हूं। निविदा आमंत्रित की गई है। आज निविदा खोलने की तिथि है और एजेंसी निर्धारित कर उस पर काम को आगे किया जाएगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निविदा में दो ठेकेदार हैं, जो लिखा हैं न श्री विनोद सिंह राठौर एवं श्री राम नरेश भदौरिया। इन्हीं दो लोगों को फॉर्म दिया हुआ है और बिना स्वीकृति के, बिना ऑर्डर के पहले बने हुए हैं। ये एस.ओ.आर. प्रधानमंत्री नाम से रोड पुल बनता है न, उसके एस.ओ.आर. से बना है। इसलिए एस.ओ.आर. बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत रेट बढ़ाने के लिए आपसे अनुमति लिया है क्या? पी.डब्ल्यू.डी के रेट से ये पुल ज्यादा से बढ़ रहा है और उसके बाद भी एक ही नाला में तीन पुल बनाने की क्या जरूरत थी? अगर ठेकेदार को बनाना है तो एक ही पुल बनाना चाहिए और तीन-तीन पुल पंचायत को दे देते। इसलिए इसका सबसे पहले वहां का इंजीनियर जो एस.डी.ओ. पद में था, जब उस समय मई महीना में लोकसभा का आचारसंहिता लगा था। उसी समय ये फटाफट काम किए। बाद में गांव वाले आंदोलन किए। धरना दिए। वह रुक गया था। अब उसी ठेकेदार को फिर देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस सब इंजीनियर को और पी.डब्ल्यू.डी. के ई.ई. को सस्पेंड करेंगे क्या?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल दोनों पुलिया निर्माण से संबंधित है, सड़क से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य सड़क से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं । वे अलग से प्रश्न करेंगे तो उत्तर ज़रूर दूंगा ।

श्री कवासी लखमा :- सड़क पर जो पुल बन रहा है वह प्रधानमंत्री योजना में बन रहा है और ऐसा करके जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का चूना लगा रहे हैं । 60 लाख में होने वाले काम को 1 करोड़, 20 लाख में किया जा रहा है । एक नाले में तीन-तीन पुलिया की क्या जरूरत है ? अगर बनाना ही है तो एक ही बड़ा पुलिया बनाइए । परिया नाला में तीन, मुलेर नाला में तीन, ये किस हिसाब से बना रहे हैं ? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, [xx] के लिए । मेरी यही मांग है कि दोनों सब इंजीनियर और ई.ई. पर कार्रवाई करेंगे क्या ? हम तो चाहते हैं कि पुल बने, लेकिन जो रेट है, जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मापदण्ड है उसके हिसाब से बनें । जनता के पैसों का दुरूपयोग न हो । जनता जहां मांग करती है, वहां तो दे नहीं रहे हैं । हमारी सरकार में कितने पुल बन रहे थे, स्लैब ढल रहे थे, पिछले सत्र में हमने प्रश्न लगाया था लेकिन आपने उसको तो चालू नहीं किया । आपका शासन आने के बाद उसको पूरा नहीं किया गया और ये कार्य बिना अनुमति के कैसे चालू किया गया ? कार्य चालू करने वाला आपसे बड़ा है क्या, सब इंजीनियर सरकार से बड़ा होता है क्या ? इसलिए मेरी एक ही मांग है कि दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे क्या ? आप पुल बनवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दो पुल के निर्माण से संबंधित है । सड़क निर्माण के संबंध में ।

श्री कवासी लखमा :- मंत्री जी, दो पुल कह रहे हैं, जबकि तीन पुलों का निर्माण हो रहा है । परिया और मुलेर में तीन-तीन पुल । महानदी जैसी बड़ी नदी में एक पुल बनता है, इतने छोटे नाले में तीन-तीन पुल कैसे ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई अनियमितता होगी तो माननीय सदस्य मुझे दे देंगे, मैं निश्चित रूप से दिखवा लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पुल बन गया है, टेंडर आज खुला है । दूसरा, मंत्री जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि आदर्श आचार संहिता लागू थी, उस समय इसकी स्वीकृति करके काम कराया गया है । दो बड़ी बातें हैं और यहां न तो राज्य सरकार से अनुमति है और इसकी कोई अन्य प्रक्रिया हुई है । माननीय सदस्य की यही मांग है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते समय मैंने बहुत स्पष्ट किया कि सुरक्षा बल के कैम्प हैं । बरसात से पहले उनकी खाद्य और अन्य सामाग्री पहुंचाने में दिक्कत होगी । जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने काम प्रारंभ कराया था । एक में केवल स्लैब का निर्माण हुआ है और दूसरे में सुपर स्ट्रक्चर का काम पूरा हुआ है किंतु उन कामों का एक रूपए का भी भुगतान नहीं हुआ है । अभी दोनों का टेंडर लगा है और आज निविदा खुलने वाली है जो एजेंसी तय होगी । उस हिसाब से कार्य होगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने स्वीकार किया और उत्तर में लिखा है कि भदौरिया और राठौर, दो को बुलाकर आपने काम दिया और दोनों ने ही टेंडर दिया है, तीसरे को मौका मिला ही नहीं । इसमें सारे नियमों का उल्लंघन दिख रहा है । आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार से अनुमति नहीं है, टेंडर हुआ नहीं है । उसी ठेकेदार को बुलाकर दिया गया है,

दूसरे को टेंडर भी नहीं दे रहे हैं तो इसमें सारी अनियमिताएं दिखाई दे रही हैं और आपने स्वीकार किया है । आपने स्वीकार कर लिया है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे यह बताइए आप ?

श्री अरूण साव :- मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है । सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ।

श्री भूपेश बघेल :- हां या ना में बताइए, कार्रवाई करेंगे या नहीं ?

श्री विक्रम मंडावी :- बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ।

श्री भूपेश बघेल :- जब आपने सारी अनियमितताएं स्वीकार की हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री अरूण साव :- जैसे ही शिकायत पहुंची ।

श्री विक्रम मंडावी :- जिस अधिकारी ने अनियमितता की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाए गए)

श्री भूपेश बघेल :- क्या आप इसमें कार्रवाई करेंगे ? एक ही प्रश्न है।

श्री उमेश पटेल :- कार्रवाई करिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि एक रूपये का भी कोई भुगतान राज्य सरकार की ओर से नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भुगतान होना या नहीं होना अलग विषय है। नियम के विरूद्ध काम हुआ है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गए।)

श्री भूपेश बघेल :- आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- वह जादू की सड़क बनाई थी ना। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आपके संज्ञान में सब कुछ आ गया है, इसमें कार्रवाई होगी या नहीं होगी, जवाब दें। यदि आपके संज्ञान में सब आ गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका संरक्षण है। मैंने नहीं कहा कि इसमें संरक्षण आपका है और नहीं है तो कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं किए तो स्पष्ट है कि आपके संरक्षण से सब कुछ हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि बरसात के पूर्व मई का महीना था, सुरक्षाबलों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में...। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- दोषियों पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अरूण साव :- एक रूपये की भी पेमेंट राज्य सरकार से नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न छठवां। (व्यवधान)

नगर पालिक निगम दुर्ग अंतर्गत व्यावसायिक परिसर का निर्माण एवं आबंटन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (*क्र. 35) श्री गजेन्द्र यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** दुर्ग जिले अंतर्गत कितने व्यावसायिक परिसर का निर्माण हुआ है? वर्ष 2020-2021 से 25 नवम्बर, 2024 तक सत्रवार जानकारी देवें? समस्त व्यावसायिक परिसरों की वास्तविक स्थिति क्या है? पता सहित जानकारी प्रदाय करें? इनका आबंटन कब-कब किया गया है? यदि आबंटन किया गया है तो वर्तमान में कितने रिक्त एवं आबंटित है, संख्या बताएं? उक्त आबंटन में आरक्षण संबंधी आबंटन नहीं होने से अभी तक नई योजना बनाकर आबंटन क्यों नहीं किया गया है? **(ख)** आबंटित व्यावसायिक परिसरों का उपयोग आबंटित व्यक्ति द्वारा ही किया जा रहा है या मात्र कब्जा है? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के उक्त व्यावसायिक परिसरों की स्थिति जर्जर है? यदि हाँ तो उसका संधारण कब-कब किया गया है? संधारण किए जाने के दिशा निर्देश क्या रखे गये हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क), **(ख)** एवं **(ग)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप कार्रवाई करिए। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

श्री रिकेश सेन :- भूपेश बघेल जी माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह नाम लेकर भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। इसको विलोपित कराईए। अरूण साव के नाम को विलोपित कराईए। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गए।)

एक माननीय सदस्य :- सरकार के खजाने से एक भी पैसा नहीं गया है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रश्न में कोई भी मंत्री को सीधा भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। (व्यवधान) इनकी सरकार ने भी की है।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए हो गया। धर्मजीत जी बैठिए।

श्री भूपेश बघेल :- इस उत्तर से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:59 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री धर्मजीत सिंह :- किसी भी मंत्री को ये लोग सर्टिफिकेट देंगे। दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऐसा कभी प्रश्नकाल में हुआ नहीं है कि विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट मिले।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गए।)

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुन लीजिए जो भ्रष्टाचार के आरोप के नारेबाजी हुए थे, उसको मैंने विलोपित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12.00 बजे

सदन को सूचना

रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में छायाचित्र की प्रदर्शनी का विमोचन

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश के तुरंत पश्चात् रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विधान सभा के विगत 24 वर्षों के महत्वपूर्ण अवसरों से संबंधित छायाचित्र की प्रदर्शनी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की उपस्थिति में किया जाएगा। अत: उक्त अवसर पर आप सभी सदस्य, पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं। शून्यकाल।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा प्रदेश के दुर्बल लोगों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं व गरीबों के साथ जो ठगी हो रही है, उसमें हजारों-करोड़ों रूपये का लोन देकर गरीब आदिवासी महिलाओं व बच्चों को फंसाया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-46 के अनुसार राज्य का यह संवैधानिक उत्तरदायित्व बनता है कि जनता के दुर्बल वर्ग के विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हित में विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करें और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करें। मेरे पास कोरबा जिले की बहुत सारी महिलायें आई थीं। वह दो दिनों से रेलवे स्टेशन में सो रही थीं। वह दो दिन बाद बच्चों के साथ आईं और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें हमें इतने हजार रूपये के कर्ज दिये गये और इस कर्ज की उगाही के लिए वह हमारे घर व जमीन को बेचने की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहां जाएं? मैंने उन्हें सलाह दी कि आप लोग पहले पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाइये। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कि आदिवासी वर्ग से हैं और आदिवासी वर्ग के मुख्यमंत्री होने के नाते आदिवासी वर्ग के हितों की रक्षा करना उनका प्रथम उत्तरदायित्व बनता है। आप लोग उनके पास जाएं और उनको अपनी समस्या बताएं। मुझे पता है कि वह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां आये थे। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले या नहीं मिले। मगर मुझे इतनी जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के किसी अधिकारी ने उनसे कहा कि आप लोग घर जाएं और आपके पैसे वापस हो जाएंगे। इस तरह से उन गरीबों को भेज दिया गया। कोरबा जिला ही नहीं, बल्कि बालोद, गुण्डरदेही जिले सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में उनको इस तरह के 1,500 करोड़ रूपये की ऋण देकर उनके घर बेचवाकर पैसों की उगाही की जा रही है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इससे हमारे गरीब वर्ग के लोग व आदिवासी बहनें बर्बाद हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने

इस संदर्भ में आपको स्थगन प्रस्ताव दिया है, इसे आप स्वीकृत करें। ताकि इस विषय में अनेक सदस्यों के द्वारा पूरी बात आपके समक्ष प्रस्तुत की जा सकें। धन्यवाद।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा शून्यकाल में एक विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- हमारे सुकमा जिले में पोटा केबिन में छिंदगढ़ में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची दो दिनों तक भूखी थी। कल वह प्रार्थना में खड़ी थी और अचानक गिर गई और वही खत्म हो गई। उसकी लाश को ले-देकर हॉस्पिटल ले जाया गया। छिंदगढ़ में उसका ईलाज करना छोड़कर उसको जिला मुख्यालय में ले जाया गया। पुलिस ने तुरंत पोटा केबिन की घेराबंदी कर दी। बस्तर में लगातार आदिवासी बच्चे हॉस्टल में सुरक्षित नहीं हैं। जंगल में तो नक्सलाइड हैं और आदिवासी बच्चे हॉस्टल में सुरक्षित नहीं हैं। जंगल में तो नक्सलाइट है। आज आदिवासी बच्चें हास्टल में सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने शून्यकाल दिया है। वह 4 सौ बच्चों का पोटाकेबिन है। उस पोटाकेबिन के अधीक्षक के ऊपर तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज हो, उनके ऊपर कार्यवाही हो। यही मेरी शून्यकाल की सूचना है। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। उसी हास्टल में 3 बच्चें मर गये। वह अधीक्षक वहां सोती नहीं है। सब्जी नहीं देती है। बच्चें भूखे मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा जिले में मड़वा में स्थापित अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से विद्युत संयंत्र है। दो माह से अधिक समय हो गया है, वहां सैकड़ों भू-विस्थापित परिवार के लोग हड़ताल पर हैं, दो महीना बीत गया है, उनकी कहीं किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है ना उनको कहीं नौकरी देने की बात हो पा रही है। आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। मैं शासन से इस सम्बन्ध में अपनी बात रखूंगा कि आप उनसे वार्तालाप करके जो हितग्राही हैं, जिनकी वहां जमीन निकली है, उनको अतिशीघ्र नौकरी दिलाया जाये।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डी लोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों के द्वारा स्थगन लाया गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के हजारों महिला समूहों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, वह एक दिन का घर खर्च कैसे चलाये, उनको यहां तक समस्या रहती है, उनसे असत्य बोलकर कहीं काम चालू करने के नाम से, किसी को मशरूम का काम करने के लिए, किसी को साबुन बनाने के काम करने के लिए, ऐसा असत्य बोलकर हमारे महिला समूह के द्वारा एक-एक पेपर में 8-8,10-10 बैंकों से लोन दिलवाया गया है। एक एक महिलाओं को किसी को 40 हजार, किसी को 48 हजार को लोन दिलवाया गया है। इस तरह एक एक महिला को 3-3, 4-4 लाख का लोन दिया गया है। उन लोगों के द्वारा एक

बार लोन पटा दिया गया है। लोन नहीं पटा है, कहकर बैंक वाले उनके घरों में तकादा करने आधी रात को भी पहुंच रहे हैं और महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। महिलाओं के घर में कलह हो गया है। पति लोग अपनी पत्नियों को मारने लगे हैं, कई पत्नियां घर छोड़कर भाग गई हैं। कई महिलाएं आत्महत्या करने की राह में हैं। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप इस स्थगन पर चर्चा करायें। धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माइक्रो फायनेंस संस्था द्वारा हमारे जिले, साथ ही आसपास के जिले, धमतरी से भी हजारों की संख्या में महिलाएं ठगी की शिकार हुई हैं। एक-एक समूह के एक-एक महिला से 3-3 लाख, 4-4 लाख रूपये की ठगी हुई है। आज जब मैं सुबह विधान सभा के लिए आ रही थी तो धमतरी विधानसभा से एक महिला फोन की। उसका यह कहना है कि बैंक के 7-8 लोग सुबह से आकर उसके यहां बैठ जाते हैं और रात तक रहते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यह पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। जिनके पास एक डिसमिल भी जगह नहीं है, जो मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहे है, उनके साथ बहुत बड़ी ठगी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक वीडियो वायरल हुआ है। जब प्रताड़ित महिला ने रिपोर्ट लिखाई और हमारे दबाव में रिपोर्ट लिखा गया तो वहां के एस.आई और टी.आई. को धमकी दी जा रही है कि हम सी.एम. के लोग हैं, इसमें कार्यवाही ना किया जाये, ऐसा धमकी मिल रहा है। यह बहुत ही लज्जाजनक घटना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर चर्चा करवायें। धन्यवाद।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो डेटा सामने आया है, उसके अनुसार मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 4 सौ से ज्यादा महिलाओं के साथ यह ठगी हुई है और प्रदेश में करीब 40 हजार से ऊपर का आंकड़ा है। चाम्पा में जो एक महिला एजेंट थी, जब ऊपर से दबाव आया तो उसने आत्महत्या कर ली है। यह मामला बहुत बड़ा होते जा रहा है अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह भयावह है। मैं इस पर आपसे अनुरोध करूंगा, कल एक विधायक जी से बात हो रही थी, इन लोगों को 10 बैंकों से लोन दिलवा दिया गया है। ये बहुत ज्यादा गरीब तबके के लोग हैं। ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सनम्र निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करायें। यह जो माइक्रो फायनेंस कम्पनी का मामला है, यह पूरे प्रदेश में भयावह स्तर का होता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको ग्राह्य कर चर्चा करायें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो माइक्रो फायनेंस कंपनी के ऊपर स्थगन लगाया है, मेरे ही विधान सभा में लगभग ऐसे ही सैकड़ों महिलायें हैं । मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ कि मेरे पास ग्राम कांदुल की लगभग 25 महिलायें हैं

और ग्राम झीका की 12 महिलायें आई थी, जिससे लगभग 50 लाख की ठगी हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम चीचा भिलाई की एक महिला रमौती निषाद बैंक वालों से तंग आकर जहर से आत्महत्या कर चुकी है । यह परिस्थितियां निर्मित है और कुछ महिलायें वसूली के डर से रोजी-रोटी की तलाश में पयायन करके अन्य राज्यों की ओर चली गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिये, जिस हिसाब से माननीय संगीता सिन्हा जी ने कहा है कि विडियो के माध्यम से मेरे पास भी उसके प्रमाण है और जितने एफ.आई.आर. हुये हैं, उसकी कॉपी भी मेरे पास है, अत: स्थगन को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करेंगे ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से विषय आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, हर विधान सभा में महिलाओं के साथ यह हुआ है । अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा ऑकड़ा शुरू में आकलन किया गया था कि 150 करोड़ के आसपास का घोटाला है, लेकिन जिस तरह से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि यह कहीं बड़ा घोटाला है । अध्यक्ष महोदय, महिलाओं ने हर जगह से लोन लिया है और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि माइक्रो फायनेंस कंपनियॉ जिन्होंने लोन दिया है, वह महिलाओं के घर में आकर बैठ जा रहे हैं और लगातार उनके द्वारा हराशमेंट किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा करायें, यही आपसे निवेदन है ।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी यह जो माइक्रो फायनेंस और अन्य कंपनियॉ जो है, उन्हें लोक लुभावने वायदे करके अपने टारगेट को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र की जितनी महिलायें हैं, उनको समूह में बुलाकर बहला-फुसलाकर लोन देते हैं, मानलो एकाध किश्त भी ऊँच-नीच होता है तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे भानुप्रतापपुर का चबेला गांव है, एक महिला जो तबियत खराब होने के कारण एक महीना लोन नहीं पटा पाई थी तो उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी । अध्यक्ष महोदय, एक महिला वहां ऐसी निकली, जिनका गैस सिलेण्डर भी उठाकर ले गये हैं । घोर नक्सली क्षेत्रों में भी कंपनियॉ पहुंच गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूँ कि इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये और स्थगन पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर बैंकिंग कंपनियों के द्वारा गांव-गांव में जाकर गरीब आदिवासी महिलाओं के नाम से लोन निकाला जा रहा है और लोन को उन्हीं के एजेन्ट के द्वारा जमा करा लिया जा रहा है कि आपका पैसा जो है डबल होगा, आपको महीने में पैसा मिलते जायेगा, इस तरह से राशि जमा करा लेने के बाद उनके घर में उन्हीं के कर्मचारी तगादा करने के लिये जा रहे हैं और बहुत सारे चिटफंड कंपनी की तरह ठग कंपनियॉ हैं, इसमें जांच कराई जाये । इस पर एफ.आई.आर. हो, कार्यवाही हो । अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन सदन में लाया गया है, उस पर चर्चा कराने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर मा माइक्रो फायनेंस कंपनी के जाल अइसे बिछे हवै जेखर एजेंट मन सीधा-सादा हमर महिला बहिनी मन के पास पहुंचथे अऊ जाल में फंसाय के काम करथे । मोर विधान सभा क्षेत्र से लगे हुये एक विधान सभा बसना हावय । अऊ बसना विधान सभा के गांव पिरदा के मामला हरय, एला बताना चाहथंव । महतारी वंदन के साथ सरकार हा मिक्सी, कूकर अऊ टार्च भी फ्री मा देवथ हावय, ऐसे कइके इण्डसलैंड बैंक के कर्मचारी सुदर्शन साहू ह महिला बहिनी मन के आधार कार्ड मांगिस, अऊ अँगूठा के निशान घलो लेगिस । बाद म महिला मन हा सोर पाईस कि महिला मन के नाम से बैंक मा खाता खोलइस, अऊ खाता खोलके वोमा लोन घलो निकालिस, फेर जाके महिला मन के अंगूठा लेके वो पैसा ला घलो निकाल लिस । एखर शिकायत महिला बहिनी मन हर बसना थाना में करे हे, तभो ले कार्यवाही नइ हो पाय हे । बहुत सारा महिला बहिनी मन से 1 लाख 38 हजार, डेढ़ लाख, 40-40 हजार, 30-30 हजार, अइसे लोन निकाले हे । अऊ ए पैसा ला खा दे हे । मैं पीड़ित महिला बहिनी मन संग न्याय के उम्मीद सरकार संग करथंव ।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने माईक्रो फाईनेंस के संबंध में जो स्थगन प्रस्तुत किया है, पूरे प्रदेश में उसका सबसे ज्यादा असर कहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि बस्तर में हो रहा है । बस्तर में बहुत ही गरीब और अशिक्षित व्यक्ति रहते हैं । वहां पर आये दिन नये-नये कम्पनियों के नाम से नये-नये आफिस खोलकर वहां के भोले-भाले आदिवासियों को फंसाने का काम कर रहे हैं । जब वहां के लोग शिकायत लेकर थाने में जाते हैं तो उसके विरोध में वहां पर कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है । जिस तरीके से कार्यवाही होती है और उनको न्याय मिलना चाहिए, वह न्याय भी नहीं मिलता है । मेरे बीजापुर जिला के साथ-साथ पूरे बस्तर में लोग इससे पीड़ित हैं । सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराएं ।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चिटफंड एवं माईक्रो फाईनेंस कम्पनी के द्वारा महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगारों के साथ ठगी किया जा रहा है, इस संबंध में हमने स्थगन प्रस्ताव लाया है । सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भी करीब 2 हजार निवेशकों के साथ ठगी हुई है और धमतरी जिले में गरीब महिलाओं को 50 लाख रूपए का लोन लेकर उनके साथ ठगी की गयी है इसलिए काम रोककर इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए ।

श्री ओंकार साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में शासन के द्वारा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है और आज माईक्रो फाईनेंस के जरिए एक कम्पनी के द्वारा हमारे भोले-भाले आदिवासी महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है । एक-एक महिला के खाते से एक-एक बैंक से 30 हजार रूपए का लोन लिया गया है और उनको मात्र 2600 रूपया महीने दिया गया है। ठगने का काम लगभग सभी जिलों में हुआ है । पड़ोसी जिला बालोद में और हमारे

धमतरी जिला में भी बहुत सारी महिलाओं को ठगा गया है । अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस स्थगन को स्वीकार कर चर्चा कराएं ।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के साथ करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी तथा माईक्रो फाईनेंस कम्पनियों द्वारा वित्तीय मनमानी से संबंधित डॉ. चरण दास महंत एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचार सुने । इसी विषय से संबंधित माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण की सूचनाएं मुझे पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, जिसे मैंने ग्राहय कर लिया है । आज वित्तीय वर्ष का भी कार्य होना है, जिसमें समस्त सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा । विचार के उपरांत मैंने प्रस्तुत स्थगन को अग्राहय कर दिया है ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- अग्राहय के बाद क्या बात है ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष जी, मैं आपसे केवल यही निवेदन कर रहा हूं क्योंकि सभी लोगों ने इसमें स्थगन दिया है, ध्यानाकर्षण केवल दो-तीन सदस्यों ने दिया है । इसमें अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दें, बस यही आपसे निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

समय :
12.18 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 503/एफ 3 (2)/48/सं.का./2020, दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2024-2025 के संदर्भ में प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लूंगा ।

समय :
12:25 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना की राशि जमा नही किया जाना ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य विभाग हेतु 7573 करोड़ 70 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रधान मंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना हेतु 1526 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन उससे प्रदेश के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाईयां, जांच हेतु रीएजेन्ट की खरीदी तक भी विभाग द्वारा नहीं की गई। यहां तक कि देश एवं प्रदेश की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी आयुष्मान योजना का दावा भुगतान प्रदेश के निजी अस्पतालों को नहीं करने के कारण अस्पताल प्रबंधनों द्वारा गरीब मरीजों का उपचार करना बंद कर दिया गया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को 1500 करोड़ का भुगतान लंबित होने से छोटे अस्पताल अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान तक नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में आम जनता इलाज हेतु दर-दर भटकने को मजबूर है। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से खर्च करने की जो योजना बनाई गई है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जबकि

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

आयुष्मान योजना के तहत केन्द्रांश की राशि भी प्राप्त होती है, उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार की देनदारी बढ़ती जा रही है। गरीबों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आम जनता को मजबूरी में प्रदेश के निजी अस्पतालों में अपना घर-बार, आजीविका के साधनों की बिक्री कर नगद में उपचार कराना पड़ रहा है। इसके कारण प्रदेश की जनता को हो रही कठिनाई से शासन-प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना हेतु कुल रुपए 1800.05 करोड़ (केन्द्रांश रुपए 274.05 करोड़ तथा राज्यांश रुपए 182.7 करोड़ तथा शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रुपए 1343.3 करोड़) का प्रावधान है। आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में प्रदेश के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयां, जांच हेतु रीएजेन्ट की खरीदी का प्रावधान नहीं है।

यह कथन सही नहीं है कि देश एवं प्रदेश की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी आयुष्मान योजना का दावा भुगतान प्रदेश के निजी अस्पतालों को नहीं करने के कारण अस्पताल प्रबंधनों द्वारा गरीब मरीजों का उपचार करना बंद कर दिए हैं, परिणाम स्वरूप आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को 1500 करोड़ का भुगतान एक समय लंबित हो गया था, जिसके कारण छोटे अस्पताल अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान तक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि देश एवं प्रदेश की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी आयुष्मान योजना शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के दावों का भुगतान प्रदेश के समस्त पंजीकृत शासकीय एवं निजी अस्पतालों को निरंतर किया जा रहा है। यह कहना भी सही नहीं है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को 1500 करोड़ का भुगतान लंबित है, अपितु सही यह है कि वर्तमान में निजी अस्पतालों का केवल 838 करोड़ का भुगतान लंबित है। योजनान्तर्गत अस्पतालों द्वारा 01 जनवरी, 2024 से आज दिनांक तक मरीजों के उपचार के लिए 12.46 लाख प्रकरणों के क्लेम किए जा चुके हैं एवं 01 जनवरी, 2024 से आज दिनांक तक कुल 1655 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें शासकीय अस्पतालों को 559 करोड़ एवं निजी चिकित्सालयों को 1096 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अस्पतालों को निरंतर दावा/क्लेम के भुगतान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अत: यह कहना सही नहीं है कि गरीबों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आम जनता को मजबूरी में प्रदेश के निजी अस्पतालों में अपना घर-बार, आजीविका के साधनों की बिक्री कर नगद में उपचार कराना पड़ रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना का सुचारू क्रियान्वयन कर आम जनों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता में शासन-प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रधान मंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना की बात कर रहा हूं, यह सबसे बड़ी आबादी और गरीबों से जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के निजी अस्पतालों का कितना क्लेम आज की स्थिति में लंबित है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निजी और सरकारी, दोनों अस्पतालों के कुल लंबित क्लेम की राशि 1440 करोड़ रूपए हैं (शेम-शेम की आवाज) । जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है कि निजी अस्पतालों का कुल 838 करोड़ रूपए लंबित है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा दूसरा प्रश्न है। आप एक तरफ ऊपर अपने जवाब में यह कह रहे हैं कि आपका कोई लंबित भुगतान नहीं है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि निजी अस्पतालों का 838 करोड़ रूपए का भुगतान लंबित है। मंत्री जी, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत मूल बजट में कितनी राशि का प्रावधान था, प्रथम अनुपूरक में कितनी राशि का प्रावधान था और द्वितीय अनुपूरक में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुनना चाह रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार अस्पतालों का लंबित भुगतान छोड़कर गयी थी तो निजी अस्पतालों की 974 करोड़ रूपए की देनदारी थी (शेम-शेम की आवाज) और अभी 838 करोड़ रूपए है। इसी प्रकार से इनके कार्यकाल में जो भुगतान होते थे, वह आदमी देखकर, पहचान-पहचानकर किया जाता था। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसमें एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि कोई भी किसी का भुगतान नहीं करा सकता। आज FIFO के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। जो पहले आवेदन करेगा, उसको पहले भुगतान होगा (मेजों की थपथपाहट) । इसमें हमने जीरो करप्शन किया है। इसी प्रकार से हमारे भुगतान की जो स्थिति है, उसके लिए हम प्रतिमाह भुगतान कर रहे हैं। हम कल से भी भुगतान शुरू करेंगे और आने वाले वित्तीय वर्ष में इनका जो फिगर था, उससे हमारा फिगर बहुत कम होगा। हम इनकी ही देनदारी का अभी तक भुगतान कर रहे हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि मूल बजट में एवं प्रथम अनुपूरक में कितनी राशि का प्रावधान था और द्वितीय अनुपूरक में आपने कितनी राशि रखी है ? आप इसका उत्तर दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में ही कहा है कि 1800 करोड़, 5 लाख का रूपए का प्रावधान था, जिसमें 274 करोड़, 5 लाख रूपये केंद्रांश और 182 करोड़, 70 लाख रूपए राज्यांश है। प्रदेश की लगभग आधी आबादी, जो 2011 की एस.ई.सी.सी. सूची में शामिल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं है, ऐसे लोगों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत 1343 करोड़, 30 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

समय :

12.27 बजे **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेंडी) पीठासीन हुए)**

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दिसंबर, 2024 की स्थिति में कितनी राशि का भुगतान किया गया है और क्लेम भुगतान की कितनी राशि लंबित है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, दिसंबर, 2024 की स्थिति में निजी अस्पतालों को 1096 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है और शासकीय अस्पतालों को 560 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इनको कुल 1655 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना के दावा क्लेम का परीक्षण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है ? क्या किसी अस्पताल ने गलत क्लेम का दावा प्रस्तुत किया है ? कितने अस्पतालों के विरूद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गयी है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्लेम आते हैं, उनके लिए टी.पी.ए. (थर्ड पार्टी एजेंसी) के माध्यम से क्लेम राशि का परीक्षण कराया जाता है और उस आधार पर भुगतान किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि करप्शन को जीरो करने के लिए, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने के लिए हॉस्पिटल के संदर्भ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बातें आ रही थी, उसके तहत हमारी सरकार ने पिछले समय में 75 अस्पतालों की जांच की है, जिसमें हमने 11 अस्पतालों में फाइन लगाया है, 9 अस्पतालों को डी.ई. इम्पैनलमेंट किया है और 1 अस्पताल को सस्पेंड किया है और हमने कुल 151 लाख 80 हजार रूपए का फाइन भी किया है। माननीय सदस्य, यदि आप कांग्रेस के कार्यकाल के पिछले एक साल की जानकारी जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताता हूं। आपकी सरकार ने कुल 14 जांच की थी, जिसमें 1 को सस्पेंड किया गया था और 6 को फाइन किया गया था और आपने केवल 29 लाख रूपये वसूला था और हमने 151 लाख 80 हजार रूपए का फाइन किया है। यह आंकड़ा बताता है कि माननीय विष्णु देव साय जी की सुशासन की सरकार हर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, एक तरफ माननीय मंत्री जी खुद अपने जवाब में बता रहे हैं कि निजी अस्पतालों का केवल 838 करोड़ रूपये का भुगतान लंबित है और आज जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के निजी अस्पतालों में ईलाज नहीं हो रहा है, गरीब वर्ग परेशान हैं। आप कहीं पर भी चलकर देख लीजिए। सभी लोगों से यह पूछ लीजिए। आज पूरे प्रदेश के निजी अस्पतालों में ईलाज नहीं

हो रहा है। शासन से जो अनुबंध किये हुए अस्पताल हैं, वह भुगतान नहीं मिलने का बहाना बनाकर, वह लोग मरीजों का ईलाज नहीं कर रहे हैं । इस स्थिति में क्या उनके ऊपर कार्यवाही होगी ? जैसे जो अस्पताल ईलाज नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी ? आप एक तरफ यह कहते हैं कि निजी अस्पतालों का केवल 838 करोड़ रूपये का भुगतान लंबित नहीं है। आप अपने जवाब में भी बता रहे हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों का केवल 838 करोड़ रूपये का भुगतान लंबित है। यह दोनों स्थितियां कैसे हो सकती हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि निजी अस्पतालों का केवल 838 करोड़ रूपये का भुगतान लंबित है। एक ओर तो आप बोल रहे हैं कि वहां पर ईलाज नहीं हो रहा है दूसरी ओर आप बोल रहे हैं कि

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, निजी अस्पतालों का 838 करोड़ रूपये का भुगतान लंबित है। इस वजह से उनका ईलाज नहीं हो रहा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनिये। आप बैठिए, मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के पूरे अस्पतालों में ईलाज नहीं हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग लगातार यहां पर भी आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले निजी अस्पतालों में ईलाज होता था, वह ईलाज नहीं हो रहा है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय एक ओर बोल रहे हैं कि वहां पर मरीजों का ईलाज नहीं हो रहा है और दूसरी ओर बोल रहे हैं कि निजी अस्पतालों का भुगतान नहीं हो रहा है, निजी अस्पतालों का भुगतान बढ़ता जा रहा है। अगर वहां पर मरीजों का ईलाज नहीं रहा है तो निजी अस्पतालों का भुगतान कैसे बढ़ेगा ? वह यह दिखा रहा है कि वहां पर मरीजों का ईलाज हो रहा है और मैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने एक सालों में 27 लाख 98 हजार नये आयुष्मान कार्ड बनाये हैं जो गरीबों के लिए एक बड़ा वरदान होगा।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी वहां पर मरीजों का ईलाज नहीं हो रहा है। मैं रायपुर के निजी अस्पतालों की स्थिति बता रहा हूँ। वहां पर ईलाज नहीं हो रहा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपको तभी बता रहा हूँ। अभी तक किसी सरकार ने एक साल में 28 लाख कार्ड नहीं बनाया। किसी भी सरकार ने एक साल में इतने कार्ड नहीं बनायें। पूर्व में आपकी भी सरकार थी आपने उसका आधा, 14 लाख कार्ड भी बनाये होंगे तो आप बता दीजिए। लेकिन हम हमारी सरकार ने एक सालों में 28 लाख आयुष्मान कार्ड बनाये हैं। इसके साथ ही जो हॉस्पिटल हैं। हमने 104 नये हॉस्पिटल को इम्पैनलमेंट किये हैं और पिछले समय में जो इनका 974 करोड़ रूपये का क्लेम था, आपकी सरकार का एक साल का था । यह क्लेम 1440 करोड़ रूपये है जो लगभग डेढ़ गुना

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

है जो यह बताता है कि माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने उन गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों का डेढ़ गुना ज्यादा ईलाज किया है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, अगर कोई निजी अस्पताल कोई बहाना मारकर, किसी भुगतान का बहाना मारकर, किसी मरीज का ईलाज नहीं करता है तो उसके खिलाफ शासकीय कार्यवाही किये जाने का क्या प्रावधान है ? मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, उसके लिए टोल फ्री नंबर 104 है यदि उसमें किसी व्यक्ति को कोई भी हॉस्पिटल हो, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने इम्पैनल्ड है अगर वह ईलाज नहीं करता है तो उसमें प्रावधान है। हम उसको डिइम्पैनल्ड कर सकते हैं। चूंकि यह ऐच्छिक है। हम किसी भी हॉस्पिटल को यह बाध्य नहीं कर सकते कि वह हमारे सरकार की योजना को जबरदस्ती फॉलो करे, लेकिन यदि वह रजिस्टर्ड है और किसी मरीज का ईलाज नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ, हमारे यहां जो भी प्रावधान हैं। हम पहले तो उसको डिइम्पैनलमेंट कर देंगे। हमारे यहां से उसकी संबंद्धता खत्म करके,उसको आयुष्मान योजना का कोई लाभ नहीं देंगे। अगर कोई ऐसे प्रकरण है तो आप मुझे बताईये। हम बिल्कुल उसे दिखवायेंगे। इसके लिए हमारी सरकार गंभीर है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ और गरीबों वर्ग का है। निजी अस्पतालों का तत्काल लंबित भुगतान हो और पूरे प्रदेश के निजी अस्पतालों, जहां-जहां से अनुबंध हुआ है उन निजी अस्पताओं में ईलाज सुचारू रूप से संचालन हो, आप इसकी व्यवस्था करें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं । इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है इसमें सतत् रूप से ईलाज चलते रहना चाहिए और आप लोगों को भी धन्यवाद् देता हूँ कि आप कम से कम आयुष्मान योजना के बारे में चिंता भी कर रहे हैं और सबको चिंता करनी चाहिए। मेरा सबसे आग्रह भी है। जो वर्तमान में निजी अस्पतालों का केवल 838 करोड़ रूपये का भुगतान लंबित है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि परसों ही इन्होंने 300 करोड़ रूपये और जारी किये हैं। हमारे प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लगातार भुगतान कर रहे हैं। आप इस प्रदेश में कहीं कोई किसी के बारे में स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो आप मुझे उसे बताईये, हम उसको दिखवायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य को आंसदी से पर्याप्त संरक्षण मिला और माननीय विक्रम मंडावी जी ने प्रदेश के मरीजों, गरीब लोगों के लिए जो आवाज उठायी और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को 1400 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं हुआ है। यह एक दिन में तो होगा नहीं। वहां पर छोटे से लेकर बड़ी बीमारी का ईलाज होना है। इसमें जो आपके छोटे-छोटे हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट हुए

हैं। अब उसकी स्थिति यह है कि उनको भुगतान नहीं होने के कारण से बंद हो गये हैं। जो गरीब लोग हैं, वह आयुष्मान कार्ड लेकर जाते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं तो आपने अभी ओ.पी. चौधरी जी को धन्यवाद् दिया, उनको हम लोग भी धन्यवाद देंगे। जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को 1400 करोड़ के भुगतान लंबित है उसे कब तक पूरा कर लेंगे ? क्योंकि यह कब से लंबित है ? आपने बता दिया कि पिछले कार्यकाल का भी है और इस कार्यकाल का भी है। दोनों मिलाकर 1400 करोड़ रुपये है और आपने 300 करोड़ रुपये दिया है तो यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। वहां तो उनके अपने स्टॉफ, नर्स, डॉक्टर हैं, वह उनका पेमेंट भी नहीं कर पायेगा। मेरे पास हॉस्पिटल के लोग आये थे, वह बोले कि हम कई महीने से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आपके सरगुजा के लोग आये थे कि हमारा भुगतान नहीं हुआ है, हम पेमेंट कैसे करेंगे? इसमें राजनीति करने की बात नहीं है। इसमें यह है कि यह जो जितने छोटे-छोटे हॉस्पिटल हैं, यदि उनका भुगतान त्वरित रूप से कर देंगे। छोटे अस्पताल निश्चित रूप से दुरस्थ अंचलों मे हैं, वहीं गरीब, आदिवासी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। आप कम से कम यह सुनिश्चित करें कि इनका भुगतान जल्दी हो जाये और इसको कब तक पूरा लेंगे? यदि पूरा भुगतान हो जायेगा तो इलाज भी सब लोगों को मिलेगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य भूपेश बघेल जी बहुत वरिष्ठ भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और साथ में 5 साल वित्त मंत्री रहे हैं। वह भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार को चलाने के लिए सभी क्षेत्रों में बराबर समेकित रूप से करना पड़ता है। यह कोई राजनीति वाली बात नहीं है। आप जितना छोड़ कर गये थे, कम से कम इस बात का संतोष है कि उससे हमारी देनदारी कम है और अभी 300 करोड़ रुपये को घटा देंगे तो और कम हो जायेगा। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर हेल्थ के लिए आज तक जब भी किसी भी राशि के लिए चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, इसके लिए हो, इन्होंने कभी मना नहीं किया है। मैं जानता हूं कि जो सरगुजा, बस्तर में छोटे-छोटे हॉस्पिटल हैं, उसी पर ही उनका हॉस्पिटल चल रहा है। उसकी चिंता है। वह 300 करोड़ रुपये तो दे ही रहे हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि और जितनी भी आवश्यकता हो, उसको पूरा करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उनका भुगतान जल्द से जल्द होकर, जो आप लोगों का भी पिछली बचा हुआ है, ये भी बचा है, सबका भुगतान करके हम बराबर करने का प्रयास करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- हमने कर दिया है, वह बचा है, हमारी देनदारी है, ऐसी बात नहीं है, वह on going process है, वह चलता रहेगा। आज आप सरकार में हैं, कल जो सरकार में आयेगा, वह भुगतान करेगा। वह तो करना ही पड़ेगा। यह तो on going process है। इसमें आपने छोड़ दिया, इसने, उसने छोड़ा यह कहना गलत है। इलाज कराये हैं तो उसको देना पड़ेगा न, वह तो on going process है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, उसको जल्द करेंगे। माननीय बघेल जी आप लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटलों को हमने जिस प्रकार से दुरूस्त किया है, आप एकात दिन मेकाहारा जाकर देखिये। आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी गये थे। उन्होंने वहां से आकर तारीफ की है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- इसमें पर्याप्त चर्चा हो गई है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हॉस्पिटल जाने की बात बोला तो मैं अपने क्षेत्र में भी गया था। पहले 110 प्रकार की जांच फ्री में होती थी, अब बंद हो गई है। दवाईयां मिलती थीं, अब वह बंद हो गई हैं। हॉटबाजार क्लिनिक योजना बंद हो गई है। स्वास्थ्य की स्थिति ये है आपके कार्यकाल में मलेरिया से, उल्टी-दस्त से कितनी मौतें हुई हैं, आपके स्वास्थ्य विभाग का यही थर्मामीटर है। मलेरिया और डायरिया से मौतें हो रही हैं और अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिये, एकात दिन उस पर भी ऐसी चर्चा ले आईये। मैं तो खुले रूप से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। पिछली सरकार में कितनी मौतें हुई थीं, क्या व्यवस्था थी, एकदम तैयार हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- आप अभी तक पूर्व सरकार की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार की बात करिये।

सभापति महोदय :- इसमें बहुत चर्चा हो गई, बहुत बात आ गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि मेकाहारा जाकर देखिये, हॉस्पिटल सर्वसुविधायुक्त मिलेगा। अभी दो दिन पहले पेपर में डी.के. हॉस्पिटल का आया था कि मरीज के परिजन सीढ़ी में सो रहे हैं। यह स्थिति है।

समय
12.38 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संजारी-बालोद विधान सभा की बात करना चाहूंगी कि एक ही जो सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस था, अधिकारियों का कहना है कि मंत्री महोदय जी के कहने से हम वह सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस धमतरी में दे दिये। वहां इसी कमी के कारण एक व्यक्ति की स्पॉट में मौत हो चुकी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वहां पर तुरंत के तुरंत सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस दीजिए। वह हमारे जिले में बहुत जरूरी है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- चलिये, आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। अनुज शर्मा जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़िये।

(2) विधान सभा क्षेत्र धरसींवा में अवैध प्लॉटिंग की जाना ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है- विधान सभा क्षेत्र धरसींवा में अवैध और अनाधिकृत रूप से हो रहे अवैध प्लाटिंग की अनेकों शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसके संबध में मेरे द्वारा भी स्थानीय प्रशासन को शिकायत की गई थी जिस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होने के कारण अवैध प्लाटिंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं और धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। उक्त अवैध प्लाटिंग बिना ग्राम एवं नगर निवेश विभाग तथा रेरा के अनुमति के हो रहे हैं। जिसके कारण स्थानीयजनों को बिजली/पानी/सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। उक्त अवैध और अनाधिकृत रूप से हो रहे अवैध प्लाटिंग पर कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र धरसींवा में अवैध प्लाटिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । अवैध प्लाटिंग के संबंध में तहसीलदार/पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवैध प्लाटिंगकर्ता के विरुद्ध छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइज़र के रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1999 की धारा-61 “क” से 61 “छ” के तहत् नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है । विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के कुल 13 ग्रामों (1.धनेली, 2.निमोरा, 3.बरौदा, 4.सांकरा, 5.टेकारी, 6.परसुलीडीह, 7.पठारीडीह, 8.कुंरा, 09.माठ, 10.केसला, 11.खरोरा, 12.सिर्री, 13.मोहरेंगा) के अंतर्गत कुल 47 व्यक्तियों/फर्म के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग की शिकायतें प्राप्त हुई है । उक्त शिकायतों के विरुद्ध न्यायालय में 19 प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । स्थल पर अवैध प्लाटिंग कार्य को हतोत्साहित किए जाने हेतु अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा किए गए रोड निर्माण को काटकर आवागमन हेतु मार्ग को अवरुद्ध किया गया है तथा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के समक्ष स्थल पर “अवैध प्लाटिंग का हिस्सा है जिसका प्रकरण लंबित है” सूचना पटल लगाया है । अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । उक्त प्रकरणों का निराकरण शीघ्र ही कर लिया जावेगा । यह कहना सही नहीं है कि अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो शिकायतें इन्हें प्राप्त हुई हैं वह किस अवधि में प्राप्त हुई हैं और यह कार्यवाहियां कब हुई हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो धरसींवा विधान सभा क्षेत्र में जितने अवैध प्लाटिंग की शिकायतें और इनकी शुरुआत जो है वह वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 का है और यह अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए हमारे राजस्व विभाग के एस.डी.एम. और तहसीलदार इनको कारण

बताओ नोटिस जारी करके न्यायालय में इनका प्रकरण विचाराधीन है । नगरीय क्षेत्र में Commissioner देखते हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में S.D.M और तहसीलदार देखते हैं ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 14 फरवरी, 2024 को इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब मुझे प्राप्त हुआ था और उसके जवाब में यह उत्तर आया था कि आवासीय बताकर विक्रय किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई उसके लिए मैंने तीन उदाहरण यहां प्रस्तुत किए थे । मैंने रजिस्टर्ड तीन शिकायतों की कॉपी दिखाई थी । उसके बाद मुझे जवाब में यह कहा गया था कि विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग की 19 शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई हैं । अब इसमें interesting बात यह है कि आज भी मुझे जो जवाब आया है । आज के जवाब में भी यही है कि आज भी वह 19 शिकायतों की ही बात हो रही है, 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि अवैध प्लाटिंग करनेवालों पर, अवैध कॉलोनाइजर्स पर वह कड़ी कार्रवाई करेंगे तो उस आश्वासन के बदले ऐसी कौन सी कार्रवाई की गई और उसकी आज तक मुझे कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं मिली । कृपया उस आश्वासन के बदले की गई कार्रवाई का थोड़ा ब्यौरा प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अवैध प्लाटिंग केवल धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की चिंता नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह प्रदेश की चिंता है और यह अवैध प्लाटिंग होने के बाद वाकई में जनप्रतिनिधियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है । प्लॉट में जो घर बनाकर रहते हैं वह नाली निर्माण और बिजली, सड़क के लिए जनप्रतिनिधियों को ही घेरते हैं और मुझको लगता है कि यह अवैध प्लाटिंग, रजिस्ट्री का काम पंजीयन विभाग करता है और इनका डॉयवर्सन का काम टी.एन.सी. से होता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए एक संयुक्त समिति, जिसमें राजस्व विभाग हो, पंजीयन विभाग हो, ग्राम नगर निवेश विभाग हो, नगरीय प्रशासन और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग इनकी एक टीम गठित कर इस अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्व विभाग अवैध प्लॉटिंग को अकेले नहीं रोक सकता। पंजीयन अलग विभाग है और जो डायवर्सन करने वाला अलग विभाग है और राजस्व विभाग किसी भी जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक नहीं लगा सकता है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है कि विगत 10 महीनों में मेरे सवाल का जो आश्वासन मिला था, उस पर विभाग ने क्या कार्रवाई की? मैंने उसकी डीटेल मांगी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन है, पिछले 10 महीनों में क्या कारवाई हुई? उसकी जानकारी मुझे कृपया मंत्री जी उपलब्ध करा दें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अवैध प्लॉटिंग वाला विषय प्रकरण में लंबित है और इसकी समय-सीमा बताना कठिन है। मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए हम एक संयुक्त टीम का गठन करेंगे और माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी और नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास इनके साथ बैठ कर एक कमेटी गठित कर इनको रोकने के लिए कुछ नया नियम बनाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, नये नियम बना देंगे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट। अब मैं आपको वस्तुस्थिति बताता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- कुछू नहीं होवे महाराज, तुम्हर सरकार में कुछू जांच नहीं होवे। मैं तोला बतावथव।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, हम जिस विधान सभा में बैठे हैं। विधान सभा में गोद लिया हुआ गांव है बरौदा। मैं बरौदा की स्थिति आपको अवगत कराना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, खसरा नंबर 473/1 विधानसभा की आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा है। खसरा नंबर 251/1 शासकीय भूमि में अवैध कब्जा है, मैं बरौदा गांव की स्थिति बता रहा हूं। खसरा नंबर 220/8 चारागाह की भूमि है, उस पर अवैध कब्जा है। 292/1, बाजू में शासकीय स्कूल है, उस पर अवैध कब्जा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी आजकल राजस्व में खूब चर्चा हो रही है। इसको थोड़ा ठीक करिए। राजस्व में आज कल बहुत चर्चा हो रही है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं । ये दोंदे से तर्रा के लिए नहर जाता है। जहां 1400 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी, उस पर इस कदर अवैध कब्जा किया गया है कि नहर को पाट कर उस पर कॉलोनी बना दी गई है। अवैध प्लॉटिंग हुई है, इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। चरौदा में, धरसींवा में, परसुलीडीह में और आप यहां इस रास्ते से आप आगे जाएंगे बरौदा से सिलियारी की ओर तो उसमें लगातार आपको कॉलोनी ऐसी मिलेंगी। मटिया पेट्रोल पंप के सामने दोंदेखुर्द एवं सेमरिया के बीच में धनेली, गिरौद, बाना, गुमा पठारीडीह, सांकरा, निमोरा, सारागांव पेट्रोल पंप के पीछे कुंरा, सोंढरा, सिलतरा, मांडर कॉलोनी के पास इतने मैं सिर्फ विधान सभा के आस-पास के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर कोई कड़ा कदम तो माननीय मंत्री जी को उठाना पड़ेना और जिस तरह से 10 महीनों में उस आश्वासन के बाद और ये देखिये अभी यहां आते वक्त भी मुझे ये दोंदे से तर्रा के बीच में यह शिकायत मिली है। अब मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज पूछता हूं कि कई लोग अवैध प्लॉट को बेच कर निकल जाते हैं। जो लोग बेच कर चले गए, उन पर कार्रवाई करने का विभाग ने क्या तय किया है? ये कृपया मंत्री जी स्पष्ट करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- मोर छइयां भुईयां के हीरो के दशा ला देख कर मोला भारी तरस आथे। तुम्हर फिल्म ला देखे हन तो सम्मानित हव । तुम्हर कहाथो कि जांच नहीं होथे।

श्री अनुज शर्मा :- ते चिंता मत कर। दशा तोर देख कर चिंता होथे। हमर दशा बने चलथे। तुम्हरे ग्रह दशा ठीक नहीं हे।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य की जो चिंता है, सही है और जितने जगह शासकीय भूमि को चिन्हांकित किये हैं, अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग किये है, कब्ज़ा किये है। चाहे बरौदा का हो, परसुलीडीह का हो, जहां का भी है, वे मुझे लिखकर देंगे, मैं तत्काल उसमें एक्शन लूंगा, कार्रवाई करूंगा, जांच कराउंगा और जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, राजेश जी, पूछ लीजिए। हो गया आपका तीन प्रश्न।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय मैं कहना चाहता हूं। ये तो जिन्होंने कब्जा कर लिया, उस पर कार्रवाई की बात है, लेकिन इसको बचाने के लिए विभाग ने क्या तय किया है कि आगे इस तरह की कोई हिम्मत न कर सके कि किसी को भी बेजा कब्जा करने या अवैध प्लॉटिंग करने से उसको डर लगे, इस बात के लिए विभाग ने क्या तैयारी की है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जहां भी शासकीय जमीन है, चाहे चारागाह के लिए आरक्षित हो, चाहे अस्पताल के लिए आरक्षित हो, चाहे खेल मैदान के लिए, चाहे स्कूल मैदान के लिए आरक्षित हो, उसमें यह कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत की सहमति से उस जमीन का क्या उपयोग कर सकते हैं, सार्वजनिक उपयोग, उसकी तख्ती लगाकर उसको आरक्षित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, राजेश जी ।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और । अध्यक्ष महोदय, होता क्या है कि अवैध कालोनी में रोड काट देते हैं । एक शेर है, इक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा और फिर जुड़ गए । फिर वे सड़कें जुड़ जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किस अवधि में यह कार्यवाही करेंगे, थोड़ा समय निर्धारित कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि हम लोग 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं । कुछ अवधि बता दें, कोई समय सीमा बता दें ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास होगा कि हम इसको जल्द से जल्द कराएं । समय सीमा बताना मुश्किल है ।

श्री अनुज शर्मा :- मंत्री जी, हम लोग 10 महीनों से इंतजार कर रहे रहे हैं । कुछ समय बता दीजिए, दो महीने, चार महीने ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए राजेश जी, छोटा प्रश्न कीजिए ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं । यह प्रश्न केवल उनके विधान सभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह पूरे प्रदेश का है । अवैध प्लाटिंग से हर व्यक्ति दुखी है । किसान को लाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, कागज में प्लाटिंग काटते

हैं उसके बाद रजिस्ट्री कराकर चले जाते हैं । आपके कार्यकाल के समय, जब आप मुख्यमंत्री थे, उस समय अमर अग्रवाल जी उस समय वित्त मंत्री थे, आपके रहते हमने छोटी प्लाटिंग पर रोक लगाई थी । पूर्व सरकार के समय जितनी अवैध प्लाटिंग हुई उसका हर्जाना हम लोग भुगत रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट मत है कि यदि इसका स्थायी समाधान चाहते हैं तो पांच डिसमिल से ज्यादा की कोई भी रजिस्ट्री बिना उसके नहीं होना चाहिए । जब तक यह प्रतिबंधित नहीं होगा, यह अवैध धंधा पूरे प्रदेश में चलता रहेगा । चाहे कोई भी हो, ए-टू-जेड, आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं । माननीय, जो प्लॉट ले लेता है उसको लाइट का कनेक्शन नहीं मिलता क्योंकि उसका ले-आऊट प्लान पास नहीं है । उसको कॉमर्शियल रेट लगता है, बाजार का रेट लगता है । उसके यहां रोड नहीं होती है, उसके यहां खंभे नहीं लगते हैं, उसके यहां वाटर सप्लाई नहीं होती है । जब एक जिम्मेदार मंत्री के नाते आप उत्तर दे रहे हैं तो आपके पास तो कई केस हैं, ज़रा पांच कार्रवाई गिना दें जो आपने इस शहर के अंदर की हो, केवल पांच कार्रवाई । यानी इस शहर के अंदर अवैध प्लाटिंग की भर्राशाही इस प्रकार से पनप रही है । मैं आग्रह करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं । वित्त मंत्री जी भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हैं । जो पहले से नियम बना हुआ है, आपको केवल घोषणा करना है कि उस नियम का पालन होगा तो एक दिन में अवैध प्लाटिंग बंद हो जाएगी ।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष जी, कार्रवाई करके नज़ीर प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, गंभीर विषय है और पूरे प्रदेश की समस्या है । मंत्री जी ध्यान देंगे, अब तो यह स्थिति है विधान सभा आवासीय कॉलोनी से लगी हुई शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है । कृपा करके जो आवासीय कॉलोनी विधान सभा की है । एक महीने के अंदर कार्रवाई करके मुझे सूचित करेंगे । इसके बारे में व्यापक रूप से शिकायत प्राप्त हुई है, धन्यवाद् ।

श्री टंक राम वर्मा :- जी अध्यक्ष महोदय ।

श्री अनुज शर्मा :- बहुत-बहुत आभार अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत आभार ।

श्री राजेश मूणत :- लेकिन पूरे प्रदेश की घोषणा कर दो ना साहब, केवल एक ही जगह का क्यों कर रहे हो । इस प्रदेश के अंदर एक नज़ीर बन जाएगी । यहां वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है । यह पूरे प्रदेश की समस्या है और इसके लिए एक निर्णय करेंगे तो एक नज़ीर बनेगी कि पूरे प्रदेश के अंदर यह सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार है, सांय-सांय निर्णय करती है, अवैध काम करने वालों को अंदर डालती है ।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अवैध प्लाटिंग के संबंध में कह चुका हूं कि संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर, राजस्व विभाग, नगर निवेश, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन ।

श्री राजेश मूणत :- टीम बनी हुई है । केवल वित्त मंत्री जी और आप लोगों की सहमति चाहिए । छोटी रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं, केवल इतने से ही मामला खत्म हो जाएगा ।

श्री टंक राम वर्मा :- हम इसे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे और इसके लिए नियम बनाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, राजेश जी ने एक बात कही है । माननीय वित्त मंत्री जी या रजिस्ट्री मंत्री जी मेरे पास बैठे हुए थे तो मैं उनसे भी आग्रह कर रहा था कि अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री बंद हो जाएगी तो एक सेकेंड में यह प्रतिबंधित हो जाएगा । यह केवल राजस्व का विषय नहीं है । संयोग से माननीय मंत्री ओ.पी.चौधरी जी भी उपस्थित हैं । यदि वे घोषणा कर देते हैं अवैध प्लॉटिंग या जो भी रेरा से अनुमोदित नहीं है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी तो एक मिनट में प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग रूक जाएगी । यह विकृत शहरीकरण एक बड़ी समस्या है। जो एक नंबर में काम कर रहे हैं, वह बेचारे दुखी हैं, दो नंबर वाले सुखी हैं। किसी भी रेट में कहीं पर भी रजिस्ट्री हो जा रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, वह जो अवैध कॉलोनी बनाते हैं, नाम बहुत ऊंचा-ऊंचा रखते हैं। ग्लोबल, मार्बल, यह ग्लोबल, मार्बल के चक्कर में वहां नाली बज-बजा रहा है, इसको रूकवाईए।

(वित्त मंत्री (श्री ओ पी. चौधरी) के खड़े होने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- वे कुछ बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, ए बड़े के गोठ ला सुने हो ना, मोरो गोठ ला सुन लेव। गरीबों के गोठ ला सुन लेव।

श्री अजय चंद्राकर :- ओला सुन ले मोर बाप। ओमे नोट नई मिले।

श्री रामकुमार यादव :- मोर बात ला तो सुन लेव मोर बाप। नोट नहीं, मोर गोठ ला सुन तैं। अध्यक्ष जी, अब मान लो कोई व्यक्ति हा रायपुर में बड़का अवैध कॉलोनी बनात हे, ते कोई गरीब तो नो ए, न ओ चंद्राकर कर जा के चाय पियत हे ना रामकुमार कर जा के रोज चाय पियत हे।

श्री अनुज शर्मा :- ओ सब न पिछले पांच साल के तुंहरे खेल ए।

श्री रामकुमार यादव :- महराज, (व्यवधान) मैं कहना चाहत हौं कि जतका बड़े आदमी हे, जतका करते हे ते मन।

श्री अनुज शर्मा :- वित्त मंत्री जी बोलत हे बोलन दे।

श्री अजय चंद्राकर :- ओला बोलन देना, ताहन बोल लेबे।

श्री रामकुमार यादव :- ए गांव के बात ए, ए गांव के। हमर अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री रिहिस हे तब जानत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रश्न पूछिए ना।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, जब महानदी में बैराज बने रिहिस हे तब ओ महानदी ...।

श्री प्रबोध मिंज :- रामकुमार जी, पूरा प्रदेश ला घोषणा करने वाला हे, सब के समाधान हो जही।

श्री रामकुमार यादव :- बईठ न मूंछ वाले भैया। त दुर्ग भिलाई के मन जा के जमीन ले रिहिस हे, ओ समय शिकायत करे रेहेन त आप निरस्त करे रहा। ओ समय जांजगीर के कलेक्टर साहब रिहिस हे। लेकिन अभी तक ओखर कुछु नई हो पाईस। अउ ओ समय हमर सरकार रिहिस त जमीन के मुआवजा ला रोके रेहेन, अभी आपके सरकार आए के बाद में महानदी के जमीन के मुआवजा ला दुर्ग भिलाई के मन पावत हे, ओखरो लिए तुहरे हाथ में निरस्त होए रिहिस हे। मै ए कहना चाहत हौं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो महानदी का विषय उठाया है। उसमें जो रजिस्ट्रियां तुकड़े-तुकड़े में करके की गयी थी, मैं उस समय वहां पर कलेक्टर के पद पर था। उसको मैंने बहुत बड़े पैमाने पर निरस्त कराने का काम किया था और यह मुद्दा लेकर यह भी आते थे। इनको एड्रेस करते हुए मैंने किया था। बाद में कोर्ट के केस हुआ, जैसे हुआ, मैं अभी उसका फॉलोअप अभी फिरहाल नहीं जान रहा हूं। उससे अलग हटकर आदरणीय सदस्य राजेश मूणत जी, आदरणीय सम्माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी की ओर से जो अवैध कॉलोनी को ले करके रजिस्ट्री पर प्रतिबंध का विषय आया है। मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि पहले लैंड रेवेन्यू कोर्ट में प्रावधान था कि पांच डिसमिल से छोटी जो रजिस्ट्रियां होती थी, कृषि भूमि को छोड़कर, उसमें नामांतरण नहीं होने का प्रावधान था। लेकिन पिछली सरकार ने सरकार में आते ही इस प्रावधान को समाप्त कर दिया था जिसके कारण अवैध कॉलोनी की स्टार्टअप का सेप लिया। यह भी सच्चाई है। जहां तक रजिस्ट्री पर प्रतिबंध की बात है, जो प्लान एरिया है और जो अर्बन एरिया है, उस पर जो अवैध कॉलोनी है या रेरा से अनुमति नहीं है या टाउन कंट्री प्लानिंग से जो भी प्रोसेस है, उसको कंप्लीट नहीं किया गया है, उस पर रजिस्ट्री प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाने की कार्रवाई हम शीघ्रातिशीघ्र विद ईन जितने महीने में हो जाए, उसके लिए हमको केबिनेट में निर्णय लेना होगा तो विद ईन मंथ कर लेंगे, उसके लिए अगर विधान सभा आना होगा तो कुछ महीने लग जाएंगे, जो भी प्रावधान उसके तहत् किया जा सकता है, जो अर्बन एरिया है और प्लान एरिया है, उस पर रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने का नियम बनाकर प्रावधान करने का काम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इस पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग बेचकर निकल गये हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो, मंत्री जी उसका भी कृपया ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, तुंहरे नियम बनाए हे, तेमा कहना चाहत हौं। अध्यक्ष जी....।

अध्यक्ष महोदय :- बस हो गया। नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय

12:59 बजे **नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्री गुरू खुशवंत साहेब
3. श्री ललित चंद्राकर
4. श्री भोलाराम साहू
5. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी

श्री रामकुमार यादव :- नहीं-नहीं, ए गरीब के बात ला अभी छोड़े हो। आप बोले हव कि मैं तुकड़ा जमीन निरस्त करे हौं। अगर मान लो बाहर मुआवजा पाईस ओखर लिए का करत हौ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रतिवेदन की प्रस्तुती। अजय चंद्राकर जी।

समय :

1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- प्रतिवेदनों की प्रस्तुति। अजय चंद्राकर जी।

श्री रामकुमार यादव :- आप निरस्त करे रहे हव ता मान लो अगर बाहर के मुआवजा पाइस ता आप ओखर लिए का करत हो?

श्री अजय चंद्राकर :- कार्यवाही आगे बढ़ गई है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ए गरीब के बात ला काबर नहीं सुनत हो? ओ गरीब के जमीन ला जब बाहर के लेके निरस्त करे रीहिस हे। अभी कहात हो कि ओमन मुआवजा पा गेहे, ओला मैं नहीं जानत हो तो आप ला उहु ला जानेन लागही। आप बताओ कि ओला मुआवजा ला पिरोए हो का?

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। आप बैठ जाइये। चंद्राकर जी, आप बोलिये।

समय :

1.01 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

(1) प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अजय चंद्राकर (सभापति, प्राक्कलन समिति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके कार्यकाल में प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है। जब हमर सरकार हा मुआवजा ला रोके रीहिस हे ता तुमन ओला काबर दे हो? बाहर के व्यक्ति ला मुआवजा मिले रीहिस हे। ए गरीब के बात है। आपके बड़े आदमी के लिए सोच है का?

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, आप जो बोलेंगे, वह रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अमर अग्रवाल जी।

समय :
1.02 बजे **(2) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठम्, सप्तम्, अष्टम्, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन**

श्री अमर अग्रवाल (सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी सिमति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठम्, सप्तम्, अष्टम्, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :
1.03 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में शामिल उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

1. श्रीमती भावना बोहरा
2. श्री कुंवर सिंह निषाद

समय :
1.04 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

अध्यक्ष महोदय :- मैंने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024)

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024)

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)

(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024)

(5) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(6) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)

को सत्र की अल्प अवधि एवं विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो नगर-निगम संशोधन विधेयक आया है, उसमें आप देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अभी इसपर चर्चा होगी तो चर्चा में आप बालेंगे ही।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रस्तुत करने के पहले की बात कर रहा हूं। जिसे आपने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि विधेयकों के प्रकाशन तथा पुर:स्थापन में अध्याय-10, 60, 02 में ऐसे विधेयकों जो संविधान के अधीन हों, उनको पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। इनको संविधान के विपरीत इसलिए पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो संशोधन आया है, यदि इसमें देखेंगे तो इसकी धारा-20 में इन्होंने कहा है। नियम यह है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में duration of municipalities में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहली बैठक से लेकर पांच साल के भीतर तक ही उसका कार्यकाल रहेगा। यदि किसी कारण से वह उसके पहले भंग हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है। लेकिन यहां स्थिति यह है कि उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि पांच साल पूरा होने के बाद आप 6 महीने बढ़ा सकते हैं। यह संविधान के विपरीत होगा। आप ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति न दें। वह वापस लेकर ही प्रस्तुत किया जाए तो बेहतर होगा। यह विधान सभा है और यदि यहां अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे तो यह गलत परंपरा होगी। क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन हुआ है और उसे पूर्णत: लागू किया गया है। आप देखेंगे कि चाहे पंजाब के मामले में हो, चाहे मध्य प्रदेश के मामले में हो। यदि इस प्रकार के मामले सुप्रीम कोर्ट में गये तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इसमें आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी और राज्य सरकारों को बाध्य होना पड़ा। मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक आया है, इसको आप अनुमति न दें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, क्या आप इस विषय में शासन का कुछ पक्ष कहना चाहेंगे ?

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, आपको नियमावली में पूरा अधिकार है। माननीय सदस्य को जो भी आपत्ति करनी है, विधयक पर चर्चा के दौरान कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। केदार कश्यप जी।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा है, क्योंकि आप सदन के प्रमुख हैं। मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे विधेयक जो संविधान के विपरीत हों, कम से कम वह प्रस्तुत न हों। संशोधन करना होगा तो मैं उनसे चर्चा कर लूंगा। लेकिन मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे विधेयक प्रस्तुत न हों और ऐसी परंपरा न बने, जो भारत के संविधान के विपरीत हों।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। केदार कश्यप जी।

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, क्योंकि यह विधेयक प्रस्तुत होने ही वाला है। पहले आपकी व्यवस्था आ जाये उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने कहा कि जब सारे विषयों पर चर्चा होगी, उस समय आपत्ति आ जायेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024)

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) के पुर:स्थापन करता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन विभाग) (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन विभाग) (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024)

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन विभाग) (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी इसी में आपत्ति है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। आप तो वकील है, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान का जो 73वां, 74वां संशोधन है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी नगरीय निकाय चुनाव के बाद प्रथम बैठक होगी, उससे 5 साल से अधिक बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको 5 साल से पहले चुनाव कराना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी कारण से कोई नगर पालिका या नगर निगम भंग हो जाता है तो आपको छः महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। लेकिन आप जो संशोधन ला रहे हैं, उसके संशोधन 20 में यह है कि पांच साल पूरे होने के बाद 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाये। ऐसा पंजाब सरकार ने भी किया था, मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा भी किया गया था। दोनों में सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली और कहा गया कि आप दो सप्ताह के भीतर चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। जब हमारे पास उदाहरण हैं तो आप ऐसा संशोधन क्यों ला रहे हैं ? आप इसको वापस लें। बाकी सब चीज तो ठीक है, आप अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट करना चाहते हैं, जो भी और संशोधन है, वह करते रहिये। लेकिन यह संविधान के विपरीत है। जो मूल संविधान की भावना है। इसके बाद दो राज्यों ने ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना और वही काम आप फिर इस सदन के माध्यम से करवाना चाहते हैं, जो आज तक नहीं हुआ है। इसलिए कृपा करके आपसे यही अनुरोध है। इसमें संख्याबल की बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम संविधान के विपरीत जाकर क्यों काम करें, आप इस पवित्र सदन से क्यों पारित करवाना चाहते हैं, जो नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको हटा लीजिये, बाकी विधेयकों को प्रस्तुत कर लीजिये और उस पर चर्चा कर लें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। आप तो पढ़े-लिखे वकील हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। कम से कम संविधान के विपरीत तो ना जाये। यह हमारे इस सदन से पास हुआ है, हम लोग इस आक्षेप से तो बच जायें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि नगर पालिक निगम संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई।

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मामला उठाया था, मंत्री जी कम से कम उसका जवाब तो दे देते । सदन से जवाब तो आना चाहिये । मैंने संवैधानिक बात की है, इसका उत्तर आ जाता ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, सामान्यतौर पर ऐसा नहीं है कि हम कार्यकाल या कार्यावधि को बढ़ा रहे हैं । यदि विशेष परिस्थिति में चुनाव नहीं हो पाये तो उन परिस्थितियों के लिये यह प्रावधान है, उन परिस्थितियों में सरकार के पास क्या आप्शन होगा, इसकी व्यवस्था हो रही है । संविधान के किसी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा है । विधेयक पर चर्चा के दौरान और चर्चा कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चर्चा आ गई । श्री ओ.पी.चौधरी ।

(5) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

(6) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन 2024) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

समय
1.14 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास अनियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन 2024) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया है ।

मैं समझता हूँ सदन सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

समय
1.15 बजे

वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है, अत: मैं, माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि -

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 41, 44, 53, 55, 56, 64, 65, 67, 68, 71, 80, 81, 82 एवं 83 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ सौ पांच करोड़, इकहत्तर लाख, चौहत्तर हजार, दो सौ छियासी रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री उमेश पटेल ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस सरकार को लगभग एक साल हो गये हैं । इस एक साल में कुछ ऐसी घटनायें हुई है, जो छत्तीसगढ़ में शायद पहले कभी नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुई है । आप लोगों ने इतिहास रचा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब हमने नारा दिया था कि छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी-नरवा, गरूवा, घुरूआ और बारी । तब हमारे साथी उसको और नारों की तरह मॉक करते थे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है, इस एक साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी चार चिन्हारी बना ली है । विष्णु सरकार की चार चिन्हारी, जिसमें से पहली चिन्हारी-बलौदाबाजार, दूसरी चिन्हारी-बलरामपुर, तीसरी चिन्हारी-सूरजपुर और चौथी चिन्हारी-कवर्धा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं सुना था कि छत्तीसगढ़ में एस.पी. और कलेक्टर के आफिस को जला दिया गया । यह पहली बार इस सरकार के शासन में हुआ है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह तो सुना था कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में एक ऐसी घटना हुई कि लोग पूरा कपड़ा निकालकर मंत्री की गाड़ी के सामने दौड़ रहे हैं । इसी चिन्हारी से उसकी उपज हुई और यही से अपनी बात शुरू करिए ।

श्री रिकेश सेन :- आपने जो घटना कही है, उसमें आप अपराधियों का भी नाम लीजिए कि कौन आरोपी है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.पी. और कलेक्टर आफिस को जला देना एक संदेश है कि शासन के ऊपर लोगों का विश्वास खतम हो गया है । मैंने बलरामपुर की घटना वीडियो में देखा और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने देखा होगा कि एक एडिशनल एस.पी. को महिलाएं चप्पल से मार रही हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं और वह जूझ रही है । छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी, यह पहली बार हुआ है कि लोग किसी एडिशनल एस.पी. रैंक के अधिकारी को मार रहे हैं । हमने सूरजपुर का वीडियो देखा । एक एस.डी.एम. भाग रहा है और लोग उसको मारने के लिए दौड़ा रहे हैं । इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं हुई । अध्यक्ष जी, मैं कवर्धा के बारे में क्या कहूं ? कवर्धा का हाल तो बेहाल है । वहां कितनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं । एक आदमी को जिंदा जला दिया गया । छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया । यह इस सरकार की एक साल की उपलब्धि है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश बाबू, मैं एक बात बता रहा हूं । आपने कहा कि कवर्धा का हाल-बेहाल है । हम और कौशिक जी गए थे । बलदाऊ कौशिक नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी । यह आपके शासनकाल की बात है । (हाथ से इशारा करते हुए) उसकी लाश को पुलिस आज उठाती थी तो यहां दफनाती थी, फिर यहां से उठाकर वहां दफनाती थी, फिर उसको वहां से निकालकर उधर दफनाती थी । पुलिस का काम लाश को हत्या करके इधर-उधर दफनाना था और सरकार बदलने के बाद आज वह जेल में है । आपको मालूम है न ? ऐसा वीभत्स कांड छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवर्धा का हाल बेहाल है । आदिवासियों की हत्या बोलूं या वहां यादव समाज के लोगों की हत्या की बात कहूं । वहां एक मां और बेटी की हत्या की बात करूं । किस तरह की बात करूं । अध्यक्ष महोदय, यह क्यों हो रहा है ? मैंने बहुत सोचा । कवर्धा में अभी एक और घटना हुई। एक थाने के सामने कुछ लोग डी.जे. बजा रहे थे । थाने का नाम मैं भूल रहा हूं, यह कवर्धा जिले का ही मामला है । वे लोग डी.जे. बजा रहे थे और गाली गलौच कर रहे थे। थाने के लोग गए, दो सिपाहियों को भेजा गया और कहा कि जाओ, उस डी.जे. को बंद करवाकर आओ । सिपाही वहां गए, उन्होंने डी.जे. को बंद करवाया । सिपाही डी.जे. को बंद करवाने के बाद वापस आये । वे लोग थाना पहुंचे नहीं थे कि फिर से डी.जे. थाने के सामने चालू हो गया । टी.आई. साहब थाने से बोले कि जाओ, फिर से डी.जे. को बंद करवाकर आओ । सिपाही लोग गए, फिर से डी.जे. को बंद करवाए। बंद करवाने के बाद पता चला कि वहां का भाजपा अध्यक्ष थाना पहुंच गया और थाने से फोन लगाया कि अभी के अभी इस टी.आई. और सिपाही का लाईन अटैच होना चाहिए । यह हमने वीडियो में देखा और कुछ घंटों के अंदर में टी.आई. और सिपाही, दोनों का लाईन अटैच हो गया । (शेम-शेम की आवाज) अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि ये जो लगातार चार, पांच, छः और सात घटनाएं हो रही हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, चार चिन्हारी की बात कर रहे हैं। कवर्धा का झंडा कांड आप भूल गए हैं क्या? जब आप सरकार में थे, तब कवर्धा में इतना बड़ा झंडा कांड हुआ , उस झंडा कांड में एक्शन लिया होता, तो वह उसी दिन रुक जाता। आपकी पुलिस की यदि उस समय इतनी सक्रियता रहती, इतनी तत्परता आपकी सरकार में रहती, तो झंडा कांड जैसे इतने बड़े इश्यू में कवर्धा जला है, वह कवर्धा उस दिन जलता नहीं। (व्यवधान) आज लगातार इतने सालों से नहीं हुआ है। (व्यवधान) अब ये आपको सुनना पड़ेगा। आप लोगों को सुनने में इतनी तकलीफ क्यों होती है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अपनी सरकार के समय तबादला उद्योग चलाते थे, अब व्यावहारिक बात कर रहे हैं। (व्यवधान) अपनी सरकार के समय तबादला उद्योग चलाते थे और अब ये बात कर रहे हैं कि लाईन अटैच कर दिया, फलाना कर दिया, ढेकाना कर दिया।(व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, अपनी जगह पर खड़े होते हैं, सुनने में तकलीफ क्यों होती है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, वही बैगा आदिवासी जो दूर था, उसने अपनी जान दी, उस घटना को उस समय आप लोगों ने दबा दी। (व्यवधान) कवर्धा की बात करेंगे तो काफी कुछ उधेड़बुन होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। माननीय सदस्यों के नाम भी हैं, जब भाषण में आपका अवसर आएगा, तब आप अपनी बात रखें। बीच-बीच में रोकने की जरुरत नहीं है, आप कृपया जारी रखें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हो यह गया है कि ये सरकार में आ गए हैं लेकिन इनको लगता है कि अभी भी हम विपक्ष में ही हैं। उन्हें वही पांच साल का कार्यकाल याद आता है और ये सरकार के मन में बैठा हुआ है। किस पर चर्चा होगी? (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, यह बोलकर पुरानी गलतियों को दबाया नहीं जा सकता। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- फिर वर्ष 2001 से चालू करो, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। यही करना है तो लाओ वर्ष 2001 से सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या-क्या हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- बिल्कुल-बिल्कुल। कराइए। बाकी चीजों के विषय भी लाइए, चर्चा कराइए। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके शासनकाल में कितने बलात्कार हुए, कितनी घटनाएं हुई, वह सब आ जाएगा। सबसे ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। (व्यवधान) आपके शासनकाल में सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। देखिए, अनुदान मांगों पर ही सीमित रहें, तो ज्यादा अच्छा है। आप उसी पर बात रखें। दोनों पक्ष के सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इसमें सबको बोलने का समय मिलेगा, उस समय आप अपनी बात रखें। उमेश जी, आप कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट नहीं बोलता फिर वह शुरु हो जाते हैं। हमने वहां देखा कि वह लाईन अटैच हो जाते हैं। अब किसी मंत्री से बात किए, ये तो उस वीडियो में पता चला नहीं, लेकिन किसी मंत्री से बात कर रहे थे, ये पता चला और दो घंटे के अंदर उनका लाइन अटैच हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो घटनाएं हो रही हैं, जब से इनकी सरकार बनी है, तब से ये पुलिस को कार्यकर्ता के रूप में काम कराना शुरु किए हैं, इसीलिए लोगों का विश्वास इस सरकार की तरफ कमजोर हुआ है। पब्लिक अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर कब लेती है, वह तभी लेती है, जब उसका विश्वास इस शासन/प्रशासन के ऊपर समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि पुलिस की धमक को बनाए रखिए। पुलिस को एक कार्यकर्ता के रुप में काम कराना बंद कीजिए। पुलिस का एक जो वजन है, उसे बनाकर रखिए, ताकि क्रिमिनल्स और जो दोषी लोग हैं, उनमें पुलिस का एक डर बना रहे। अध्यक्ष महोदय, इस लोगों की ताकत देखिए। आपने स्वयं देखा होगा, मेरे ख्याल से सभी सदस्यों ने देखा होगा, वन विभाग के दो कर्मचारी कवर्धा जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें लहूलुहान किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को वायरल किया जाता है। उनको बांध दिया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है, ये तो क्रिमिनल्स की ताकत हो गई है। इसमें हमारे जितने भी पुलिस

के अधिकारी हैं, मैं उनसे भी इस बात को कहूंगा कि आप लोग पढ़-लिखकर इस वर्दी को अपने शरीर के ऊपर पहने हैं, इस वर्दी की आन-बान-शान को बनाकर रखिए। किसी से डरने की जरुरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ी घटना, जिसे आपने चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट किया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट आया है और अधिकारी दीर्घा में एक भी अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अधिकारी बैठे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, एक-दो अधिकारी बैठे हैं। यह पूरे अनुपूरक बजट का विषय है। कम से कम इसमें तो अधिकारी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- दीदी, जरूरत ही नहीं है। मंत्री स्वयं में पर्याप्त है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठकर माईक ऑन करके कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है संगीता जी। इसके लिए उनको प्रताड़ित किया जाये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, यदि मुझसे कोई भी अवहेलना हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के कोई भी अधिकारी यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, हमको किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, यह हम निर्धारित करेंगे। हम तैयारी से आये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, तो अधिकारी दीर्घा बंद करवा दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी वहां से आदेश कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है। यह बात उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने अपनी बात कह दी। अब आगे बढ़िये।

श्री धर्मजीत सिंह :- निषाद साहब, इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी सरकार थी, तब हमने भी कई बार देखा था कि अधिकारी दीर्घा का पूरा मैदान साफ रहता था। उस समय हमने कई बार सदन की कार्यवाही भी रूकवाई है। यहां तो चार अधिकारी बैठे भी हैं। पहले तो एक भी नहीं रहते थे तो कार्यवाही भी रूकी है कि पहले अधिकारियों को अधिकारी दीर्घा में बुला लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हम भी तो वही बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, हमको अधिकारियों की जरूरत नहीं है, यह बात उचित नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमको सबकी जरूरत है। यह सदन सब के साथ चलेगा। हमको तो आपकी भी जरूरत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि पर्ची देखने के बाद ही जवाब आता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, वहां से आंकड़ों की पर्ची आयेगी, तभी आप जवाब दे पायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यदि जरूरत नहीं है तो अधिकारी दीर्घा को बंद करवा दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। यदि अधिकारी दीर्घा की आवश्यकता नहीं है तो आप व्यवस्था बनाईये कि वहां पर कोई नहीं बैठेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- उमेश जी, तिल का ताड़ मत बनाईये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। यदि ट्रेजरी बेंच मानती है कि अधिकारी दीर्घा की आवश्यकता नहीं है तो आप व्यवस्था बनाईये कि अधिकारी दीर्घा को हटवा दीजिये।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, यदि वित्त मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं तो अधिकारी दीर्घा को हटवा दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वहां चार अधिकारी बैठे हुए हैं और हमको तो आपकी भी जरूरत है। बिना आपके हमको अच्छा नहीं लगेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, काऊण्ट करवा लीजिये कि कितने अधिकारी बैठे हैं।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, काऊण्ट करवा लीजिये। यह बोल रहे हैं कि चार अधिकारी बैठे हैं परंतु वहां तीन अधिकारी ही बैठे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है और अधिकारी उपस्थित नहीं है।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- आपको हमसे काम कराना है या अधिकारी से ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी मांगें रहती हैं, उसको भी तो अधिकारी नोट करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि यदि अधिकारी दीर्घा की जरूरत नहीं है तो आप इसको बंद करवा दीजिये। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी व्यवस्था आनी चाहिए, तभी हम आगे की कार्यवाही में भाग लेंगे।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण लेते हुए एक बात बताना चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय नेताम जी, आप यह बताईये कि आपको अधिकारियों की जरूरत है या नहीं (हंसी)? ओ.पी. चौधरी जी ने तो कह दिया कि उनको अधिकारियों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है या नहीं ?

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। यहां सदन में जितने सीनियर लीडर है, उनको स्मरण होगा। आपके ही कार्यकाल का एक समय ऐसा था, जब आपके खास मित्र की सरकार थी। आप उस बात को तो मानेंगे ना ?

श्री भूपेश बघेल :- हां।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जब अधिकारी नहीं होते थे, दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया जाता था (हंसी)। एक बार कहां से विदेशी आदमी को लाकर अधिकारी दीर्घा में बैठाया गया, तब हम लोगों ने हल्ला किया कि आपने सदन में कौन से अजूबा आदमी को लाया है। यह स्थिति थी। उस स्थिति से तो आज हमारी स्थिति अच्छी है कि अधिकारीगण बैठे हुए हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अधिकारी अभी आये हैं।

श्री कवासी लखमा :- आपके वित्त मंत्री बोलते हैं कि हमको अधिकारियों की जरूरत नहीं है। ऐसा है तो कुर्सी हटवा दीजिये। हमने चुन लिया है। यह सदन की नियम प्रक्रिया में लिखा हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह वित्त मंत्री अधिकारियों से चिट नहीं मंगवाते हैं इसलिए उन्होंने बोला कि उनको जरूरत नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हम आपसे व्यवस्था मांगते हैं। आप यह तय करे कि यहां अधिकारी दीर्घा की आवश्यकता है या नहीं। यदि जरूरत नहीं है तो हम बैठ जाते हैं।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- सामान्यत: नियम परंपरा यह है सभा में अध्यक्षीय दीर्घा के अतिरिक्त अन्य दीर्घा पर हम चर्चा नहीं करते, मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुपूरक की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। यह गंभीर विषय है। उनमें अधिकारियों की उपस्थिति रहनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) चलिये, अब आप शुरू करिये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय

3.00 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, दो दुनी चार, दो तिया छः।

सभापति महोदय :- श्री उमेश पटेल जी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपको क्या दिक्कत है, यह बताईये?

श्री राजेश मूणत :- आप जो स्क्रीप्ट लिखकर लाये हो, आप ऐसे भी बोल दीजिए और यहां दे दीजिए । माननीय उमेश पटेल जी एक बात जरूर बताईएगा। जब आप बोलेंगे तो आप तो अड़ोसी-पड़ोसी हैं। आप अनुपूरक पर बोलेंगे तो कम से कम रायगढ़ में जो काम और रायगढ़ जिले के अंदर उन छात्रों के लिए नालंदा परिसर से ही बड़ी लाईब्रेरी बना रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद् जरूर दे दीजिएगा। वहां अपने भी बच्चे पढ़े हुए हैं और आप भी वहीं से सब जगह से पढ़कर निकले हैं।

श्री उमेश पटेल :- आपको याद है न। जब आप लोक निर्माण मंत्री थे तब मैंने आपको धन्यवाद् दिया था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आप अभी भी धन्यवाद् दे दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- अभी भी मैं आपको धन्यवाद् दूंगा। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार को बने हुए अब एक साल हो गया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति है। मैं सारंगढ़ गया था। सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र से हमारी विधायक महोदया श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी हैं। उनके पति के ऊपर एफ.आई.आर. हो जाता है। वह एफ.आई.आर. किस बात के लिए हुआ कि उन्होंने गलत ढंग से धान को बेचा है। उन्होंने धान को कब बेचा जब वह उपस्थित ही नहीं थे। वह कहां गये थे जब वे आऊट ऑफ स्टेशन थे और उनके नाम से किसी ने धान बेचा तब उन्होंने स्वयं उसकी शिकायत की। मेरे नाम से किसी ने धान बेचा है मुझे ऐसी जानकारी मिली है। उन्होंने अपेक्स बैंक को एक चिट्ठी भी लिखकर दी कि मेरे खाते में कुछ पैसा आया हुआ है इसको वापस लिया जाये। इतना करने के बावजूद अगर उनके ऊपर एफ.आई.आर. होता है तो इसे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में दमनकारी नीति चल रह है। मैं दमनकारी नीति इसलिए बोलूंगा। इस छत्तीसगढ़ के लिए धान खरीदी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रदेश के राईस मिलर्स धान खरीदी के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।

पिछले 3 दिनों में जिस तरह से उनको सील किया गया है, डराया, धमकाया और बैठाया गया है और जबरदस्ती उनके हड़ताल को वापस कराया गया है। यह एक दमनकारी सरकार का उदाहरण है। मैं तो कहता हूँ कि आप उनके साथ बैठिए। इस सरकार, उस सरकार ने यहां हो गया...

श्री राजेश मूणत :- हम किनके साथ बैठें?

श्री उमेश पटेल :- माननीय मूणत जी, आपका टेप अटक गया है? आप वहीं पाये जाते हो।

श्री राजेश मूणत :- हम किनके साथ बैठें? भाई सुनना ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जिससे जब पूछना था तब पूछना था। आप अभी कहां लगे हो।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आधे जेल में हैं। आधे बेल में में हैं और आधे रेल में हैं। अब किसके साथ बैठें, आप यह बता दीजिए ?

श्री विक्रम मण्डावी :- जिस होटल में बैठे थे, वहीं पर फिर से ...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जिस होटल में तीन-तीन लोग बैठे थे उसी में। आप जिन लोगों के साथ बैठे थे उसी में।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, वहां मेफयर में तो हम दोनों तो बैठे थे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, वहां पर हम दोनों तो खाना खाने के लिए बैठे थे।(हंसी) यह राईस मिलरों के साथ बैठकर, चर्चा करके, उनसे बात करके एक रास्ता निकालने की आवश्यकता होती है। उनको डरा, धमका कर क्या होगा ?मेरी यह आशंका है। होगा क्या ? उन्होंने डर में हां कहा है। वह लोग डर में हां कहने के बाद डी.ओ. भी कटवायेंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश भाई, कृपया आप एक मिनट दीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय राजेश मूणत जी, उनको बोलने दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, बहुत आदरणीय हैं, उपनेता हैं।

श्री उमेश पटेल :- उप नेता नहीं हूं।

श्री राजेश मूणत :- क्या उप नेता खत्म हो गया?

श्री उमेश पटेल :- उप नेता नहीं बनना चाहता हूं।

श्री राजेश मूणत :- चलिये, भगवान करे आपको बनाये। मैं आपके साथ हूं।

श्री विक्रम मंडावी :- राजेश भैया, आप मंत्री कब बन रहे हैं, यह बता दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप राईस मिल की जितनी बात कर रहे हैं, सब लोग एक बात चाहते हैं, 120 रुपये किसके कहने पर तय हुआ था? आप मेरी बात को सुन लीजिए। दुर्ग में कौन-कौन इनवॉल्वमेंट थे? तीसरा जो व्यक्ति राईस मिल का पूर्व

अध्यक्ष था, जो बिचौलिये के रूप में था, जिसके ऊपर ई.डी. ने चार्जशीट दायर की, उससे कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, बस वह क्लीयर कर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- और कुछ पूछना है?

श्री अटल श्रीवास्तव :- कौन 03 लोग थे, यह बता दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- दे दिन हमू मन के जांच करय के समय आही न, ओमा मे-फेयर जरूर लिखाही। यह याद रखना।

श्री अटल श्रीवास्तव :- कौन तीन लोग पैसा लेने गये थे? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- उमेश भैया, 40 टका का कहां गया, पता कीजिए? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप देखना मे-फेयर कहां निकलेगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मे-फेयर में कौन तीन मंत्री गये थे, इसको भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- उमेश भैया, यह तो बताईये कि 40 टका का कहां गया?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति जी, अब जवाब तो देने दें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, अब वह भी नया-नया आदमी था, पुराने कोषाध्यक्ष का आज तक पता नहीं लग पा रहा है।

सभापति महोदय :- राजेश जी, आपका विषय आयेगा, आपका भी नाम है, सुशांत शुक्ला जी का भी नाम है और इसमें 17 सदस्यों को चर्चा करनी है और कुल 3 घंटे का ही समय है। इसीलिए जो भी बोल रहे हैं उनको टोकाटाकी न करें, आपने समय पर बोलें। आप बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने निर्णय ले लिया है, मैं जब भी बोलूंगा उसमें राजेश मूणत जी ही बोलेंगे।

सभापति महोदय :- आप उधर ध्यान मत करिये न, आप अपनी बात रखिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मूणत जी, मैं यह कहता हूं कि हमारी सरकार थी, कुछ काम हुए। आप जो आरोप लगा रहे हैं। आपको जांच करने का अधिकार है, आप जांच करिये, जिन्होंने गलती की है, उनको अंदर डालिये, बिल्कुल अंदर डालिये। लेकिन मैं इस मंच से यह भी कहूंगा कि वह मे-फेयर की भी जांच होगी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तीन लोग कौन थे, इसकी भी जांच होगी।

श्री राजेश मूणत :- आपकी सरकार 05 साल तो थी, आप क्या कर लिये? जाना पहचाना खरा, डंके की चोट..। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- फिर से 5 साल आने वाला है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति जी, धमकी दी जा रही है।

श्री उमेश पटेल :- मैं ताल ठोक कर बोल रहा हूं जिसने गलती किया है, उसको अंदर करिये। लेकिन ताल ठोक कर यह भी बोल रहा हूं कि वह मे-फेयर में जो तीन लोग थे जिन्होंने कट लिया, उनके ऊपर भी जांच होगी। जब कांग्रेस सरकार आयेगी तो वह 03 लोग अंदर होंगे।

श्री अनुज शर्मा :- एकर मन के कबहू सरकार बनही, तब ना।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन यह सब सुन लेव।

श्री राजेश मूणत :- यादव जी, एक मिनट सुन लीजिए। मैं उमेश पटेल जी की भावनाओं का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैंने पहले भी सदन में एक बात कही है और पूरे कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है। आज फिर चुनौती दे रहा हूं कि झीरम घाटी के दस्तावेज कहां हैं? (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- राईस मिल वालों का पहले बताईये न। राईस मिल की बात कर रहे हैं, आप झीरम में पहुंचे गये।

श्री राजेश मूणत :- बहुत बोलते थे कि मेरी जेब में दस्तावेज रखे हैं, 05 साल मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, आप उसकी जांच नहीं करा पाये। आप क्या बात करेंगे? (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- आप राईस मिल की बात करिये न, झीरम में क्यों जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आप मेरे साथ बैठिये। इस विषय में मैं आपके साथ बैठूंगा और पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या हुआ?

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, जितना दर्द आपका है, वह छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे थे।. (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप एक चीज ईमानदारी से सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- जांच रोकने की बात किसने की ? (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- हम चाहते हैं कि दस्तावेज आये । (व्यवधान) साय-साय सरकार साय-साय कार्रवाई करेगी और जिसको-जिसको दण्ड देना होगा उसको यह सरकार नहीं छोड़ेगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- आप करिए ।

श्री राजेश मूणत :- आप दस्तावेज लाईये, हम चर्चा करने को तैयार हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मे-फेयर होटल (May fair Hotel) की बात कर रहे हैं । मे-फेयर होटल बना ही इसलिये है कि वहां लोग जायें । खाना खायें, मिलें-जुलें । मे-फेयर होटल में क्यों नहीं जायेंगे ? और आप मे-फेयर की बात कर रहे हैं, जो खनिज निगम का सौदा हुआ था वह आपकी सरकार में मे-फेयर होटल में हुआ था । (शेम-शेम की आवाज) और सुनिये, इधर-उधर दारू का जो होलोग्राम छपा है वह मे-फेयर होटल में छपा है । (शेम-शेम की आवाज) और जो सेण्ड माफिया का

निर्णय हुआ था वह मे-फेयर होटल में हुआ था तो मे-फेयर होटल में किसी के जाने में तो आपत्ति नहीं कर सकते हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- पी.एस.सी. का घोटाला भी वहीं तय हुआ था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अगर कोई घटना हुई हो । अगर आपके पास प्रमाण है कि वहां पर आपके पास ऑडियो हो, वीडियो हो तो बता दीजिये कि कौन लोग गये थे, अब कोई बाहर का आदमी मे-फेयर होटल में गया । कोई अगर भाजपा का है तो नहीं जा सकता, कांग्रेस का है तो नहीं जा सकता यह कौन सा तर्क है ? यदि हमारी सरकार ने मे-फेयर होटल में जाकर कोई घोटाला किया हो तो आप तथ्यों में बात करिये और उसको आपको बताना चाहिए । मे-फेयर होटल में हम दो सौ बार जायेंगे और कौन-कौन नहीं गये हैं, उनको भी भेज देंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल ।

सभापति महोदय :- देखिये । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा है । माननीय सदस्यों से आग्रह है कि विषय पर बोलें ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो दूसरे विषय में नहीं जा रहा था, मैं तो अभी नहीं जा रहा हूं । मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि मैं इसी विषय पर, इसी एक साल पर ही बात करूंगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- आपने ही मे-फेयर होटल की बात शुरू की थी ।

श्री उमेश पटेल :- उन्होंने क्या कहा ? कहां से शुरू हुआ पहले उसको तो सुन लीजिए । आपके बगल में जो बात आयी ।

श्री राजेश मूणत :- मैंने मना थोड़ी न किया ।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपको यह चीज फिर से कहता हूं कि आप लोगों की सरकार है, आरोप लगाना बंद कर दीजिये ।

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं । हम तो यही कह रहे हैं । आप मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपकी बात बताउं । आपने कहा कि गौठानों में घोटाला हुआ है । अभी मैं बताता हूं कि मेरे यहां 30 गौठानों पर इन्होंने जांच करायी, क्या मिला, कुछ नहीं । पता चला कि अभी सरकार को सरपंचों को पैसे देने की आवश्यकता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, कुछ होगा तब तो कुछ मिलेगा न । पिछली सरकार में ही गौठान गायब है । गौ भी गायब है और गौठान भी गायब है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप कुछ समझ रहे हैं ? आपको समझ में नहीं आता है तो मत बोला करो । हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, कुछ बचा ही नहीं है तो कहां होगा ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तुंहर बर दू झउंहा गोबर हेरे बर लगही ।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आरोप लगाना बंद करें । अभी आप सरकार में हैं । कोई भी आरोपी हो, आप उसको उठाईये और अंदर करिये। अगर कोई भी आरोपी है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- डबल इंजन की सरकार है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, ये 3-4 लोग यह चाहते हैं कि वह 3 नाम उजागर हो जायें ताकि मंत्री पद खाली हो तो ये मार्गदर्शक मण्डल लोगों का नंबर आ जाये । (हंसी)

सभापति महोदय :- उमेश जी, अनुदान मांगों पर बोलिये ।

श्री उमेश पटेल :- जी । माननीय सभापति महोदय, मैं यही कह रहा था कि राईस मिलरों के साथ बैठने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है । उनको डरा-धमकाकर, मेरी आशंका यह है, यह मेरी आशंका है । हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं । मेरी आशंका यह है कि यदि आप उनको डरा-धमकाकर कम कराओगे तो वे क्या करेंगे, उनकी क्षमता से कहीं कम वे लोग डी.ओ. कटवाएंगे, ऐसा प्रमाणित करेंगे कि भैया हम तो धान उठा रहे हैं । किसी ने 500 का उठा लिया, किसी ने 100 का कटवा लिया, अपनी क्षमता के अनुरूप किसी ने हज़ार का कटवा लिया और फिर उससे क्या होगा कि सोसायटियों में जाम जारी रहेगा, आज जाम की स्थिति है। आपने कई जगह छापा मारा, कई जगह यह किया उससे अच्छा उनको बैठायें, उनका जो payment है, सरकार आती रहती है, कोई payment हमारे समय का है उसको हम मना नहीं कर रहे हैं । आप अनुपूरक में लाईये, उस पैसे को दीजिए और खत्म करिए । लेकिन धान खरीदी छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस छत्तीसगढ़ के किसानों का लगभग अस्सी से ज़्यादा परसेंट लोग इससे सीधे प्रभावित होते हैं । चाहे वह किसान हो, चाहे राईस मिलर्स हो, चाहे हम्माल हो, चाहे वह प्रबंधक हो । किसी भी रूप में 80 प्रतिशत लोग सीधे-सीधे इससे प्रभावित होते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा कहना है कि दमनकारी नीति को छोड़कर टेबल पर आ जाइए, बातचीत करिए और उससे जब बातचीत करेंगे तो हल भी और रास्ता भी निकलेगा। ये मैं मान रहा हूं क्योंकि जब वे मुख्यमंत्री के पास गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए रास्ता निकाला था। मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था। हम तो ये सोचे भैया कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर आये हैं तो रास्ता निकल गया है। अब कल से राइस मिलरों का हड़ताल खत्म हो जाएगा, लेकिन पता चला कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की कही हुई बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मुख्यमंत्री जी का राइस मिलरों के लिए जो आश्वासन है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से राइस मिलरों को फिर से हड़ताल में बैठना पड़ गया। भैया, जिसकी चल रही है, उसको उनके साथ बैठा

दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी की नहीं चल रही है तो हम लोगों के पास तो इतना ज्ञान चक्षु नहीं है कि हम देख पाएं कि किसकी चल रही है? महोदय, झालर लगा रहता है। जब दीपावली में हम लोग झालर लगाते हैं, पता है। कभी-कभी उस झालर को लगता है कि मैं सूरज हूं। मूणत जी, देखे दीपावली में झालर लगा रहता है। उसके एक बल्ब को हमेशा ये लगता है कि मैं सूरज हूं। क्या मालूम यहां हर झालर को लग रहा होगा कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं। हो सकता है कि सुपर सी.एम. कुछ हो। सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिसकी चल रही है, उसके साथ राइस मिलरों को बैठाएं। लॉ एंड ऑर्डर के मैटर को देखें। पुलिस के बूट की धमक बनी रहनी चाहिए। सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में कभी भी पुलिस के मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी की सरकार हो। सभापति महोदय, मैं इस विषय के अलावा एक और विषय को टच करना चाहूंगा। शायद इस सत्र में या इससे पहले सत्र में बहुत ज्यादा बात हुई नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रश्न अवर पर इन्होंने घोषणा किया। जहां तक मुझे याद है, शायद प्रथम बजट सत्र था । प्रथम बजट सत्र में इन्होंने घोषणा किया कि प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को हम रेत मुफ्त में देंगे। ये इस सदन में घोषणा थी। हम सब ने ताली बजाई थी। बीच में प्रधानमंत्री आवास आया नहीं, प्रधानमंत्री आवास निकलना शुरू हो गया। आज के दिन में किसी भी व्यक्ति को फ्री में रेत नहीं मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति को मिल नहीं रहा है और रेत की स्थिति यह है कि रेत की नीति तो बदली नहीं, जो मेरे ख्याल से वर्ष 2022 की थी, वही नीति आज भी चल रही है, लेकिन बिना घाट के घोषणा के चल रहे हैं। सभापति महोदय, दो गांव है, दो गांव के लोग परेशान हो गये हैं। एक का नाम है बनर और एक का नाम है काशीचुआं। उसके बगल में गांव है लेबड़ा। 250 ट्रैक्टर रोज उस रोड से चल रहे हैं और दोनों जगह प्राथमिक स्कूल हैं। पहले वे लोग माइनिंग इंस्पेक्टर के पास गए बोले भैया, ये रेत में कुछ कारवाही कर दो, हम लोगों को बख्श दो। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वे लोग एस.डी.एम. के पास गए। एस.डी.एम. बोला ठीक है, मैं आकर देखता हूं। इतनी गाड़ी क्यों चल रही है? वे लोग कलेक्टर के पास गए, मैं खुद उनके साथ कलेक्टर के पास गया था । काशीचुआं में भी स्कूल के सामने, बनर के सामने कलेक्टर की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेत घाट वैसी की वैसी चलता रहा और जिस दिन हम लोग कलेक्टर के पास गए थे, उसके एक हफ्ते बाद एक आदिवासी लड़के की मृत्यु उस घाट में हो गई। सभापति महोदय, इसका जिम्मेदार कौन है? जब एक illegal रूप से रेत उत्खनन हो रहा है, जिसकी जानकारी गांव वालों ने दी, जिसकी जानकारी मैंने स्वयं कलेक्टर को दी। मैं उपस्थित होकर उसके ऑफिस में इसकी जानकारी दी। उसके एक हफ्ते बाद अगर एक आदिवासी लड़के की मृत्यु उस उत्खनन के कारण होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह की रेत की नीति चल रही है। बदल लो। आप सरकार में आगे हो। नई नीति बना लो, आपको जो अच्छा लगता है वह कर लो, लेकिन एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपके समय में तो उमेश जी आप बोले कि वही नीति चल रही है। ट्रक के ट्रक पूरे उत्तप्रदेश झारखंड पूरे चले जा रहे थे, उसको तो देखिए।

श्री कवासी लखमा :- एक साल हो गया है। एक साल से क्या कर रहे हैं?

श्री रामकुमार यादव :- एक ट्रैक्टर, दू ट्रैक्टर छोड़ो, यहां घोषणा करे हव, छत्तीसगढ़ के गरीब मन ला ताली बजवाए हव कि फ्री में रेत देंगे तो कुछ दिये क्या?

श्री उमेश पटेल :- आप शायद समझे नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, वही नीति चल रही है । लेबड़ा को आप लीगल घाट डिक्लेयर कीजिए ना, उसके बाद चलाइए । वहां से ढाई सौ ट्रेक्क्टर चल रहे हैं, बिना लायसेंस के लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये कोई आम आदमी नहीं, ठेकेदार लोग गांव-गांव से किराये पर ले रहे हैं । ऐसा नहीं है कि कोई गांव का गरीब आदमी ले जा रहा है । गांव का गरीब आदमी एक ठेला ले गया तो उसको हम भी नहीं देखेंगे और आप भी नहीं देखेंगे । लेकिन वह तो ठेकेदारी कर रहा है । धर्मजीत भईया बहुत शर्म की बात कब होती है, पता है ? जब एक पत्रकार माइनिंग अधिकारी को फोन लगाकर कहता है कि रेत के कारण गांव वालों के पास शिकायतें आ रही हैं, कलेक्टर के पास शिकायतें आ रही हैं, एस.डी.एम. के पास शिकायतें आ रही हैं तो वह कहता है कि हमें ट्रैक्टर पकड़ने की ऊपर से मनाही है । (शेम शेम की आवाज़) ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति जी, ये अभी का बता रहे हैं या अपने कार्यकाल का बता रहे हैं । ये सब आपके समय चलता था ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरे साथ चलिए, अभी दिखाता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- उस पेपर की कटिंग को मैं यहां प्रस्तुत भी कर दूंगा । उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप यह बयान ऑफिशियली दे रहे हो ? तो उसने कहा कि हां मैं ऑफिशियली बयान दे रहा हूं । मुझे ऊपर से मनाही है कि ट्रैक्टर नहीं पकड़ना है चाहे इल्लीगल हो, यह शर्म की बात है सभापति महोदय । सभापति महोदय, रेत में, वन विभाग में कर्मचारियों को जिस तरह से इल्लीगल मामलों में कार्यवाही करने से रोका जा रहा है । पुलिस को जिस तरह से रोका जा रहा है, यह हमारा आदमी है इस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और यह कांग्रेस का आदमी है इसके ऊपर डबल एफ.आई.आर. होनी चाहिए । कांग्रेस का आदमी कहीं चला जा रहा है तो उसको पकड़कर अंदर करो । इस पर रोक लगनी चाहिए तभी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में एक विश्वास का वातावरण तैयार होगा । जब ऐसा वातावरण तैयार होगा तब लोग इस शासन पर विश्वास करेंगे और कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे । अभी कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पांच साल जब आपकी सरकार थी ना तो ऊपर वाला और ऊपर वाली के कारण आपकी भी नहीं चलती थी ।

श्री कवासी लखमा :- पांच साल हमने गलती तो हम इधर बैठे हैं ना । हमने जो किया आप भी वही करेंगे ?

सभापति महोदय :- उमेश जी, संक्षेप में, आधे घंटे से ज्यादा हो गया ।

श्री उमेश पटेल :- धर्मजीत भइया, आप यहीं पर बैठते थे ।

श्री राजेश मूणत :- यार उमेश भाई, वो खनक वाली आवाज किसकी थी ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, हम लोग विपक्ष में हैं, हम नीति निर्धारण नहीं कर सकते लेकिन हम लोग आपको आईना नहीं दिखा सकते कि सरकार कैसी चल रही है । हो सकता है लोग आपको बता रहे हों कि सब हरा-हरा है, सब सुंदर है, राम राज आ गया, दूध की नदियां बह रही हैं, लोग शहद पी रहे हैं । लेकिन ऐसा नहीं है । सभापति महोदय, वास्तविकता बहुत खराब है । इसलिए मैं इस बजट का विरोध करते हुए, आपके इशारे को समझते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर ।

श्री रामकुमार यादवव :- मेहनत करे मुर्गी अउ अंडा खाए फकीर (हंसी) ।

श्री राजेश मूणत :- मुर्गी कौन है भाई ? आप मुर्गी का नाम ले रहे हो, मुर्गी कौन है ?

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, उमेश बाबू ने लगभग 45 मिनट भाषण दिया है । (श्री उमेश पटेल, सदस्य के सदन से बाहर जाने पर) कहां चले, कहां चले ? सभापति महोदय, बजट क्या होता है, बजट क्यों आया है? उस पार्ट पर बोलना आता है या नहीं, यह मैं नहीं जानता । किंतु विष्णुदेव साय जी की सरकार के नवजवान वित्त मंत्री ने इस छोटे से अनुपूरक बजट को जिस तरह से विज़नरी बनाया है, दृष्टिकोण से युक्त बनाया है, उसको सोचना, समझना इनके बस की बात नहीं है । इनको लगता है कि साल भर में छत्तीसगढ़ की जनता सब भूल गयी। छत्तीसगढ़ की जनता कुछ नहीं भूली है। अभी उस पर बात करेंगे। बजट दृष्टिकोण से युक्त क्यों है ? जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ? छत्तीसगढ़ को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं या ले जाना चाहते हैं ? ये नौजवान वित्त मंत्री किन प्रयत्नों में लगा हुआ है ? उसको सोचने समझने की जरूरत है। विनियोग के एक पार्ट में बोल रहे हैं, ठीक है साहब, आपने आलोचना कर ली, विनियोग के एक पार्ट में बोल लिया लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अब तक जितने अनुपूरक और पूरक आए, अभी मुख्य बजट के पहले एक अनुपूरक और आएगा। 805.71 करोड़ का बजट है, उसमें 62 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ पूंजीगत व्यय के लिए है। इतना बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए कभी बजट में आयोजित किया नहीं गया। यह समझ में आएगा। दादी, यह समझ में आएगा।

श्री कवासी लखमा :- अपनी स्थिति पहले बताईए।

श्री अजय चंद्राकर :- ये उठकर चले गये, इसीलिए वे दोनों बाहर हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अजय जी, दादी को मत समझाईए। दादी, 5 साल तक आबकारी विभाग चलाएं हैं। राजस्व का हिसाब तो जानते ही होंगे, आप वहां क्या समझा रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- अभी दादी के तरफ आना पड़ेगा। उसके बगैर हमारा भाषण पूरा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आयोजन भले छोटा सा हो लेकिन उससे इच्छाशक्ति 100 गुना बढ़ी है। इस बजट में पूंजीगत व्यय 50 प्रतिशत से उपर पार हुआ। आगे यह प्रतिशत और बढ़ेगा। इसकी झलक आपको मुख्य बजट पर दिखेगी।

श्री कवासी लखमा :- इसमें मुख्य बजट में क्या झलक दिखेगी ? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए थोड़ा विनियोग की ओर बढ़ जाते हैं, फिर बजट में बात कर लेता हूं। इनको तो इस चेयर में बैठना नहीं चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। पूरे कांग्रेस पक्ष को इस्तीफा देना चाहिए और क्यों देना चाहिए ? इनको पूरी देश की जनता ने, इनके सहयोगी दल इंडिया ब्लाक के लोगों ने नकार दिया और नकारना शुरू किया कि आप EVM का रोना मत रोईए। आज अभिषेक बनर्जी जी का बयान है। शरद बाबू बोल दिए, लालू जी बोल दिए, उमर अबदुल्ला जी बोल दिए। दादी, भी EVM में बयान दिए। जब EVM में शंका है तो EVM से चुनकर आए हो, यहां से इस्तीफा देकर निकलिए। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, उस दिन यहां अंदर आईएगा।

श्री कवासी लखमा :- गुस्सा मत होईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, एक शायरी बोल देती हूं, महोदय जी, बहुत सीरियस हो गये हैं। अजय जी, बहुत ही आक्रोशित होकर बात करे हैं।

श्री कवासी लखमा :- यहां लोकसभा चल रहा है। थोड़ा लोकसभा जाकर देखिए।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है, लोकसभा, विधान सभा की बात नहीं है। आपका जो घीसा-पीटा वक्तव्य है, आपका जो घीसा-पीटा दृष्टिकोण है, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो नकार ही दिया, आपके इंडिया ब्लाक के लोग भी आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यहां सभा पर आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब आईना दिखा रहे हैं, क्यों आईना दिखा रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, बहुत ही आक्रोशित होकर बात कर रहे हैं। विनियोग पर बात हो रही है। एक शायरी है, मैं उसको बोलना चाह रही हूं। माहौल को थोड़ा नार्मल कर रही हूं।

श्री राजेश मूणत :- अजय जी एक मिनट।

श्री कवासी लखमा :- मोदी जी बोल रहे थे, 400 पार। क्या 400 पार हो गया?

श्री राजेश मूणत :- शायरी किसके लिए है, मोहले जी के लिए है या अजय जी के लिए है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सरकार के लिए है। इतना भी गुमान न कर अपनी जिद पे ए बेखबर, राज्य में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे, हमारी हार के हैं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं कि आप गंगा, यमुना, त्रिवेणी के अंदर की सरस्वती हैं, पिछले 5 साल आपकी ज्यादा चलती थी लेकिन वह गोपनीय तरीके से चलती थी। आपकी प्रत्यक्ष में नहीं चली। प्रत्यक्ष में किसी और का नाम था। गोपनीय रूप से आपका ही चलता था। अब इससे ज्यादा आलोचना नहीं करता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जितनी बुराई ये पूर्ववर्ती सरकार की कर रहे हैं, वह एक साल में जनता जान चुकी है।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे, जीत गये तो इतराना मत और हार गये तो घबराना मत।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आज भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार की चर्चा है। आप भी इस बात को मानते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, आप बोलते जाइये। यूनिटी मॉल की स्थापना। मैं सोच रहा था कि यह नवजवान बजट पर बोलेगा। आप आदिवासियों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने उत्पाद हैं, बाहर के लोग भी अपनी लोककला से संबंधित, फोग से संबंधित व किसी भी चीज से संबंधित। आपके यहां बहुत से शिल्प हैं। जैसे-बांस शिल्प, डोकरा शिल्प। छत्तीसगढ़ के हर 100 किलोमीटर में नई चीजें देखने को मिलेगी। वह यूनिटी मॉल के लिए नये हेड बनाएंगे। मैं यूनिटी मॉल बनाऊंगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार दूंगा। यदि आपने इसके लिए एकाध प्रयत्न किया हो तो बताइये। यूनिटी मॉल की परिकल्पना के बारे में बताइये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। सी-मार्ट उसी के लिए बनाया गया था। आपने उसका नाम बदल दिया। आप केवल नाम बदल रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। काम तो वही पुराना वाला चल रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- आपने उसका नाम बदल दिया। प्रधानमंत्री आवास ला पी.एम. आवास कर देहो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- इनका सुनना है। अगला नंबर इनका है। एक को भेज दिये हैं, अगला इनका ही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अभी दारू के बारे में भी बताएंगे। अभी दारू रेस्टारेंट में भी मिलेगा, चंद्राकर जी उसके बारे में भी बताएंगे।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी के बुद्धि ज्यादा हो गेहे। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- अभी आप लोगों का ध्यानाकर्षण था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 53 करोड़ रूपये। जो पी.एम. जनमन योजना है, उससे छत्तीसगढ़ के कितने लोग प्रभावित होंगे ? जैसे अभी

हम नियद नेल्लानार योजना की चर्चा करेंगे। लेकिन पी.एम. जनमन योजना के क्षेत्र में आंगनबाड़ी बनेगी। वह primitive tribes। किसी समय आदिवासी मंत्रालय बना। आयोग बनाकर आदिवासी लोगों को legislative support दिया गया। उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई। उस बजट के बाद primitive tribes के लिए अलग अभिकरण बने। लेकिन वह अभिकरण कागज में रहें। दिल्ली सरकार ने जितने पैसे भेजे, उसकी आपने कभी चिंता नहीं की। जिनकी डबल इंजन की सरकार कही जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पैसे दिये, उसके अतिरिक्त इस नवजवान वित्त मंत्री ने कहा कि हम भी उसमें पैसे देंगे। वहां के primitive tribes के बच्चों के लिए यह जो आंगनबाड़ी बनेगी, उससे उनका पोषण का स्तर सुधरेगा, उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और उनका देख-रेख सुधरेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त ही आई है, दूसरी किश्त के लिए लोग भटक रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी आंगनबाड़ी में चर्चा चलने दीजिए। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में चलेंगे। अभी बजट पर चर्चा चल रही है। उमेश जी, क्या आप गुटखा खाने गये थे ?

श्री उमेश पटेल :- नहीं।

श्री रामकुमार यादव :- ओ गोली खात रीहिस हे।

श्री अजय चंद्राकर :- बस्तर ओलम्पिक। एक छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक होता था। लखेश्वर जी, बस्तर ओलम्पिक के लिए बजट से 7.6 करोड़ रूपये लिये गये। 10 कदम उठाये गये। 100 कदम उठाये जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 दिन केन्द्रीय मंत्री रहें। मैंने कहा कि मैं नियद नेल्लानार योजना की चर्चा करूंगा। उसको मुख्यधारा में लाने के लिए एक प्रयास है। अटल जी, एक मिनट सुन लीजिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, पहले यह तय हो जाए कि 3 दिन तक गृहमंत्री जी कौन सा कॉरिडोर बनाने के लिए आये थे ? वह आयरन ओर के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए आये थे या बस्तर ओलम्पिक कराने के लिए आये थे ?

श्री अजय चंद्राकर :- आइये, बिल्कुल करते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- वही गुलाब के फूल वाला कॉरिडोर बनाने के लिए आये थे। शायद, आपको याद आ गया होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- बस्तर ओलम्पिक की जगह छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक होता था। मेरे उसमें ढेर सारे प्रश्न हैं। यह खेल मंत्री थे। वह बजट से नहीं होता था। वह अभिसरण से होता था। उसमें अभिसरण में किसके-किसके पैसे लगे, कितने पैसे लगे और कितनी जगहों पर उसका आयोजन हुआ ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला छत्तीसगढ़ के मन ले अतका दुश्मनी काबर हे ? छत्तीसगढ़ के मन हा कबड्डी खेल डारही, छत्तीसगढ़ के मन खो खेल डारही ता ऐला का तकलीफ हे ? तुमन ला छत्तीसगढ़ से अतका नफरत काबर हे ?

श्री अजय चंद्राकर :- मोला कोई तकलीफ नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला छत्तीसगढ़ के बासी से, रोटी से अतका नफरत काबर हे ? छत्तीसगढ़िया मन ला...। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक को बदलकर आपने उसको युवा महोत्सव किया है।

श्री लखेश्वर बघेल :- अजय भैया, सुन लीजिए। मैं आपको प्रत्येक जानकारी दे रहा हूं। ब्लॉक स्तर के टूर्नामेंट के लिए पंचायतों से 10,000-10,000 रूपये की वसूली हुई। फिर आने-जाने का किराया अलग था। सब हुआ। आपके पैसे कहां गये ? यह जांच का विषय है। आप कितने लोगों को अंदर करेंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी युवा महोत्सव हुआ है। इन्होंने महिलाओं के नाम पर बोला है।

श्री लखेश्वर बघेल :- इसी प्रकार जिला स्तर पर, संभाग पर सब में पंचायत से पैसे की वसूली हुई है। क्या आप उसकी जानकारी नहीं लेंगे ? आपने करोड़ों रूपये आबंटित कर दिये हैं तो आपके करोड़ों रूपये कहां गये ? लेकिन पंचायत का खजाना तो खाली हो गया। यदि हिम्मत है तो आप उसकी जांच कराइये।

श्री अजय चंद्राकर :- हो गया। आप बैठिये।

सभापति महोदय :- लखेश्वर जी, आप बैठिये।

श्री लखेश्वर बघेल :- बिल्कुल हो गया। यदि मेरा नाम आएगा तो मैं और जानकारी दूंगा। (हंसी)

सभापति महोदय :- बैठिये लखेश्वर जी, बैठिये।

श्री लखेश्वर बघेल :- मेरा नाम आयेगा तो मैं और जानकारी दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- बैठिये। छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक का आयोजन अभिशरण से होता था, इसका पैसा, उद्योगपति का पैसा, डी.एम.एफ. का पैसा, सी.एस.आर. का पैसा खर्च होता था, लेकिन बजट का पैसा नहीं था। कोई ट्रांसपरेंसी नहीं था। कोई खुलापन नहीं था। छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक पैसा खाने का एक उपक्रम बना था। यह नवजवान लड़का खेल मंत्री था। मैंने एक दिन उनसे पूछा किया छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक की उपलब्धि क्या है ? अरे, 66 साल की एक बुढ़ियां ने, एक वृद्ध माता ने फुगड़ी खेली। यह उपलब्धि थी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तो अजय भईया, अभी तुमन का-का खेल खेलावत हा, तेला त बताव ? गांव का हाकी खेलही ? गांव में क्रिकेट खेलही का ? गांव के मन तो फुगड़ी अउ कबड्डी खेलथे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अभी मार्गदर्शक मण्डल फुगड़ी खेलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एखर कहे के मतलब ये हे माता जी, भाभी जी, एखर कहे के मतलब ये हे कि छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक बजट से नइ होवत रहिस हे। खुलापन नहीं रहिस हे। वो हा पैसा खाय के माध्यम रहिस हे। युवा मितान क्लब के आज तक आडिट नहीं होय हे।

श्री उमेश पटेल :- सुन लीजिये। माननीय सभापति महोदय, 66 साल की उम्र की एक महिला फुगड़ी खेलने में प्रथम स्थान प्राप्त की, इसमें भावना को समझने की आवश्यकता है। भावना क्या था ? उस बुजुर्ग महिला का उत्साह भी इतना देखने को मिला।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधानसभा में उस भावना को कई बार व्यक्त कर चुके हो।

श्री उमेश पटेल :- आप इन चीजों को समझेंगे नहीं। आपमें वह है ही नहीं, संवेदना है ही नहीं।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप आधा घंटा बोल चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधानसभा में उस भावना को कांग्रेस पक्ष दस बार बोल चुके हैं।

श्री उमेश पटेल :- बस, आप यही करते रह गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस, छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक की यही एक उपलब्धि। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप मन ला छत्तीसगढ़ के खेल से नफरत, छत्तीसगढ़ के परम्परा से नफरत, छत्तीसगढ़ के खाना-पीना से नफरत, छत्तीसगढ़ियां आदमी से नफरत, यह सरकार ला छत्तीसगढ के सब चीज से नफरत पैदा हो जाथे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैं आरोप लगाता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के विरोधी हो। छत्तीसगढ़ियां वातावरण के विरोधी हो। मैं आरोप लगाता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों, संस्कृति के विरोधी हो।

एक माननीय सदस्य :- छत्तीसगढ़ के मनखे मन ला लाके क्रिकेट खेलाबे का ?

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। चर्चा हो रही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, अभी पूरे ब्लाक, जिले में युवा महोत्सव हुआ है। उसमें महिलाओं का नाम था लेकिन वहां पर एक भी महिला नहीं थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, ये कुछ भी कर देते थे। कोई गोबर बेचकर कार ले लिया था, हम उसकी भी तस्वीर देखे हैं। एक गाय एक दिन में डेढ़ क्विंटल गोबर देती थी, वह भी रिकार्ड में देखा है। अगर छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक कराकर एक 80 साल की महिला फुगड़ी खेल ली तो हमको कोई ताज्जुब नहीं हुआ।

श्री उमेश पटेल :- ताजुब्ब नहीं, वह सच्चाई है। उसका उददे्श्य यही था। मैं उस समय आपको उत्तर में भी कहा था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मगर फुगड़ी खेल लेने से आपके लड़के जो राजीव मितान क्लब बनाकर माल-टाल खा रहे थे, वह सब खाये थे।

श्री उमेश पटेल :- वह 56 साल की महिला फुगड़ी खेल रही है तो उसके उत्साह का वर्णन करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा विषय क्या है ?

श्री उमेश पटेल :- अभी आपके जो खेल मंत्री हैं, मैं आपको यही बोलता हूं कि आप जांच करा लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- मैं चैलेंज करत हव कि 56 साल के महिला, [xx]

श्रीमती भावना बोहरा :- महिला विधायक ला मत कहबे। नीचे हाथ दिखा के मत बोल। नीचे हाथ दिखा के मत बोल। नीचे हाथ दिखा के महिला विधायक ला मत बोल।

श्री रामकुमार यादव :- 56 साल के महिला मन फुगड़ी कर के मोला दिखा दव।

श्रीमती भावना बोहरा :- महिला विधायक ला हाथ दिखा के बोले के अधिकार सदन मा कोई ला नही हे। महिला मन ला हाथ मत दिखावव। गलत बात हे।

श्री रामकुमारयादव :- 56 साल के महिला फुगड़ी करके दिखा देहा तो मैं मान जाहूं। 56 साल के महिला मन, दिख देव आप मन।

श्रीमती भावना बोहरा :- पूरे सदन में महिला विधायक को हाथ दिखा रहे हैं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप पहले माफी मांगो, आप माफी मांगो। ये क्या हाथ दिखा रहे हो।

श्री रामकुमार यादव :- का चीज के माफी ?

श्रीमती भावना बोहरा :- महिला विधायक को क्यों हाथ दिखा रहे हो ?

श्री रामकुमार यादव :- आप मन छत्तीसगढ़ के महिला के अपमान करा ..(व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी (व्यवधान) माननीय सदस्यगण बैठिये, बैठिये। बैठ जाईये, बैठ जाईये। देखिये, अनुदान मांगों पर महत्वपूर्ण चर्चा है। (व्यवधान)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री रामकुमार यादव :- 70 साल के महिला के अपमान करत हव अउ आप मन ताली बजात हव। महिला के अपमान करत हव।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाईये। सम्माननीय सदस्यगण बैठे। आप लोग बैठिये, सदन को चलने दें। महत्वपूर्ण अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। कृपया विषय पर आये। रामकुमार जी, आप तो बैठिये। आपका समय आयेगा तो आप बोलियेगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, सम्माननीय सदस्य ने यदि किसी बात पर आपत्ति ली है, कृपया उसे गंभीरता से लें ।

सभापति महोदय :- जी, जी । बैठिये, बैठिये । चलिये, अजय जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, किन कारणों से सदन बाधित हुआ, जो टिप्पणी की गई, मेरा आपसे आग्रह है कि उस टिप्पणी को देखकर विलोपित करवाने का कष्ट करें । दूसरा, महिलाओं के लिये कुछ भी बोलते हैं...।

श्री रामकुमार यादव :- मैं तो कुछ बोले नई हंव ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आग्रह कर रहा हूँ । (व्यवधान) मैंने देखवा लें बोला । मैं आगे बोला ही नहीं है ? आप अभी भी कार्यवाही देख लें ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, क्या गलत हुआ है ? (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- इसी सदन में [xx] कहा है, तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप देखव । (व्यवधान) मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने बोला है कि 56 साल की महिला फुगड़ी खेली है, आपके विधायक उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें आपके विधायक लोग ताली बजा रहे हैं और मुझे माफी मांगने बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी । संगीता जी, बैठिये । यदि कोई असंसदीय बात आई होगी तो विलोपित होगी । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कोई बात आई ही नहीं है ? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आपत्ति क्या है यह तो बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दिखवा लेना ना, क्या हुआ है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यहां पर कोई बात हुई ही नहीं है ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- कुछ हुआ ही नहीं है, जबरदस्ती हंगामा क्यों करते हो? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- क्या बात हुई है बताईये ? (व्यवधान) मैं सुनना चाहथंव बताओ ? बताओ ?

सभापति महोदय :- कोई बात नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं है । वह सारे प्रोसिडिंग्स में है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय जी, पहली बात सम्मानीय सदस्य मुझे आदेशित करने वाले कोई नहीं होते कि मैं यहां पर बोलूँ । दूसरी बात, आदरणीय सदस्य जी ने यह कहा कि 56 वर्षीय महिला अगर कोई फुगड़ी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत सम्मान करते हैं । किसी भी खेल में महिला हो, सम्मान करना चाहिये, लेकिन मुझे आपत्ति इस शब्द में है कि आपने जब खड़े होकर बोला कि जो भी आपके विधायक हैं, आपने महिलाओं के साईड क्यों ऊँगली की ।(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(नारे लगाये गये)

एक माननीय सदस्य :- सभापति महोदय, इसके लिये सदन में माफी मांगनी चाहिये ।

श्री रामकुमार यादव :- ऐसा नहीं चलेगा ? मैंने क्या बोला है ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- माफी मांगने का सवाल ही नहीं है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैंने पहले ही कहा है कि कोई बात ऐसी आई होगी तो वह विलोपित होगा और वह प्रोसिडिंग्स में है, वह सब हो जायेगा ।

श्रीमती लता उसेण्डी :- सभापति महोदय, हाथ के इशारों से बात होगी तो विलोपित कैसे होगा ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था आ गई है । ऐसी कोई बात होगी...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- वह हो गया है । बता दिया जायेगा । भावना जी, आप बैठिये ।

श्रीमती भावना बोहरा :- एक मिनट ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए, आपकी बात आ गई है । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यह महत्वपूर्ण चर्चा है । आप सभी लोगों से अनुरोध है, सदन की परम्परा है कि आप आसंदी की तरफ देखकर बात करें, आपस में एक-दूसरे से बात न करें । आसंदी को संबोधित करें । आप सीधे एक-दूसरे को देखकर अपनी बात रखते हैं, यह उचित नहीं है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, मैं इस बात को समाप्त कर दूं क्योंकि माहौल थोड़ा गरम हो गया ।

सभापति महोदय :- अटल जी, आप बैठिए । फिर बात शुरू होगी । अभी उनका विषय है । आपका समय आएगा, तब आप बोलिएगा ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति जी, मैं इस मामले के लिए दो मिनट बोल दूं। आदरणीय अजय जी ने 66 वर्षीय महिला की बात की ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो रोज माफी मांग दूं, दिन भर माफी मांग दूं । हाऊस में यह कोई प्रेस्टिजियश नहीं है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमारी सदस्य भावना जी का बड़ा सम्मान है, पर शायद उनको गलतफहमी हुई है, वे भी रामकुमार जी की ओर ऊंगली दिखाकर बात कर रही थीं । उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए । (व्यवधान) इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसी विषय को आप बार-बार कह रहे हैं । उस पर व्यवस्था आ गई है । अब उसमें कोई बात ही नहीं होना चाहिए ।

श्री रामकुमार यादव :- ये बेमतलब के बोलथे ।

सभापति महोदय :- अटल जी, आप बैठिए । रामकुमार जी, व्यवस्था दे दी गई है । आप शांत रहें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, दो मिनट । अजय भैया के पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, मैं अजय भैया से अनुमति ले रहा हूं, आपसे भी अनुमति ले रहा हूं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, मैंने आपको बात करने की अनुमति नहीं दी है । मैं अजय जी को अनुमति दे रहा हूं । आप अपनी बात रखें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैंने छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का उल्लेख किया तो मेरा आशय बिल्कुल दूसरा था । बजट से पैसा देना और एक उद्देश्यपूर्ण । मैंने पूछा था कि आप छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक करवाते हैं तो उसके लिए बजट कहां है, फंड कहां है । भ्रष्टाचार को नीचे नौजवानों तक पहुंचा दिया गया। मैंने इसी विधान सभा में कहा है, अब फिर बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा इसलिए मैं इस बात को यही तक रोक देता हूं । इसी विधान सभा में मेरे बोलने का रिकार्ड है । उसका उद्देश्य क्या था, उसको ओलम्पिक में मान्यता दिलाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ? आप छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का ओलम्पिक संघ बना रहे हैं क्या, उसको मान्यता देंगे क्या, वह साल में कितनी बार होगा ? चुनाव साल में एक साल में अलग-अलग जगह में तीन बार छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक हो गया । यह विधान सभा के प्रश्न का उत्तर है । आपके और वक्ता आएंगे तो उसका स्पष्टीकरण दे देंगे । कोई समयावधि निर्धारित नहीं है । जिस दिन भूपेश बघेल चाहें, जो भूपेश बघेल जी बोलें, वह कायदा है । कोई कानून नहीं है, स्वेच्छाचारिता के ऊपर कोई बात नहीं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं विष्णु देव सरकार के इस नौजवान मंत्री को बधाई देता हूं कि उनके शहरों को आगे ले जाने के लिए 2 अरब रूपए दिए हैं । अमूमन हम पूंजीगत व्यय के लिए तृतीय-चतुर्थ अनुपूरक में व्यवस्था नहीं करते, खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं । छत्तीसगढ़ में जो नया घट रहा है, उसको महसूस करिए कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में बढ़ने जा रहा है । राष्ट्रीय आजीविका मिशन, गरीबी से लड़ाई का एक संकल्प, 250 करोड़ रूपए हम गरीबी से लड़ाई को मजबूत करने के लिए देंगे । (मेजों की थपथपाहट) हम छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ हैं ।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए गर्व करना चाहिए क्योंकि यह भारत सरकार का मामला नहीं है, यह छत्तीसगढ़ सरकार का मामला नहीं है । माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं । घूमरा रास, मेरा प्रोनाऊन्सेशन गलत हो सकता है । घूमड़ा रास विश्व के मानचित्र पर बस्तर अंकित हुआ । यह किसके प्रयत्नों से अंकित हुआ । (मेजों की थपथपाहट) अब उसमें प्रोत्साहन दूंगा, यह विष्णु देव जी का संकल्प है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अजय जी, आप जिस घूमड़ा रास की बात कर रहे हैं । वह कब हुआ था ? वह हमारी सरकार के समय सामने आया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी सरकार में बहुत कुछ हुआ था, मैं उसमें आ रहा हूं । मैं आपको उसका श्रेय दूंगा । उसके लिए 97 करोड़ रूपए नया आएगा । मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना- सावित्री भाभी जी, आप अनुशंसा दे देना, विजय जी आप नहीं आये हैं । मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं भी 10 साल मंत्री था कि अनुपूरक में इस आईटम में विधायकों की मांग पर, जनता की मांग पर और किसी की मांग पर पैसे दिए जा रहे हैं । यह मैं पहली बार देख रहा हूं । जिस दिन से छत्तीसगढ़ बना है, मैं उस दिन से सदन में हूं । मैंने सभी सरकारों को देखा है । इस नौजवान मंत्री को, इस सरकार के नेतृत्वकर्ता को बधाई देना चाहिए कि तृतीय अनुपूरक में इस आईटम में 50 प्रतिशत से ऊपर 62 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए बजट लाया जा रहा है ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, आप इतना असत्य क्यों बोल रहे हो ? एक बार तो 5 साल नहीं थे ।

सभापति महोदय :- लखमा जी, इनके बाद आपका नम्बर है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी किसी बात पर भाभी जी आपको समर्पित कर देता हूं। लखपति दीदी बनाना है, छत्तीसगढ़ का आजीविका मिशन भी उसमें जुड़ा है कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरागत चीजें हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका बैंक लिंकेज, उसकी मार्केटिंग।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- लखपति दीदी बनावथो कि कंगालपति दीदी बनावथो? अभी बैंकमन लूटथे ते का हे?

श्री अजय चन्द्राकर :- ओखरे बर मोला बइठा देस।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, ये बैंक लूट की जो बात आ रही है, ये कहां से चालू हुआ है? ये चालू हुआ है, कर्ज माफी वाला जुमला आया था, उसके कारण लोग भ्रमजाल में फंसे हैं। कर्जमाफी करने का आपने आश्वासन दिया था।

श्री बालेश्वर साहू :- उन महिलाओं का कर्जमाफ आप लोग भी कर दीजिए। भाई उन लोग तो माईक्रो में लोन लेकर लूटे हैं। आप भी कर्ज माफ कर दीजिए।

सभापति महोदय :- आप लोग आसंदी की तरफ देखकर बात करें। आप एक-दूसरे से बात करते हैं, उचित नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं लक्ष्मण रेखा के समान, आप मुझे देख लीजिए। श्रीमती अनिला भेंडिया जी ने कहा कि लखपति दीदी बना रहे हो या कंगाल दीदी। आपने तो पूरे प्रदेश के रेडी टू ईट वालों को कंगाल करके छोंड़कर चली गईं। (शेम-शेम की आवाज)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप तो रेडी टू ईट वालों को समय पर देने वाले थे, उसका क्या हुआ। आरोप लगाने के अलावा आप लोगों के पास कोई बात नहीं है, असत्य बोलने के अलावा कोई काम नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- मतलब आप स्वीकार कर रही हैं कि आपने किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सहानुभूति की पात्र हैं, आपकी चलती नहीं थी। उस कलकत्ता वाले ने आपसे लेन-देन नहीं किया था। कलकत्ता वाले ने जिससे लेन-देन किया था, हम सबको मालूम है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने नहीं किया।

श्री अजय चन्द्राकर :-आपको कुछ नहीं मिला, इसे मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं आरोप नहीं लगाया। सबसे ज्यादा आरोप मैं ही लगाता था, मैं आपके ऊपर कभी आरोप नहीं लगाया, क्योंकि कलकत्ता वाले ने आपको कुछ नहीं दिया, यह मैं जानता हूं।

श्री बालेश्वर साहू :- मेफेयर का आपको मिला है या नहीं मिला है?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो आप 100 करोड़ रुपए समग्र विकास के लिए आया है, उसमें अनुशंसा दे दीजिएगा। विजय जी आयेंगे तो उसमें आग्रह करेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मेरे जिले में आपने पूरा भाजपा कार्यकर्ताओं को दे दिया है। पूछ लो हम तीनों विधायक बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- राजीव मितान में किसको पैसा दे रहे थे?

श्री रामकुमार यादव :- विधायक के फंड ला भी काटने वाला हे।(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आपके अधिकारी ये बोलते हैं कि कांग्रेस के पार्षद हो ना, तो तुम्हारे वार्ड में एक पैसा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वहां स्थिति ये है कि हमारे विधायक निधि का पैसा काट रहे हैं तो क्या समग्र का पैसा दे देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उमेश पटेल जी, हमारे अधिकारी क्या बोलते हैं, उसे बाद में बतायेंगे। मैं वहीं बैठता था और मंडी बोर्ड के लिए कागज लाकर यहां ऐसा दिया था, जब आदरणीय यहां बैठे थे तो ऐसा उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं मंडी बोर्ड की बात कह रहा हूं। ये होता है, चलता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पिछली बार कागज में फिल्म विकास निगम बन गया। मैं दो उदाहरण दे देता हूं, साथ में विनियोग में भी बोल देता हूं। भारत सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने 147 करोड़ रुपए दिए और उसके लिए बजट आयोजन नए मद में किया, तो इस नौजवान मंत्री ने किया, इस विष्णुदेव के शासन ने किया। यह आदिवासी बाहुल्य राज्य है, ट्राईबल कन्वेंशन सेंटर की परिकल्पना की गई। आपको किसने मना किया था, बैठे हैं। एक चिन्तन को देखिए। तो यह बजट ऐतिहासिक है, छोटा

आकार में होने के बावजूद 62 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए पूरे देश को एक नई दिशा दिखा रहा है। पूरे सदन को इस नौजवान मंत्री को बधाई देना चाहिए। अब बजट के साथ-साथ कुछ दूसरे विषय हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी आ रही है। गुमराराज जैसे कई गांव पनपेंगे। नियद नेल्लानार होगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने फिल्म सिटी की बात की तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में फिल्म सिटी की सिर्फ घोषणा करते रह गये लेकिन एक पैसा नहीं दे पाये। इन्होंने बोला कि फिल्म सिटी बनायेंगे, फिल्म विकास निगम को एक्टिव करेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाये। फुल लबारी, फुल लबरा सरकार रिहीसे।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तोहर फिल्म हमन देखे हन। अउ ओती गुण गात हवव।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अब कानून व्यवस्था में इधर-उधर की बात। (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- सभापति महोदय, अभी डबल इंजन के सरकार हे। साय-साय काम होवत हे गा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बस्तर से हमारा नेतृत्व आता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस सदन में है (मेजों की थपथपाहट)। संसदीय कार्य मंत्री भी बस्तर से आते हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो नक्सलियों ने कैसे उपस्थिति दिखाई ? सड़क के ऊपर गीदम के थाने को लूटा गया और यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अजीत जोगी जिंदाबाद। अब क्या स्थिति है ? एक साल में 230।

श्री लखेश्वर बघेल :- आप कौन सी बात कर रहे हैं। आप 24 साल की बात कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इनके कार्यकाल में झीरम घाटी कांड हुआ था। आपके शासन काल में झीरम घाटी कांड हुआ था।

श्री लखेश्वर बघेल :- 15 साल में क्या-क्या हुआ, आप उसको भी बता दीजिये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- एक साल में 230 लोग मारे गये। वह जानते नहीं थे कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इन्हीं के शासनकाल में झीरम घाटी कांड हुआ था। हमारे आदरणीय लोग यहां है, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, 15 साल में क्या-क्या हुआ, उसे बता दीजिये ? कितने जवान मारे गये, उसको बता दीजिये ? कहां-कहां लूटा गया, उसको बता दीजिये। कितने गांव उजड़ गये, उसको बता दीजिये ?

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति को, विष्णु देव सरकार की पुनर्वास नीति को सबसे अच्छी पुनर्वास नीति कहा (मेजों की थपथपाहट)। यह सबसे अच्छी पुनर्वास नीति है। पहली बार उस शांत इलाके में मेरा सबसे अच्छा गांव नियद नेल्लार है। उसमें 96 गांव है। जो अपने विधान सभा क्षेत्र में कभी नहीं जाते, उनको वहां जाना चाहिए, जो डर के कारण रायपुर में रहते हैं। यह बस्तर की बात करते हैं और रायपुर में रहते है। यह क्या बोलते थे ? हमने इतने स्कूल खोल दिये। आपने कितने स्कूल खोले और उसमें पढ़ाने वाले कितने लोग थे ?

श्री कवासी लखमा :- असत्य बोल रहे हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, वह स्कूल हमारे समय में खुले थे। अभी आपके कार्यकाल में कौन से स्कूल खुले हैं, बताईये ? वह सब स्कूल पिछले वर्ष खुले हैं। आप नियद नेल्लार की बात करते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, इनके मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं। उनसे पूछिये कि क्या वह हमारे जवानों के कैम्प में एक रात भी बिताये हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मैंने इसी सदन में बोला कि निवेश घोटाला हुआ है। लोहा वालों को बुला लिया गया कि इस-इस तरह की इतनी छूट दी जायेगी, आप ऐसा-ऐसा करिये। उस एग्रीमेंट में एक भी काम अभी तक शुरू नहीं हुए। मैं अभी जब तक बोल रहा हूं, तब तक एक भी काम शुरू नहीं हुआ। बिना हल्ला के, बिना एक्सटॉर्शन के कार्य नहीं हुए। भूपेश बघेल मतलब एक्सटॉर्शन की सरकार, वसूली की सरकार। कोई काम बिना एक्सटॉर्शन के होता नहीं था और यह हमको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। यह चुपचाप बिना कुछ बोले अलग-अलग क्षेत्रों में ए.आई. में, आई.टी. में, डाटा सेंटर में, एथेनॉल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्रेस बायो गैस में छोटा सा 35 हजार करोड़ रूपये का कार्य किये, लेकिन विविध क्षेत्रों में कार्य हुए हैं, विविध विषयों में कार्य हुए हैं। ए.आई. तो उनका विषय ही नहीं था। ए.आई. जैसे नये विषय को लायेंगे, नयी-नयी टेक्नोलॉजी को लायेंगे तो उसमें एंट्री कहां से मिलेगी। जिसमें एंट्री मिलेगी, उसमें निवेश होगा। बिना एंट्री के निवेश नहीं होगा, यह सूत्र वाक्य था। उसमें ऐसा हुआ कि आज तक उसमें कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष निवेश नहीं हुआ न ही एक रोजगार हुआ। 18 लाख आवास इसलिए नहीं बने क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था। वह आवास किसको मिलता ? वह बस्तर के गरीबों को मिलता, कुनकुरी के गरीबों को मिलता, सरगुजा के गरीबों को मिलता या मैदानी क्षेत्रों के गरीबों को मिलता। आपने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया, आपकी संवेदना इसीलिए मर गई कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, उसमें भाजपा लाभ ले जायेगी, हमारा स्टेट शेयर है। गरीबों के साथ पीड़ा शेयर करने की आपकी क्षमता नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया। जितना भारत सरकार ने स्वीकृत किया, उसकी कंपोनेंट की

राशि छत्तीसगढ़ ने दे दी। अब पांच साल चुप बैठने वाले लोग प्रश्न करते रहे। एक किस्त मिली, दो किस्त मिली, आधी किस्त मिला, पौन किस्त मिली, हमने शुरूआत कर दी। हम जिस दिन जनता के पास मेंडेट लेने जायेंगे, उस दिन हम बोल देंगे कि हमने 18 लाख आवास बनाये हैं। हमने जो कहा था वह किया है (मेजों की थपथपाहट)। विष्णु देव साय जी की सरकार ने जो कहा, वह किया है। आप इंतजार कीजिये यह पहला साल है।

समय
4.00 बजे

श्री रामकुमार यादव :- अउ रेट ला कोन दीही। फ्री में। ओकर बारे में कोन बोलहि।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अच्छा अभी यह 18 लाख की संख्या में कितनी स्वीकृति हुई है ? और उसके पहले की स्वीकृति कितनी है ? आपको नहीं पता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अभी यह 18 लाख की स्वीकृति कब हुई है ?

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय उमेश जी, इसका जवाब दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, एक मिनट।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी, आप उधर से ईज़ाजत ले लेते हैं।(हंसी) यह सदन की परम्परा रही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, एक सेकण्ड के लिए ईज़ाजत चाहता हूँ। इसमें एक जो समस्या आ रही है वह जेनुअन है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभी पैसा मिल रहा है जो इन्फ्लेशन बढ़ा है। उससे गरीबों को दिक्कत हो रही है। इसमें शायद हमको बजट में और उनको पैसा देने की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भी यह निवेदन करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो शायद सबका घर बराबर बन जाएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय,एक निवेदन है।

सभापति महोदय :- आप बाद में बोलिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय,एक लाख नौकरी देने की बात भी थी और 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देने का वायदा था, आप उसको भी दीजिए।

श्री सुशान्त शुक्ला :- 5 सालों तक कुछ नहीं बोला और जिन्होंने बोला, आज वह सत्ता से बाहर हैं।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, आप ला समझ गेन। तुमन ला छत्तीसगढ़ के हीरो समझे रेहेन। अइसना मत पूछव। आप ठग के जीत गेव।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और दीर्घा में वित्त सचिव जी मौजूद हैं। केबिन में हमारे इसी परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद है उसका परिक्षण अवश्य करेंगे। इतनी संवेदनशीलता तो है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पुनर्वास नीति के बारे में कहा कि पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों लोगों को 15 हजार प्रधानमंत्री आवास देंगे। यह एक बड़ा कदम है। मैं नियद नेल्ला नार की बात कह रहा था। अब माननीय वित्त मंत्री जी 5 साल का बता देता हूं। यह सरकार सुन रही है आपके राज में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रिमण्डल को बधाई देता हूँ कि यहां ए.सी.बी. लगातार एक्टिव है। यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिख रहा है। (मेजों की थपथपाहट) अब जब यह हमको आईना दिखा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। इन 5 सालों में ए.सी.बी. ने कितना चालान पेश किया ? आप बता सकते हैं ? यहां बुलाकर बता दें। मैं उनके सामने बोलूंगा कि यहां पर कितना चालान पेश हुआ। यदि किसी की शिकायत हुई तो ए.सी.बी. से फोन जाता था कि आप आईये और सेटल कर लीजिए। अगर इन 5 सालों में एक भी चालान पेश हुआ। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई थी। (शेम-शेम की आवाज)

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा बात तो बोलूंगा नहीं। यह तृतीय अनुपूरक पर चर्चा हो रही है। माननीय उमेश जी को एक छोटा सा उदाहरण कल का ही बता देता हूँ। वह पहले वक्ता थे। पूर्व में गोबर पेंट अनिवार्य किया गया। सरकारी भवन गोबर पेंट से पोते जाएंगे। यहां पर 17 करोड़ 40 लाख रूपये के गोबर पेंट खरीदे गये। आप लोग मद को कल के परिशिष्ट में पढ़ लीजिए। उसका कोई रेट निर्धारण नहीं हुआ। उसे कौन-कौन से रेट में खरीदा या नहीं खरीदा, यह भी किसी को नहीं मालूम था। मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ साहब, यह 17 करोड़ रूपये जनता के लोक धन की लूट है, आप इसे भ्रष्टाचार भी कह लें। (मेजों की थपथपाहट) जिसका दर नहीं था, जिसके रेट फिक्स नहीं थे। उस समय 17 करोड़ रूपये के पेंट खरीद लिये गये। उधर बैठे लोग हों, चाहें इधर बैठे लोग हों। इस खुली लूट में रोक लगनी चाहिए। हमने ऐसा भ्रष्टाचार जीवन में नहीं देखा। इसमें अतारांकित प्रश्न लगा था मैं फिर उस पर प्रश्न लगाऊंगा। लेकिन जो इनके विषय हैं जब तक परिणाम नहीं निकलेगा, मैं उसके पीछे दौड़ते ही रहूंगा। अभी माननीय डिप्टी सी.एम. साहब, मैं इस मोशन पर बोल नहीं रहा था। मैंने उनको कह कि आज मैं इस पर बोलूंगा। एक बात स्पष्ट है अरूण साव भ्रष्ट है। अच्छा। भारत सरकार का छत्तीसगढ़ का वेबसाईट देख लीजिए। वर्ष 2023-24 में 5 हजार करोड़ रूपये जल जीवन मिशन में व्यय करने वाली सरकार है तो भूपेश बघेल की सरकार है। आप पैसे खर्च करिये। हमें पानी से मतलब नहीं है। आप लाईये, दीजिए। माननीय वित्त मंत्री जी, हम लोग बचपन में प्रतिभा के पलायन में निबंध लिखते थे कि यहां से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ में 5 सालों में धन का पलायन हुआ हुआ। धन का पलायन हुआ छत्तीसगढ़ का धन कांग्रेस के कोष में दिल्ली में गया। कांग्रेस पार्टी उसी से

चलती रही । छत्तीसगढ़ में ए.टी.एम. की सरकार थी और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ ने 05 साल में भ्रष्टाचार के रूप में देखा और भुगता। और विकास कार्य एक उदाहरण हैं। गोबर पेंट इसी सत्र का मैं बोल रहा हूं, पिछले सत्र का नहीं बोल रहा हूं। जल जीवन मिशन उसका उदाहरण है कि आपके भ्रष्टाचार के ये स्मारक हैं। इसको छत्तीसगढ़ की पीढ़ी देखेगी। सभापति महोदय, इसी सत्र की ही बात कर रहा हूं। खेल मंत्री बैठे हैं, मैं इनका प्रशंसक आदमी हूं और सद्भावना भी रखता हूं क्योंकि इनके पिताजी से दूसरे संबंध थे। पर इनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी बनाई। मैंने वेंगसरकर की, प्रकाश पादुकोण की अकादमी बंगलौर में देखी है। रहने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी, क्या सेटअप होगा, कोई मंजूर नहीं है। जैसे जोगी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का एलाउंस कर दिया, उसको पूरा कौन करायेगा? भाजपा की सरकार आयेगी, वह पूरा करायेगी। रायपुर में जाकर मुख्यमंत्री जी ने नारियल फोड़ दिया। अकादमी बन गई है। अब 23 करोड़ रुपये का आपसे पास रिवाइज के लिए फिर प्रस्ताव आ रहा है कि इसको पूरा करना है। उसके बाद उसका सेटअप बनायेंगे। क्यों छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ ऐसा छल करते हो?

सभापति महोदय :- अजय जी, संक्षेप करिये, बहुत लोगों को बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, दो-चार मिनट में खत्म करता हूं। आप लॉ एण्ड आर्डर की बात कर रहे थे। मैंने नक्सली भर को स्पर्श किया है। कवर्धा की बात हो रही थी। जब से मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानता हूं, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिकता नहीं फैली। जैसे बोल रहे थे न बलौदाबाजार, क्या करने गई थीं ? कविता प्राण लहरे जी कहां गईं ? वहां शिव डहरिया जी क्या करने गये थे ? वह तो किसी समाज का कार्यक्रम था।

श्री उमेश पटेल :- वह नहीं गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, दूसरा नाम दे देता हूं।

श्री विक्रम मंडावी :- समाज ने बुलाया था, इसलिए गये थे। क्या समाज वाले बुलायेंगे तो नहीं जायेंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, कविता प्राण लहरे जी उस समाज की हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम उसेंडी :- सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप उस समाज के लिए नहीं बोल सकते। कविता प्राण लहरे जी इसी समाज की हैं। .. (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- जबदस्ती सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए गये थे। (व्यवधान) क्योंकि वह लोग गये थे, वह लोग समाज को बदनाम किये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- क्या आप उनका वीडियो देखो हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोला हूं कि सद्भावना रखता हूं।

श्री उमेश पटेल :- क्या आप वीडियो देखें हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सब देखा हूं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सब जानकारी है, वह गये थे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- पूरा कांग्रेस पार्टी के लोग ही वहां दंगा कराये हैं। (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी ने सतनामी समाज को बदनाम किया है। असली अपराधी वही है। कांग्रेस पार्टी ने सतनामी समाज को लड़ाने का काम किया है और आपका एक विधायक आज जेल में भी है। (व्यवधान) उत्पात मचाने वाला कांग्रेस का विधायक जेल में है। जिसने सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया। (व्यवधान) सतनामी समाज अहिंसा का पुजारी है, उसका बदनाम करने के लिए आपके विधायक गये थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग स्थान ग्रहण करें।

श्री उमेश पटेल :- भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलौदाबाजार में करवाया है। आपने लोगों को भड़काया है। (व्यवधान)

(सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि कृपया बैठें । अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है । आप बैठिये । अब वे बात को समाप्त करेंगे ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठ जाईये । उमेश जी बोल रहे हैं । आप बैठिये, रामकुमार जी बैठिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, पुलिस जांच कर रही है । पुलिस की जांच में कविता प्राणलहरे जो हमारी विधायक हैं, उनके वीडियो को भी देखा गया, उसमें वह कह रही हैं कि किसी को कुछ नहीं करना है, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करना है ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, [xx] जाकर वहां समाज को बदनाम करने का काम किया गया है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए न । खुशवंत जी बैठिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, कृपया इनको सुनने के लिये बोलिये । यदि हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो सुनना तो चाहिए । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप समाज के आदमी को [xx] बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आप समाज के लोगों को [xx] कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप कैसे समाज के आदमी को [xx] बोल रहे हैं और खुद वहां के विधायक हैं । आप उनको [xx] बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिये । उमेश जी बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जब पुलिस जांच कर रही है । कविता प्राणलहरे के खिलाफ पुलिस में कुछ नहीं मिला, उनका वह वीडियो वॉयरल है जिसमें वह बोल रही हैं कि इस तरह का काम नहीं करना है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जब पुलिस जांच कर रही है । यह बिल्कुल गलत बात है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये न । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि ये बार-बार टोका न करें । मैं पाइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रहा हूं । (व्यवधान) पहले थोड़ी जानकारी ले लीजिये । जब पुलिस की जांच में अभी तक उनके खिलाफ कुछ आया नहीं है, कविता प्राण लहरे जी वहां की विधायक हैं, उस क्षेत्र की विधायक हैं और उस क्षेत्र की विधायक होने के नाते उन्हें जब किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो वह जाती हैं । उसको इस तरह से प्रस्तुत करना कि क्यों गये थे । इस आशय से प्रस्तुत करना कि वह इसी कारण से गये थे यह गलत है । (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, ये सफाई क्यों दे रहे हैं?

सभापति महोदय :- खुशवंत जी आप बैठिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी सदस्य जो इस विधानसभा का सदस्य है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक । मैं दूसरे आशय से, दूसरे तरीके से बोल देता हूं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- जब तक उस पर आरोप साबित नहीं होता है तब तक न बोलें । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं दूसरे तरीके से बोल देता हूं न ।

श्री उमेश पटेल :- मैं तो माननीय सभापति महोदय जी से व्यवस्था मांग रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे व्यवस्था मांग रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- उस भाषण में...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे भाषण में क्या व्यवस्था का प्रश्न होगा ? (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- आपने बोला है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उन्होंने यह कहा है कि कविता प्राणलहरे क्यों गयी थीं ? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- कविता प्राणलहरे के खिलाफ बात कही । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उन्होंने यह कहा है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- क्यों गयी थीं ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, चलिये मैं दूसरे तरीके से बोल देता हूं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इन्होंने आरोप लगाया है कि क्यों गयीं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, चलिये मैं दूसरे तरीके से बोल देता हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये । अभी बैठिये । वे कुछ बोल रहे हैं, अपने शब्दों को वापस ले रहे हैं, वे दूसरी बात बोल रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपका निर्देश है । मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं । मेरे सहित मेरे दल के, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोल सकता सभी लोग चिंतित हैं कि माननीय देवेंद्र यादव जी कहां हैं ? कहां हैं और क्यों हैं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपकी सरकार ने ही उनको गलत ढंग से भेजा है

श्री अजय चंद्राकर :- अरे भई, अभी तो मैंने कुछ आरोप नहीं लगाया, केवल कारण बताया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं । आपके आरोप के पहले ही मैंने स्पष्ट बोल दिया ।

समय :
4.13 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात कि सूरजपुर के जो आरोपी थे उसकी फोटो किसके साथ थी ? उसकी फोटो किसके साथ थी ? तो कहीं ना कहीं क्यों गए थे ? किसलिए गए थे ? चलिए माननीय उमेश जी को वह अतिरिक्त लगा तो कहीं ना कहीं Congress से जुड़े लोगों का इस तरह की घटनाओं में तार दिख रहा है जैसे...।

श्री विक्रम मण्डावी :- अजय भैया, कवर्धा केस में एक आरोपी की फोटो माननीय गृहमंत्री जी के भी साथ था उसमें आप क्या बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, गृहमंत्री जी के साथ फोटो थी। जो मर्डर का केस हुआ था । (व्यवधान) पुलिस के दो बच्चों का मर्डर हुआ था उनकी फोटो गृहमंत्री जी के साथ था । (व्यवधान) अगर फोटो से संबंध है तो आप उसको भी जोड़िए । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- हां, आप उसको भी बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । अजय जी, आपने अपराह्न 3.24 बजे से प्रारंभ किया था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल रहा हूं कि मैं जल्दी समाप्त करूंगा । मैं समाप्त कर देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं घड़ी देख रहा हूं । आपने बहुत अच्छा बोला है लेकिन कृपया समाप्त करें । काफी सदस्य बोलने वाले हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- जी । ये इंटरप्शन न करें तो मैं दो मिनट में समाप्त कर देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप दो मिनट में समाप्त कर लीजिये । चलिये, अब डिस्टर्ब न करें ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, ये हमको बाहर देखकर हमारे सदस्यों को डराते भी गये हैं और धमकाते भी गये हैं । (हंसी) इनको जरा...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं । कोई सदस्य को, किसी को नहीं डराया जा सकता है, यह विधानसभा का परिसर है, यहां आप चिंता मत करिये । (मेजों की थपथपाहट) आप अध्यक्ष के संरक्षण में और विपक्ष को ज्यादा संरक्षण मिलता है। आप चिंता मत करें। मगर आप समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, थोड़ी देर में कर रहा हूं। आपका आदेश शिरोधार्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में अभी संसद भी चल रही है और एक हफ्ते तक संसद एक आदमी के नाम पर इसलिए नहीं चली, पूरा नाम पर नहीं, एक सरनेम पर अडानी। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो अमेरिकी अदालत जो है न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है और माननीय वित्त मंत्री जी, उसके बाद सारे पेपर में छपा है कि उस दौरान जो लेन-देन हुआ, वह दिल्ली जाने अंतर्राष्ट्रीय मामलों का क्या हुआ? पर एक लाइन आया है कि वह लेन-देन छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और वह छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय में हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) किस मंत्री, किस अधिकारी ने उस घूस को खाया है? छत्तीसगढ़ की जनता उसको जानना चाहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपे, राष्ट्रीय स्तर पर छपे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसी परिप्रेक्ष्य में परसा कोयला खदान, जिसमें आदिवासियों ने 300 मीटर पद यात्रा की थी, उसको खोलने की वन अनुमति 6 अप्रैल, 2022 को आपकी सरकार ने दिया था और जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत ही परसा खदान चलाने की अनुमति आपने जारी की।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दो लाइन बोलकर खत्म कर रहा हूं। मेरे खत्म होने के बाद बोल दीजिएगा, मेरा समय कट जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- जो रिफरेंस अजय जी ने कहा है कि उसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी आ रहा है। चार अलग-अलग प्रदेशों का नाम आ रहा है और इनके नेता ये बोलते हैं कि हमारी तो वहां सरकार ही नहीं थी, वह बाकी लोगों की सरकार थी। तो ये इनकी केंद्र सरकार जांच से भाग क्यों रही है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय वित्त मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के किस नेता, किस अधिकारी ने घूस खाई है? इसकी जांच तो आप करवाइए। अब चूंकि मैं विनियोग पर बात कर रहा था और माननीय अध्यक्ष महोदय जी की बात हो गयी। मैं दो बात बोलता हूं, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। ये पुलिस विभाग ने इनके समय में 400 बोलेरो खरीदे हैं। धूल खा रहे हैं। टायर सड़ गई हैं। तो 400 बोलेरो जो खरीदे हैं और उपयोग नहीं किए, कितना कमिशन खाये हैं ये राष्ट्रीय न्यूज पेपर में अंग्रेजी, हिंदी सबके राष्ट्रीय पोर्टल में सब में छपे और फोटो समेत छपे। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इसकी जांच करवाएंगे। दूसरा एक हमारे समय का है। ये भी राष्ट्रीय स्तर में छपा न, मैं आपको बता देता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- आप अध्यक्ष जी को देखकर बोलिए भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाप रे, रामकुमार जी बड़े संसदविज्ञ हो गए हैं, ठीक है।

श्री रामकुमार यादव :- हां, महू धीरे-धीरे तुम्हरे गुण ला पाथौं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिलासपुर में गरीब से लोन दिलवाने के लिए 39 मुर्गा एक बैंक मैनेजर ने खा दिया । उसको तो जिन्दा मुर्दा पकड़ के लाइए उसको 139 मुर्गा हम अपने पैसे से खिलाएंगे । कौन है उसको? विष्णु देव के शासन में ये गतिविधियों नहीं चल सकतीं। ये भी जो समाचार है कोई लोकल समाचार से नहीं बता रहा हूं, यह मैं आपको आज तक और ए.बी.पी. जैसे न्यूज चैनल हैं, उसमें चले कि 39 मुर्गा गरीब को लोन दिलाने के लिए बैंक मैनेजर ने खाया। उसको जिन्दा मुर्दा पकड़ के लाइए, उसको 139 मुर्गा हम खिलाएंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको बुलाइए और एक 26,000 के टमाटर पर 28,000 का पेनाल्टी आर.टी.ओ. ने लगाया है। जरा उसे भी बुलाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये किस तरह की गतिविधियां हैं, जब आप जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब तो भूमिका है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय विष्णुदेव जी को बधाई देता हूं कि ऐतिहासिक अनुपूरक बजट जिसमें 62 प्रतिशत पूंजीगत व्यय का प्रावधान है और जिसमें आपने नए आइटम लिए हैं। अभी तक हम समझते थे कि साहब ये प्रतिपूर्ति के लिए बजट आता है, आपने एक मापदंड स्थापित किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने समय दिया उसके लिए, मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कवासी लखमा जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एकमुश्त राशि के लिए इसमें कुछ है तो चन्द्राकर जी बता दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- देखिए कवासी जी अपना भाषण शुरू कर रहे हैं। इनको डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- नहीं करना भाई। आज हमारे अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया, उसका पालन सबको करना है। (हंसी) आपको भी करना है इधर मत आना। मैं अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सबसे ज्यादा किसी को ठगा है तो किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, बच्चों को ठगा है । छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो 2500 रूपए में धान खरीदी के कारण पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम हुआ था । (श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा श्री कवासी लखमा, सदस्य के आसन के सामने से गुजरने पर) अध्यक्ष जी, इनको डांटिये, ये आपकी बात भी नहीं सुनते, इसीलिए तो मोदी जी ने मंत्री नहीं बनाया । मेरी बात मानो तभी बनोगे । अध्यक्ष महोदय, हमने घोषणा की थी कि 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे । जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे तो अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि किसान इतना धान कहां से लाएंगे, क्या चोरी करके लाएंगे ? इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो 20 क्विंटल धान होता ही नहीं है । बाद में इनके आका ने 21 क्विंटल की घोषणा की तो ये चुप हो गए । इन्होंने विधान सभा में बोला था और पूरे छत्तीसगढ़ के अखबारों में छपा था कि 20 क्विंटल धान छत्तीसगढ़ में नहीं होगा । इसलिए इनकी बात पर भरोसा कम करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर फड़ में प्रतिदिन 1800 से 2000 बोरा खरीदी होती थी । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कटौती करके 1000 बोरा खरीदी करने को कहा और वह भी 15 जनवरी तक । मैं पूरी मंडियों में घूमा हूं, सबने बताया । हमारे समय में हमने कहा था कि मंडियों में 2000 क्विंटल पहुंचेगा तो उठाव करना है क्योंकि मंडी छोटी-छोटी हैं, ग्राम पंचायतों के पास ज्यादा जमीनें नहीं हैं । जैसे ही 2000 क्विंटल होगा तो मिल में पहुंचाना है । आज शासन का आदेश है, माननीय पढ़े लिखे शासन के मंत्री हैं वे अपने जवाब में बताएंगे कि आदेश है या नहीं है । पहले 2000 क्विंटल में उठाव करना था, लेकिन अब 4000 क्विंटल में करना है । सोसायटियां पैक हो चुकी हैं । बस्तर में अभी तक एक क्विंटल भी ढुलाई नहीं हुई है और धीरे-धीरे धान खरीदी बंद हो रही है । किसानों ने इतनी मेहनत से धान लगाया था, मेहनत की थी यह सरकार उस पर पानी फेरने का काम कर रही है । उसके बाद लाडली बहन योजना में कहा कि सब महिलाओं को देंगे । जो जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको देंगे, बिना शादी वाली महिलाओं को नहीं देना है, हम भी नहीं मांगेंगे । लेकिन उसमें भी 100 में से 25 महिलाओं को मिल रहा है, 75 महिलाओं को नहीं मिल रहा है, इसमें भी ठग दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारे बस्तर में हॉस्टल, आश्रम हैं । जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं और अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इनकी शुरूआत हुई थी । बस्तर में हॉस्टल, आश्रम की व्यवस्था, पोटा केबिन, मनमोहन

सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में पोटा केबिन बने, आप मुख्यमंत्री थे । सरगुजा और बस्तर के कांकेर में पोटा केबिन नहीं है । दक्षिण बस्तर में पोटा केबिन है, पिछड़ा एरिया है, नक्सली क्षेत्र है, अंदर के बच्चे आए 100-100 सीटों का आश्रम, 500-500 पोटा केबिन में । वो पोटा केबिन बर्बाद होता जा रहा है । कल ही की घटना है छिंदगढ़ थाना से, तहसील मुख्यालय से और एस.डी.एम. ऑफिस से पांच किलोमीटर दूर है । वहां की अधीक्षक प्रभावशाली बीजेपी नेता की पत्नी है । वह, वहां खाना नहीं दे रही है, वहां जाती नहीं है । घर में रहकर 500 बच्चों का आश्रम चला रही है । कल सुबह प्रार्थना में दूसरी पढ़ने वाला बच्चा गिरकर खत्म हो गया । उन्होंने असत्य बोला कि हॉस्पीटल में खत्म हुआ, वह आश्रम के अंदर खत्म हुआ । वहां पर वीडियो चल रहा है, प्रभारी मंत्री को हर बच्चे को देना है, उपर पहुंचाना है, 50-50 रूपये दें। लोहण्डीगुड़ा में, नारायणपुर में, बीजापुर में बच्चे लोगों को खाना कहां से खिलाएंगे ? हमारी सरकार थी तो हॉस्टल आश्रम में 1500 रूपये मिलता था, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि 2000 कर दीजिए। हम लोगों ने 2000 देने की व्यवस्था की। पोस्ट मैट्रिक में 700 रूपये मिलता था, पिछली सरकार ने उसको 1200 कर दिया। इन सरकार ने आश्रम हॉस्टल के लिए एक रूपया नहीं बढ़ाया है। उसको भी डाका डालने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लखेश्वर बघेल जी ने एक विषय उठाया था, वहां पर जब-जब सरकार बदली है, यहां कोई मंत्री नहीं हैं, दो ही मंत्री बैठे हैं, जब-जब चावल बंट रहा है, कभी 20 क्विंटल कम, कभी 10 क्विंटल कम बंट रहा है, वहां वहां मारा पीटा हो रहा है, चेयरमेन को पीट रहे हैं। वह काट-काट के दे रहा है। वहां क्या हो गया ? वहां 15 साल से ऐसा नहीं हुआ, हमारी सरकार 5 साल थी तो नहीं हुआ, ये विष्णुदेव सरकार में क्या हो गया ? पूरे देश में चर्चा है। छत्तीसगढ़ में चर्चा है। यहां किसका चलता है ? विष्णुदेव का चलता है, वित्त मंत्री का चलता है, न दो-दो उप मुख्यमंत्री का चलता है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये बी.जे.पी. के लोग भी नहीं बोलेंगे, हमारी सरकार में किसका चल रहा है। उपर से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है, पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, मैंने एक एप्लीकेशन ट्रांसफर के लिए सी.एम. साहब के यहां दिया, वह काम नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए भी दिल से बधाई दूंगा कि कुछ लोग बोले तो मुख्यमंत्री को दिया, आंगनबाड़ी का काम था, विधान सभा अध्यक्ष के पास जाओ तभी काम होगा। मैंने इसलिए आपको बधाई दी, मैंने आपको घर जाकर कागज दी, वह काम हुआ। मुख्यमंत्री के पास तो फूटी कौड़ी का काम नहीं होगा। चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यह कैसी सरकार है ? सरकार कौन चला रही है ? यहां पर हर दिन चक्कूबाजी, गुंडागर्दी हो रही है। हमारे बस्तर में सलवा जुडूम के जमाने में वहां रोज मर्डर होता था, बस्तर खून में नहाता था। उसी प्रकार रायपुर राजधानी में मुख्यमंत्री डी.जी., डी.जी.पी., रहते हैं, रायपुर में रहने के लिए लोगों को डर लग रहा है। बस स्टैंड में बलात्कार हो रहा है। यह क्या हो गया ? सीधा सादा छत्तीसगढ़ है। हम लोग सरगुजा में सुनते हैं, किसी भी प्रदेश में जहां आदिवासी बच्चे हों, पढ़ने वाला बच्चा हो, बस में चलने वाले लोग

सुरक्षित नहीं हैं। यह क्या हो गया? इसलिए अभी हमारे यहां चना मिलता है, हमारे समय में गुड़ मिलता था। अभी तीन-चार महीना हो रहा है, चना भी बंद हो गया, अभी बस्तर में किस्टाराम गया था, वहां के लोग बोल रहे थे, दो महीने के बाद गेंहू आएगा। बस्तर के आदिवासी गेहूं खाएंगे ? रोटी बनाना तो जानते नहीं हैं तो गेहूं कैसे खाएंगे। वहां गोदमा बोलते हैं, बस्तर के लोग भी दूसरी भाषा में गोदमा आएगा बोल रहे थे। हम लोग गेहूं को गोदमा बोलते हैं। यह भी प्लान चल रहा है, यह बस्तर में नहीं चलेगा। यह मध्य छत्तीसगढ़ में चलेगा लेकिन बस्तर में इस तरह से थोपने का काम नहीं करना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी टी.व्ही. में जाते हैं, चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं, नियद नेल्लानार, नियद नेल्लानार मतलब अजय चंद्राकर को आता नहीं होगा, हिंदी में नियद नेल्लानार मतलब अच्छा बांध बनाएंगे। इसमें अच्छा काम होगा। एक भी गांव जगरगुण्डा से पूर्ववर्ती से ज्यादा नक्सली तो है नहीं। किसी भी गांव में नियद नेल्लानार बनाने के लिए एक करोड़ रूपये दिया हो, सी.सी रोड बना हो, आंगनबाड़ी बना हो, हॉस्पिटल बना हो, मैं भूपेश बघेल को बधाई देता हूं कि झगरकोण्डा में 30 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। वह उनके समय से घोषित हुआ है। वहां हम लोग छोटा-छोटा तासीर झगरकोण्डा।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, एक मिनट। पर्यटन केन्द्र ढोर्रा भी है न ? जैसे जगदलपुर का घुमड़ारास छठवें गांव में आया है।

श्री कवासी लखमा :- नहीं है। छठवें गांव में आया है। हमारी सरकार में बांस के डोंगा से। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, आपके समय में ढोर्रा भी ताश-जुआं के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह अंतर्राष्ट्रीय स्थल था। देशभर के लिए वहां जुआं खेलने के लिए आते थे।

श्री कवासी लखमा :- आते हैं या नहीं आते हैं, इसको मैं जाकर देखकर आपको बताऊंगा कि यह सही है या नहीं है। मैं आपके जैसे हवा-हवाई में नहीं बताऊंगा। नगरनार में कौन सा गांव, झगरकोण्डा किस पंचायत में है ? आपके वित्त मंत्री जी हमारे सुकमा, दंतेवाड़ा जिले में दो-ढाई साल तक कलेक्टर थे। यह बात एक-एक गांव वाले को मालूम है। उन्होंने झगरोड़ा को भी जाकर देखा है। वह एक गांव भी बता दें, जिसमें नियद नेल्लानार योजना के तहत् कुछ काम हुआ है तो मैं वहां जाकर देखूंगा। केवल टी.व्ही. में देखने और विधान सभा में बात करने से क्या होगा? क्या पता ? इसलिए अच्छे काम को तो करना चाहिए। आज हम लोग इसी विधान सभा में बड़ी-बड़ी मांग करते हैं। उद्योग मंत्री होने के कारण मैंने इस विधान सभा में एक बिल लाया था। एन.एम.डी.सी. और नगरनार प्लांट में लोगों को आशा और भरोसा था कि वर्षों से, हजारों सालों से एन.एम.डी.सी. का माल जापान जाता है। इसलिए यहां लोहा पैदा हो और कारखाना लगे। इसके लिए यहां का जमीन दी जाए, ताकि यहां के नवजवान को नौकरी मिलेगी। एन.एम.डी.सी. व नगरनार प्लांट बनकर लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन वह पूरा होने के बाद एन.एम.डी.सी. को नहीं चला पाएंगे। इसलिए उसको बेचना है। इसी विधान सभा से हमने बिल पास

करके भेजा है। यहां पर हम भी उपस्थित थे। यदि वह एन.एम.डी.सी. को नहीं चल पाएंगे तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार को दो। उसको छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं बोल रही है। विष्णु देव साय जी की सरकार बस्तर को पीछे क्यों कर रही है ? एक तो रायपुर से जगदलपुर तक हवाई जहाज चल रही थी, उसको भी बंद कर दिया गया। अभी मैं बोल रहा था कि बस्तर का विकास माननीय संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी ने किया है। वह जब से विधायक बने हैं, तब से मंत्री हैं। वह कभी केवल विधायक नहीं रहें। उनके यहां भानपुरी विधान सभा क्षेत्र हुआ करता था। कांग्रेस की सरकार उस गांव को तहसील बनायी, मरदापाल को तहसील बनायी, कोहकाभट्टा को तहसील बनायी और छोटे डोंगर को तहसील बनायी। अभी आपने कुछ भी नहीं किया है तो विकास कैसे होगा ? मैंने कल भी कहा था कि किरण देव जी सुकमा से हैं, लेकिन उन्होंने जगदलपुर से चुनाव लड़ा है। वह भा.ज.पा. के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने चुनाव के समय बड़ी-बड़ी बात की थी कि हर ग्राम पंचायत में खोलेंगे, पंचायत भवन में नगद पैसे बांटेंगे तो फिर अभी आप 2,300 रूपये क्यों दे रहे हैं ? माननीय वित्त मंत्री जी, आप अपने भाषण में बताइये कि आप बाकी पैसे कब देंगे ? इतना असत्य, हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों और आम जनता को गुमराह किया गया कि हम एकमुश्त पैसे देंगे। आपने कहा है तो आप एकमुश्त पैसे दीजिए। हम लोग एकमुश्त पैसे दे रहे थे। लेकिन हमको ऊपर से डण्डा पड़ा था कि यदि आप समर्थन मूल्य से एक रूपये भी ज्यादा देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे और आपकी मदद नहीं करेंगे। हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से पैसे दे रहे थे। लोग उसको पसंद कर रहे हैं। एकमुश्त देना है। नहीं देना है, छोड़कर कभी चावल में 2-3 किलो। आज सोसायटी एक साल में एक भी धान खरीदी केन्द्र नहीं खोली है। बहुत केन्द्र खोल दिये गये हैं, आप उसी में अच्छी खरीदी कीजिए। यह सरकार फेल हो चुकी है। अभी फॉरेस्ट की भर्ती हुई। हमारी सरकार में बस्तर में बस्तर फॉरेस्ट (पुलिस वाले) की भर्ती हुई थी। हर जिले से सुकमा, नारायणपुर से 300-300 लोगों की भर्ती हुई थी। उसी जिले के लड़के हों और उसी जिले से वह पांचवीं पास हों। लेकिन अभी फॉरेस्ट की भर्ती हुई तो हम लोग चाहते थे कि सरकार सब भर्ती करे। लेकिन सरकार के लोगों ने भर्ती नहीं की और हैदराबाद की कंपनी को टेण्डर दे दिया गया। यह सरकार भर्ती भी नहीं कर पाती है। इतने सक्षम वित्त मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी हैदराबाद की कंपनी को टेण्डर दे दिया गया। हैदराबाद की कौन सी कंपनी इतना ज्यादा जानती है ? तो इस प्रकार का होने से यहां केलोगों को छत्तीसगढ़ की सरकार पर विश्वास एक साल में जितना उठा है, वह पहले कभी विश्वास नहीं उठा था। हमारे बीजापुर के लोगों को दोनों तरफ से, नक्सलाइट मारेंगे और इधर पुलिस भी मारेगी, इसलिए वहां से लोग रोज पलायन कर रहे हैं। अभी सुकमा और दंतेवाड़ा से पलायन रूक गया, लेकिन बीजापुर से लोग रोज पलायन कर रहे हैं। मैने प्रश्न उठाया था कि कितने लोग जेल गये ? सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सेन्ट्रल जेल जगदलपुर में हमारे सरकार के समय में 11 सौ लोग थे। यह सरकार

खाली जेल भेजने के लिए बनी है। बन्दूक वाले को मारो, पकड़ो। यहां शांति हो, यहां विकास हो, हम भी चाहते हैं कि बस्तर का विकास हो। लेकिन जेल भेजने काम काम चल रहा है। पुराना केस है, उसके पास नोटिस है। वह कभी संघम में रहा होगा, कभी एकाध रैली में गया होगा। लेकिन उस समय उन लोग डरते थे, तो यदि उसको देखकर जेल भेजोगे, हजारों आदमियों को जेल भेजोगे तो पाप लगेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उसको बंद करो। नक्सलाइट को आज खत्म करो, कल खत्म करो, 2026 तक करो। लेकिन उसके नाम से आदिवासियों को बंद करना, आदिवासियों को प्रताड़ित करना, वहां के लोग पलायन करके जाये, छोड़कर जाये, यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, वहां परम्परागत मुर्गा बाजार लगता है। मैं मध्यप्रदेश में बस्तर से एम.एल.ए. बना था। मैं एक कमेटी में असम गया था। वहां पर असमगढ़ परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत, मुख्यमंत्री थे। हम लोग वहां गये तो उन्होंने पूछा कि आप लोग किस-किस क्षेत्र से आये हो ? मैंने कहा कि मैं बस्तर से आया हूं। उन्होंने कहा कि हां वही बस्तर है, जहां मुर्गा बाजार होता है। उस मुर्गा बाजार को आपकी पुलिस बंद करा रही है। मुर्गा बाजार वाले को लाठी मार रहे हैं। मैंने थानेदार को बोला तो उसने कहा कि हमारे एस.पी. का आदेश है। यहां सरकार का आदेश चलेगा या एस.पी. का आदेश चलेगा ?

माननीय सभापति महोदय, धान खरीदी में कलेक्टर, तहसीलदार जाकर-जाकर घूमते हैं तो 8 किलो धान खरीदी हुई है। मैंने कहा कि जितना धान हुआ है, उतना लो। 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो। अगर 23 क्विंटल नहीं है, जितना भी धान है, 12 क्विंटल धान है तो उतना खरीदी करो। क्यों डरा रहे हो ? एक तो सरकार कर रही है। इस अनुपूरक अनुमान में पैसा देने का क्या मतलब ? कुछ ही लोगों को ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ मैं आपकी तारीफ नहीं करता हूं, सब लोग, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग तारीफ करते हैं। हम लोग भी उस समय प्रतिपक्ष के विधायक होते थे और हम जब पत्र लिखते थे, उस उस समय अगर बी.जे.पी. विधायक को एक करोड़ मिलता था तो हम लोगों को 10 लाख रूपया मिलता था। लेकिन विष्णदेव जी इतना सोचते हैं कि कांग्रेसी बोलने से शायद हम लोग नक्सलाइट हो गए या पाकिस्तानी हो गये। हमको पैसा ही नहीं मिलना है तो विकास कैसे होगा ? इसलिए यह अनुपूरक जनता के हित का नहीं है, किसान के हित का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके बोलने से सब पर असर पड़ा है। सब लोग चुपचाप देख रहे हैं और चुपचाप सुने भी हैं। इसलिए सब सुनने वाले सदस्यों को भी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

सुश्री लता उसेण्डी (कोण्डगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ सरकार को एक साल हो गया है। हम सबने 13 तारीख को जनादेश परब भी मनाया है। मैं माननीय विष्णुदेव साय जी और पूरी सरकार को बधाई देती हूं,

जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं को कार्य रूप में परिणित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की बात आती है, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद वह जो 3 साल का समय था, उसके उपरांत इसी छत्तीसगढ़ में जनता ने त्रस्त होकर, परेशान होकर, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और 15 साल में आपके नेतृत्व में, माननीय डॉ.रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में, जो अभूतपूर्व विकास हुये हैं, उससे विपक्ष भी वाकिफ है । अध्यक्ष महोदय, हमारे कई पुराने सदस्य भी आपके कार्यकाल में विधायक के रूप में रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के लोगों को लाग-लपेट के सपने दिखाकर वर्ष 2018 में विपक्ष के साथियों ने जो जनादेश हासिल किया तथा वर्ष 2018 से वर्ष 2023 की जो त्रासदी रही है, छत्तीसगढ़ की जनता जिन सपनों को साकार करना चाहती थी, उस सपने को तोड़ने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया है । अध्यक्ष महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब विष्णुदेव जी की सुशासनयुक्त सरकार चल रही है तो विपक्ष के बंधुओं को भी यह बात हजम नहीं हो रही है । अध्यक्ष महोदय, गोठान की बात आ रही थी, उसमें कई सारे बिन्दु के विषयों में बात हुई, जिनके घरों में दो गाय है, वह भी 10 लाख रूपये का भुगतान ले रहा है, एक गाय डेढ़ क्विंटल गोबर दे रही है, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूँगी, यह कहना चाहूँगी कि इसकी जांच करनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, गोठान में गऊ मूत्र की भी खरीदी प्रारंभ की गई थी और जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम के लिये बिना प्लॉनिंग की बात की गई, जिस तरह से एकेडमी प्रारंभ करके लोगों को छलने की बात की गई, उसमें बिना प्लॉनिंग के सारे काम हुये, उसी तरह से गऊ मूत्र की टनों खरीदी का मामला प्रदेश के सामने आया । अध्यक्ष महोदय, मैं विष्णुदेव साय जी को साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने सरकार बनने के साथ ही कैबिनेट में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में, जो बात हमारी महिला बहनों को सशक्त करने के लिये कही गई थी, उन्होंने उस वादे को पूरा किया और महतारी वंदन योजना चालू करके आज हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग 70 लाख बहनों को लगभग 1 हजार रूपये की राशि मिल रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को पुन: साधुवाद देना चाहूँगी कि मेरे ही जिले में 1 हजार रूपये मिलने से बहनों का जो सशक्तीकरण हुआ है, वह आर्थिक रूप से मजबूत हुई है, उसका एक उदाहरण है । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बैंकों में पहले एक महीने में एक करोड़ रूपये का लेन-देन होता था, मैंने अभी हाल ही में पता किया है कि इस मंथ में बैंक का ट्रांजेक्शन कोंडागांव जिले में 15 करोड़ रूपये का था और इसका श्रेय किसी को जाता है तो सरकार को जाता है, वित्त मंत्री जी को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, हमारी बहनों को जाता है कि इस प्रकार से आर्थिक मजबूती के पक्ष में आगे बढ़ रही है । अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट का काम जिनके हाथों से छीना गया, उस विषय पर बात करते हुये मुझे अफसोस होता है, अभी जिस तरह से लखपति दीदी बनाने की बात आई, योजनाओं की बात आई, हम निरन्तर देख रहे हैं कि सरकार में महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा रहा है, यह आज की बात नहीं है, पूर्ववती सरकार की बात करें

तो समूह बनाकर, मजबूत बनाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मैं आज इस अवसर पर हमारी सरकार को बधाई भी देती हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण आजीविका मिशन में, अनुपूरक बजट के तहत 250 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है, इससे निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन के जितने भी काम हैं, उसमें और मजबूती आयेगी और जिस क्षेत्र में सिर्फ सपने दिखाकर लोगों को छलने का काम किया गया है, अब हमारी सरकार उन सारे कार्यों को मूलभूत कार्यों में परिवर्तित कर रही है और यह कार्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है । नमो दीदी योजना हो या अन्य योजना हो, वह सारे कार्य हमारी बहने करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है । अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में किसानों को बिजली देने की बात हो, उनके खेतों में बिजली पहुंचाने की बात हो, उनको फ्री अन्य इक्विपमेंट देने की बात हो, यह सारी चीजें अगर हम उठाकर देखते हैं तो पिछले 5 सालों में जिसका प्रतिशत पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गिराया गया । आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तेजी के साथ वे सारे काम वापस हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है । धान खरीदी की बात आती है । मुझे तो यह समझ में नहीं आया कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्हें किसानों से प्रेम था या राईस मिलरों से ? किसानों की बारी आई, अतिरिक्त राशि का नाम देकर चार-चार किश्तों में उन्हें राशि दी जाती थी और जब मिलरों की बात आई तो 40 रूपए से बढ़ाकर 120 रूपए कर दिया गया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या 4 किश्तों की बात कर रही हैं । अभी एक मुश्त 3100 रूपए की बात है । अभी तक किसानों के पास एक मुश्त राशि नहीं गई है । हमने तो 4 भाग में राशि दी है, हर त्यौहार में दिया है।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा अंतिम किश्त पर भी घोटाला किया गया, यह प्रदेश के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है । मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूं । संगीता जी, जब इस विषय पर बात आती है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी दर्द होता होगा कि 40 रूपए से बढ़ाकर 120 रूपए कर दिया गया । इतना गुना जो वृद्धि हुई, यह किसलिए हुई, कैसे हुई, यह सवाल उठता है और पूरा प्रदेश आपकी ओर आज भी उसके लिए सवाल कर रहा है और आपकी ओर देख रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आज भी वे आवाज उठा रहे हैं तो 22-23 और 23-24 का भुगतान नहीं हुआ है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता जान रही है कि 120 रूपए देने से शासन को कितना नुकसान हो रहा है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो कह रही हूं । ये किसानों से प्रेम था या राईस मिलरों से प्रेम था ? कोई भी सामान की कीमत कितनी गुनी बढ़ गई, यह सीधे-सीधे देखने को मिल रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह है कि आज उठाव रूक गया है । आज धान बिक्री नहीं हो रही है, कहीं किसी केन्द्र में धान को नहीं लिया जा रहा है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- कांग्रेस की सरकार ने जनता के पैसों को कुछ वर्गों के बीच में उनके जेबों में डाला और अपने जेबों में डाया । यह स्पष्ट दिखाई देता है । आज के इस अवसर पर जिस तरीके से धरती आबा योजना लाने की योजना माननीय वित्त मंत्री जी ने बनाई है, उसके लिए निश्चित तौर पर जो हमारे ट्राईवल क्षेत्र हैं, जो वर्षों से पिछड़ापन का शिकार रहा है और वर्षों से जिस विकास की कल्पना को देखते रहे हैं, आने वाले समय में उन सारी योजनाओं के माध्यम से उसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगी कि पर्यटन के माध्यम से तेजी के साथ उस क्षेत्र में विकास आएगा और देश विदेश के लोग जिस बस्तर को देखने के लिए आतुर रहते थे, आज उस बस्तर को देखने के लिए वापस बस्तर की तरफ मुड़ रहे हैं, बस्तर की तरफ आ रहे हैं । इसका श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विष्णु देव जी की सरकार को जाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और पुन: बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देती हूं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज 2024-25 के द्वितय अनुपूरक अनुमान जो यहां पेश हुआ है, मैं उसकी मांगों के विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान भी है और जब शुरूआत होती है तो कितना राजस्व आएगा, हम कितना खर्च करेंगे, कहां-कहां खर्च करेंगे, इसकी बात होती है । यह राज्य का एक आईना भी है कि हम कौन सी योजनाओं पर खर्च करेंगे, किन तबकों के ऊपर खर्च करेंगे । एक समग्र विकास की बात होनी चाहिए, जिसमें सबका विकास होना चाहिए । विकास किसी एरिया के लिए या सिर्फ किसी एक जन समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए । जो अलग-अलग मुख्य बजट के बाद बात आती है, वह हमारी सप्लीमेंट्री बजट में बात सामने आती है और इसी चर्चा में पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बात रखते हैं, जिसको यदि बजट में सम्मिलित किया जाये तो कहीं न कहीं हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा । यहां पर वरिष्ठ सदस्य पूंजीगत व्यय की भी बात कर रहे थे । अगर अभी हम 2018 से अभी तक की एक संख्या पर जाएं तो 18 में लगभग 41,695 करोड़ का कर्ज हम पर था, उसके बाद 2023 में लगभग 82 हजार करोड़ के आसपास हो गया और 10 महीनों में ही वर्तमान सरकार में हम लोग 28 हजार करोड़ कर्ज ले चुके हैं। ये फिगर एक्जेक्ट से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं एक दिन एयरपोर्ट पर उतरा तो एक एडवर्टाइजमेंट वहां पर लगा हुआ था कि हम 19 प्रतिशत कोयला अपने जीडीपी में सप्लाई कर रहे हैं। ये बात मैंने पिछले बजट पर जब अपनी बात की थी तब भी कही थी और आज भी यह बात कहूंगा

कि इस बजट में कई चीजें प्रतीकात्मक हैं। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी से यह बात कहूंगा कि हमारा राज्य पहला होना चाहिए जो ग्रीन जीडीपी की बात कहे। मैं एक बहुत सीरियस बात यहां पर कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं जब हम कोयला या माइनिंग की चीजों को निकाल रहे हैं, हम उसे अपने जीडीपी में एड करते हैं लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हम अपने फिक्स्ड एसेट को भी लिक्विडेट कर रहे हैं। यदि हम अपने फिक्स्ड एसेट को लिक्विडेट करते हैं, तो हमें या तो ग्रीन जीडीपी या उसका रेंटल जो कि वर्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर है, हमें कहीं न कहीं उसको काटना पड़ेगा। यदि हम उसे नहीं काटेंगे तो हमारा फिक्स्ड एसेट लिक्विडेट होगा और हम उसे अपने जीडीपी पर एड करते जायेंगे। यह आने वाले समय में एक अच्छी स्थिति हमारे लिए नहीं होगी। जब मुख्य बजट भी आया था, तो उसका आज तक का आंकलन हमें करना होगा। मेरे पास एक कागज है जिसमें अप्रैल 2024 से नवंबर, 2024 का टार्गेट और एक्चीवल रिसीव्ड के अगर हम अंतर देखें, तो माईनस 9.62 प्रतिशत का आंकड़ा आता है। वही अगर हम लोग वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में अप्रैल से नवंबर तक का देखें तो हमारा जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है जो नेशनल लेवल पर करीब-करीब 8 से 12 प्रतिशत तक होता है, हम उससे कुछ बेहतर होकर 14.57 पर हैं लेकिन मुख्य बजट का हमारा जो 20 के ऊपर का कहीं न कहीं टार्गेट है, उससे हम पीछे चल रहे हैं। अनुमानित अगर हम लोगों के 23 की बात करें तो 22 हजार करोड़ का हमारे जो जीएसटी का collection होना था, वह 20 हजार करोड़ के आसपास जाकर रुका था और इस साल की अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे प्रोजेक्शन से हमने 01 दिसंबर तक सिर्फ 45.87 एचीव किया है। मैं इसलिए यह बात point out कर रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम देखें तो हमारे अप्रैल से लेकर जून तक हम लोग जीएसटी कलेक्शन में प्लस में गए हैं और जुलाई से नवंबर तक हम लोग माइनस की स्थिति में गए हैं। अगर हम वहीं लक्षद्वीप, सिक्किम, पांडीचेरी की बात करें तो उन लोगों ने 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई है। गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय 15 से 17 प्रतिशत के एवरेज पर चल रहा है। तो आखिर छत्तीसगढ़ में हम लोग ऐसे कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं कि हमारे प्रतिशत आगे आएं?

अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं अभी जब औद्योगिक नीतियॉ आती हैं, तो उसमें अगर हम लोग बहुत सूक्ष्मता से देखें तो लघु उद्योगों को जो सब्सिडी मिल रही थी, नई नीति में थोड़ी सी उसे कम कर दी गई। एससी, एसटी के अलग-अलग क्षेत्रों में जो ब्याज पर अनुदान मिल रहा था, जो एक considerable amount था, उसे कम करके हम 45% तक ले आए हैं। तो हमें बड़े उद्योगों के साथ लघु उद्योगों की भी बात करनी होगी। रामचरित मानस में कहा गया है कि -

मणि-माणिक महंगे किए, सहजे तृण, जल, नाज।
तुलसी सोइ जानिए राम "गरीब नवाज"।।

गहने और विलासिता की चीजें हम लोग महंगे जरुर करें लेकिन जल और अनाज को हमें सस्ता करना होगा। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा है कि -

बरषत हरषत सब लखैं, करषत लखै न कोइ।
तुलसी प्रजा-सुभाग तें भूप भानु सो होइ।।

आम लोगों को असर न पड़े, हमें लोगों से उतना ही कर्ज लेना चाहिए और उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उसका उपयोग कहां हो रहा है। अभी हसदेव की बात करते हैं तो वहां हम लोग जंगल जरुर काट रहे हैं, नीचे किसानों को कल बहुत बड़ी बात धान की और बाकी सारी समस्याओं पर न बोलकर सिर्फ एक comparison आदरणीय वित्त मंत्री जी के सामने रखूंगा। हम लोग जो मिलिंग चार्ज प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं वह करीब 90 और अगर मध्य प्रदेश से compare करें तो 60 के आंकड़े में जाती है। लेकिन अगर वे लोग एफसीआई के 40 और नॉन के 60 परसेंट के रेशियो पर काम कर रहे हैं, तो उनको वहां पर 120 रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसान या किसी एक वर्ग के बारे में ही बात करना है लेकिन हमें हम वर्ग के बारे में सोचना होगा। वित्त मंत्री जी, यदि हम 1-12-2024 का FCI के कस्टम मिलिंग का स्टेट बैलेंस देखे तो वह 13.2 लाख मीट्रिक टन था। अध्यक्ष महोदय, हमारा स्टेट मूवमेंट प्लान जो हमें दिसंबर का मिला हुआ है, वह 2.5 लाख मीट्रिक टन है। वहीं पंजाब और हरियाणा को मिलाकर जो प्लान मिला हुआ है, वह 22 लाख मीट्रिक टन है। जब डबल इंजन की सरकार है तो वह डबल इंजन हमारे यहां आते-आते फेल क्यों हो जा रहा है ? paddy procurement में कोई बहुत ज्यादा difference नहीं है। यदि वहां 185 लाख मीट्रिक टन का है तो हमारा 144 लाख मीट्रिक टन का है। हमें इस बारे में आगे सोचना होगा कि कहीं न कहीं यह नीति क्यों फेल हो जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम जी.एस.टी. कलेक्शन में इतना ज्यादा फोकस न हो जाये कि जो हमारे छोटे व्यापारी है, जिनका 2 करोड़ और उससे थोड़ा-बहुत ऊपर नीचे का टर्न ओव्हर है, उनको notices दिये जाते हैं। उनको installments में देने की बात करते हैं और installment देने के बाद उनको यह बताया जाता है कि हम आपका जी.एस.टी. नंबर ब्लॉक कर देंगे। हम इस तरह गला पकड़कर नहीं निकाल सकते। हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। यदि आप शुरू से लेकर अभी तक का बजट देखे, हमारे article 14 में equality before law की बात कही गयी है। The state shall not deny any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory in India. लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा खराब लग रहा है और यह सरकार के संज्ञान में भी आना चाहिए कि area wise discrimination हो रहा है। एक कॉमन सा ऑर्डर आया कि जितने काम शुरू नहीं हुए है, आप उसको वापस भेज दे, तब से हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। यह एक छोटा सा उदाहरण है। मेरे यहां 750 मीटर की एक सड़क है, जिसके संदर्भ में मैंने बहुत बार सबसे निवेदन किया। अभी तक उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही

है। उसके लिये हमें घूमकर 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारी एक सड़क बनी है, जिसके दो पुलियों के पैसे वापस हो गये हैं, जो वित्तीय स्वीकृति के लिये आज तक अटके हुए हैं। ऐसे में हमें यह सोचना होगा। मैं अनुपूरक जानता हूं। वित्तमंत्री जी यह बात जरूर कहते हैं कि अनुपूरक बजट में सारी चीजें नहीं आ सकती है लेकिन जब 100 रूपये खर्च हो चुका है तो 2 रूपये खर्च करने के लिये हम क्यों उस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने का काम कर रहे हैं ? सड़क, बिजली हमारा बेसिक राईट है।

श्री राजेश मूणत :- राघवेन्द्र जी, वह आपके पड़ोसी है। आप ऐसे ही रिक्वेस्ट कर दीजिये, जो पहले नहीं हो पाया, उसे यही करेंगे और कोई नहीं करेगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसी ही व्यवस्था से काम हो, तो आदरणीय वित्त मंत्री जी हमारे सीनियर हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिना किसी discrimination के सारे एरिया का, सब जगहों का विकास हो। अभी जो यह बात हो रही थी। अभी एक सीनियर सदस्य ने बहुत अच्छी बात की कि भ्रष्टाचार चाहे जहां भी हो, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, उस पर रोक लगनी चाहिए। आरोप तो लगते हैं, लेकिन हमें सीरियसली उसकी जांच भी करनी चाहिए। चूंकि यह सीनियर सदस्यों का मामला है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि वह धान का बोरा अमानक है और उस पर आगे बोलने के बाद भी अधिकारियों की बात मान ली गयी। मैं अपनी विधान सभा की बात बता देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ भाव पत्र में नगर पालिका में 2 करोड़ में से 1.25 करोड़ गौण खनिज के लिये दे दिये गये और सिर्फ 75 लाख रूपये का टेण्डर निकाला गया और सिर्फ 2-3 ठेकेदार को वह पैसा दिया गया। आखिर आप कब जांच करायेंगे ? इसकी जांच होनी चाहिए और सामने आना चाहिए कि आखिर तथ्य क्या है। अध्यक्ष महोदय, It is not the magnitude of the budget, but the impact that it makes. बजट छोटा हो सकता है लेकिन जो मैंने बताया कि छोटे-छोटे काम हैं। मैंने अभी बताया कि हमारे यहां एक बलौदा बायपास है, जहां पर 10 करोड़ के आसपास की मांग के लिये पूरा प्रोजेक्ट install कर दिया गया है। हमें यह बात समझनी होगी कि यदि हम अनुपूरक में इन मांगों को पूरा करते हैं तब जाकर उन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पायेंगे। चाहे अकलतरा बायपास की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात और करना चाहता हूं कि पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों को हम लोग उखाड़ने का काम कर रहे हैं। राखड़ और कोयले की गाड़ियां बेधड़क चल रही है। सभी जगहों पर कोयले और राखड़ की गाड़ियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के संबंध में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने अपने जिले के एक अधिकारी को जब फोन किया कि यह आप तुरंत रूकवाईये नहीं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें नहीं बन पायेंगी, तब उन्होंने कहा कि साहब हमने चिट्ठी लिख दी है और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात की सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को भी दी है। हम लोग

महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं। हमें उन दिव्यांग महिलाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जो अविवाहित हैं और इससे उनका लाभ हो सकता है।

समय
5.00 बजे

कहीं न कहीं मोदी की गारण्टी प्रदेश की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन का पोर्टल 10 माह से बंद है। कभी यह बताते हैं कि अब शुरू होने वाला है, लेकिन जिनकी 10 माह से शादियां हुई हैं अभी तक उनको इसका लाभ नहीं पा मिल पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। स्कूल के चॉक-डस्टर तक ही खबरें आती हैं कि यहां पर आत्मानंद स्कूलों में स्टेशनरी का पैसा नहीं है। यह किसी की भी शुरू की हुई योजना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें उन जगहों पर पैसा देना होगा। क्योंकि यह इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी हमारे यहां बहुत दिनों से बी.एड. बनाम डी.एड. घटनाक्रम चल रहा था जिसमें कोर्ट का इन्ट्रेवेंशन भी हुआ था।

श्री रामकुमार यादव :- इहां पूरा सन्नाटा छा गे हे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.एड. अभ्यार्थी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की बात हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी यह पूरा मामला लटका हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय रामकुमार जी....।

श्री रामकुमार यादव :- Please sit down

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग इसलिए सुन रहे हैं कि माननीय राघवेन्द्र सिंह जी बहुत ही प्रतिभावान विधायक हैं और बहुत ही विद्वतापूर्ण बात कह रहे हैं इसलिए उनको ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- I dont care (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- का बात हे। में गरीब मत बोले कर। में तोर गरीबी देखेला अवईया हौं।

श्री रामकुमार यादव :- काय हे। में फिल्म में देखे हौं तेला इहां गोठियाथव।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के इस फैसले के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन बी.एड. अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जो 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिकाएं निरस्त कर दीं हैं। जब हम लोग 33 हजार भर्ती की बात कर रहे हैं तो आखिर इनको Accommodate करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ? उनको कहीं न कहीं हमने नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। ठीक है वह conditional हो सकता है कि आने वाले समय में जो कोर्ट का डिसीजन

आएगा, वह सभी पर बाध्य होगा। यदि ऐसा हो चुका है वे कई महीने नौकरी कर चुके हैं। आखिर हम लोग उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग के यहां एक बड़ा मुद्दा सिंचाई का है, जो कि हसदेव से जुड़ा हुआ है। हर बार हम लोग हसदेव की बात करते हैं। हसदेव की सिंचाई की बात करते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जब से हसदेव कटना शुरू हुआ है तब से वहां आदिवासियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वहां पर बार-बार वही आरोप लगा रहे हैं कि जो ग्राम सभा हुई है वह फर्जी हुई है। जब यहां पर एक वरिष्ठ सदस्य उसकी बात कर रहे थे कि हमें सही या गलत कही जांच करनी चाहिए तो आखिर इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है ? जब यहां से शासकीय संकल्प पारित हुआ था कि यहां पर आगे कटाई नहीं होगी। आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है ? जब यहां पर सर्वसम्मति से पारित होने के बाद गया था। आखिर हमें उसकी जांच करनी होगी। यदि वहां पर हम लोग जांच नहीं करते हैं तो आने वाले समय में वहां की स्थिति भयावह होगी। जांजगीर-चांपा से लेकर डभरा तक का जो क्षेत्र वहां से सिचिंत होता है कहीं न कहीं हम लोग उसका दंश झेलेंगे। वहां पर 100 से ऊपर ऐसी प्रजातियां हैं जो वहां विलुप्त होने के कगार पर हैं। क्योंकि वह 2 प्रतिशत जो घनघोर जंगल की श्रेणी में आता है, वह उसमें है। आने वाले समय में 100 से अधिक प्रजातियां, यह देहरादून की वाईल्ड लाईफ की रिपोर्ट है। आने वाले समय में वहां पर वह विलुप्त हो जाएंगी और यहां हमें नहीं मिलेंगी। आने वाला समय शासन किसी का भी हो, आपका या हमारा। आने वाला समय हमें इसके लिए याद रखेगा कि हमने उन प्रजातियों को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माइक्रो फाईनेंस की बात है। माइक्रो फाईनेंस कंपनियों से मेरे विधान सभा क्षेत्र, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बालोद में ऐसी स्थिति है। यहां बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं है। अभी तक 40,000 ऑफिशियल फिगर आया है। एक साल का उन लोगों को विथआऊट इंट्रेस्ट अभी एक जो एक्सटेंशन अवधि दी गई, उनके घर पर लोग लेने आ रहे हैं। तब उनको पता लग रहा है कि अच्छा, हमसे जो लोन लिया गया है वह 4 से ज्यादा किसी अन्य बैंक से भी लोन ले लिया गया है। तो इसमें होम मिनिस्टर साहब के साथ-साथ, हमारे वित्त मंत्रालय को भी आगे आना होगा। हमें ऐसे Regulations बनाने होंगे कि इस तरह का फ्रॉड न हो। कोई जाकर बता रहा है कि तोला फ्री मा कुछ मिलईया हे अपन आधार कार्ड ला दे दे, अंगूठा लगा दे ओकर बाद टार्च के नाम पर महिलाएं ठगी जा रही हैं। जो गांव की महिलाएं ही हैं जिनके पति या हो सकता है वही लोग एजेंट बनी हुई हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक झन तो सत्ता पक्ष के पार्टी के ठगा गे हावए। वह टी.व्ही में आवत राहए। ओति के नेता मन ठगात हे ता ऐसी के का हो ही।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक जगह दारंग पड़ती है जो महिला एजेंट थी उनके पति द्वारा आत्महत्या कर ली गई । इस तरह की लगातार माइक्रोफाईनेंस की भी

दिक्कतें हो रही हैं। एक महिला को 4,7,8 बैंक तक ने महिला को लोन दे रखा है। वह पैसा कहां गया है, किसी को नहीं पता। पुलिस के साथ-साथ आखिर हमारी एल.आई.बी., आई.बी. क्या कर रही थी जब इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की बात हो रही थी। हमें ऐसे लॉ रेगुलेशन लाने होंगे, हम लोग legislature का हिस्सा हैं। हम लोगों को ऐसे लॉ रेगुलेशन्स लाने होंगे कि आगे इस तरह का फ्राड करने वाले कभी महिलाओं के लिए सामने न आ पायें। हम लोग महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं और अगर 40-50 हजार लोगों के साथ ये घटनायें हो रही हैं तो इसका magnitude बहुत बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आने वाले समय में हम लोग प्रोजेक्शन के जो फिगर्स हैं, उसको realistic रखें ताकि आने वाले समय में चाहे वह छोटा व्यापारी हो, because everything works in a circle. किसी भी जंजीर को ऐसा न लगे कि उस पर ज्यादा भार पड़ रहा है। क्योंकि यदि एक पर ज्यादा भार पड़ता है तो वह पूरा सर्कल टूटता है। मैं कोरोना की बात करना चाहूंगा। कोरोनाकाल में चूंकि इस जंजीर को ठीक से रखा गया था। कोरोनाकाल में जब पूरा हिन्दुस्तान recession में गया तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था, चूंकि धान के पैसे का इन फ्लो मार्केट में और इकानामी में था, recession का इतना ज्यादा प्रभाव हम पर नहीं पड़ा। धान हमारा सिर्फ जरिया नहीं है, सिर्फ recession की ही बात नहीं है, धान हमारे पूरे स्टेट की इकॉनामी चलाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इस तरह की पालिसी बनाई जायें और इस तरह जो चावल में और धान खरीदी में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, यह हमाने सामने न आयें। हम लोग सभी क्षेत्रों को equal तरीके से पैसा दे सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी। संक्षिप्त में बोलेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा द्वितीय अनुपूरक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के द्वारा सरकार में आने के बाद से जिस प्रकार से नीतियां बनाई गई हैं और नीतियॉ बना करके सभी तबकों को चाहे हमारे किसान, महिला, गरीबी रेखा में जीवन करने वाले लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, वनवासी, नक्सल क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, सभी लोगों के लिए कार्ययोजना बना करके जो कार्य किये हैं, निश्चित रूप से यदि हम एक साल का कार्यकाल देखेंगे तो प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन में हम किसानों, महिलाओं की बात कर सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से कहीं न कहीं मजबूत हुए हैं। हम यदि नक्सल क्षेत्र की बात करेंगे तो एक साल पहले वहां जो स्थिति रही, सामान्य लोग भयभीत रहते थे, नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। आज हम एक साल में देख रहे हैं कि आम लोग अपनी इच्छा शक्ति के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी फोर्स के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ में जो

लगातार मूवमेंट बनाये हुए हैं और उनके खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई का परिणाम है कि आज नक्सली हतोत्साहित हैं। वहां विकास के कार्य प्रारंभ हुए हैं। वहां पर जो विकास के रास्ते बंद हो गये थे, नये सिरे से पुन: विकास के कार्य शुरू हुए हैं। हम सी.एम. जनमन योजना की बात करें जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। वहां रहने वाले जो हमारे जन-जातियों का जो पूरा समूह है, जो पूरा group है जिनका चाहे बिजली का हो, हम स्कूल की बात करें, सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें इनको लेकर उनको जो काम करने के लिए एक बजट में जो शामिल करके यह प्रयास किया गया है कि उन प्रभावी क्षेत्रों के ऐसे समूह जो हैं उन समूहों के लिए काम किया जाए और आज उसका परिणाम हमारे सामने में दिखाई दे रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जब बात करते हैं, बस्तर के हमारे Olympic की बात करते हैं । जिस प्रकार से वहां पर युवाओं को प्रोत्साहन के लिए और खेल -कूद को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर Olympic का आयोजन किया गया । इस आयोजन के माध्यम से कहीं ना कहीं आज युवाओं में काफी उत्साह का वातावरण जो दिखाई दे रहा है । विविध खेलों में जो उनके द्वारा प्रतिभागिता-सहभागिता और उसके साथ में एक बड़े आयोजन के साथ में उसके लिए सरकार के द्वारा जो वहां पर राशि दी गई और उस राशि के अंतर्गत में बस्तर Olympic 7 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया और उसके लिए जो एक बड़ा आयोजन हुआ और उस बड़े आयोजन का हमारे राष्ट्रीय गृहमंत्री जी के द्वारा अभी समापन किया गया । हम यहां किसानों की बात करेंगे तो आज मुझे बताने में सुखद अनुभूति है कि जिस प्रकार से हमारे किसान चुनाव के पहले जो घोषणा हम लोगों ने किसानों के लिए की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद में 21 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी और 3100 रुपए का भुगतान किया जाएगा । आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे हम मध्य प्रदेश में हों या छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में हों यदि किसानों के खाता में सबसे ज़्यादा राशि गई है तो विष्णुदेव साय की सरकार में आम किसानों के खाता में सबसे ज़्यादा राशि गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं ।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष जी, वह राशि कब मिलेगी थोड़ा बता दीजिये ? 3100 रूपये कब मिलेगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको पिछली बार मिला कि नहीं मिला ?

श्री बघेल लखेश्वर :- मिला । लेकिन अभी कब मिलेगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने दो साल का बोनस नहीं दिया । आपने पिछले दो साल का बोनस नहीं दिया, जो चुनाव के पहले आपने कहा था । दो साल का बोनस मिला कि नहीं मिला ?

श्री बघेल लखेश्वर :- हां ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चार किश्त का एक किश्त में मिला कि नहीं मिला ?

श्री बघेल लखेश्वर :- उस बात को छोड़िए न । अभी 3100 कब मिलेगा वह बता दीजिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसको कैसे छोडूं ?

श्री बघेल लखेश्वर :- अब 3100 कब मिलेगा वह बता दीजिये ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी तो धान खरीदी शुरू हुई है । धान खरीदी चल रही है । (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- आप एकमुश्त देने की बात कर रहे थे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पंचायत में काउंटर लगाकर देने की बात कही थी । महोदय जी उस राशि की बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कहां जाबे, सीधा ऊपर । हमर नेता जी तौले बर गे रिहिस हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं । मैं सारी बात बता रहा हूं ।

श्री बघेल लखेश्वर :- सभी जगह धान खरीदी केंद्र बंद हो गया है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार आपको तो भूमिहीन का पैसा भी मिलेगा । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी की सरकार में कभी धान खरीदी की समस्या नहीं आयी थी । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- वह रामकुमार के खाते में आयेगा, उसके लिये आप इंतजार करो लेकिन बाकी का जो पैसा है, आपने चार किस्त में दिया और हम लोगों ने कहा था कि एक किस्त में देंगे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो इस राशि की बात चल रही है । एक राशि प्रदान नहीं किये हैं । (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है । (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- जब किसान को जरूरत होती है तब तो देना चाहिए । (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- दीजिये न । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमर सीनियर नेता जी ला तुमन मंत्री नइ बनाये हओ अउ मंत्री नइ बनाये हओ तेकरे ओ हा बदला लेत हावय । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जरूरत थी । (व्यवधान) आपने तो एक राशि भी नहीं दी है । (व्यवधान) आप एकमुश्त राशि की बात कह रहे हैं लेकिन एक राशि नहीं मिली है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, खाद्यमंत्री के गांव में धान खरीदी बंद है । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 के इनके घोषणा-पत्र में था । (व्यवधान) आप लोग अपना घोषणा-पत्र देखिये, क्या कह रहे हैं ? आपने खुद नहीं किया । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी की सरकार में कभी धान खरीदी बंद नहीं हुई थी । (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- अभी तो आपकी सरकार है न । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी का परिणाम है । आपने असत्य वायदा किया था । (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले की बात कर रहा हूं। अधिकतर धान केन्द्र बंद हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धरम भैया, खाद्य मंत्री के गांव में धान खरीदी बंद। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- पता नहीं, आप कहां से लेकर आ गये हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ये समिति का कागज है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप एक काम करें। मैं बोल सकता हूं। आप मंत्री के पास मत जाइए। आप कल मेरे साथ चलिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बिल्कुल चलूंगा। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- और चलकर आप 10 खरीदी केन्द्र को आप साथ में देखिए। मैं चलने को तैयार हूं। वहां पर धान खरीदी हो रही है, नहीं हो रही है, आपको पता लग जाएगा । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- खाद्य मंत्री के गांव में धान खरीदी बंद है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने साहस नहीं किया, लेकिन हमने पिछली बार कई बात इस बात को उठाया। आप लोगों ने साहस नहीं किया। मैं साहस कर रहा हूं। सब धान खरीदी केन्द्र में चलेंगे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में चलिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम चलने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप स्वीकार करिए। (व्यवधान)

श्रीमती सावित्री मंडावी :- हम चलने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा था कि एक-एक बीजा धान की खरीदी करेंगे और पिछले साल हम लोग 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी की है जो अब तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ में 13 हजार 300 करोड़ रूपये का प्रोत्साहन राशि। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस बार विष्णुदेव साय सरकार की मंशा ही नहीं दिख रही कि वह धान खरीदे। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- आप लोगों की मंशा क्या थी? जनता ने बता दिया कि आपकी मंशा क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ लूट, लूट, लूट किये हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :-45 हजार करोड़ रूपये का एकमुश्त भुगतान भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा की गई है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम सोसाइटी में गये हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता वहां का दौरा नहीं किये हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना की आपने घोषणा की थी कि हम महिलाओं को 1000 रूपये देंगे और उसके बाद आप लोगों ने 12000 की बात की। (व्यवधान)

श्री ओ.पी. चौधरी :- 500।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने कहीं घोषणा नहीं की। महतारी वंदन आपने घोषणा की थी। आप इतना असत्य क्यों बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सावित्री मंडावी :- महतारी वंदन की आपने घोषणा की थी। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ये इतना असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आज महिलाओं को 1000 रूपये खाते में पहुंचा रहे हैं। 6500 करोड़ रूपये की राशि अभी तक महिलाओं के खाते में गयी है। महिला आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। (व्यवधान)

श्रीमती चातुरी नंद :- महिला मन के खाता में रोक लग गे हे। महतारी वंदन में महिला मन के खाता में परमानेंट रोक लग गे हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने विधवा महिलाओं को 500 रूपया दिया है। उसका 500 रूपया कहां गया?

श्री सुशांत शुक्ला :- जो खुद नहीं दे पाये, वे आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। (व्यवधान) जो 5 रूपये नहीं दे पाये, वे हमसे सवाल पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इन्हें 1000 रूपये देना था। 500 रूपये दिया जा रहा है। आपके घोषणा पत्र में नहीं था कि पेंशनधारी महिलाओं को 500 रूपये काटकर दिया जायेगा। लेकिन आपकी सरकार ने 500 रूपये काट लिया।

श्री सुशांत शुक्ला :- ये कौन सी बात हुई? (व्यवधान) आप 5 साल तक 5 रूपये नहीं दे पाये, आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 500 रूपये काटा। उनका पैसा कहां गया? बताइए। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रायमुनी भगत :- संगीता जी, आप महिला हैं तो कम से कम आप तो महिलाओं का सम्मान कीजिए। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने आधी आबादी का अपमान किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मोतीलाल साहू :- बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता खा गये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 500 रूपया ला बाबा जी के झोला म भेज देहव। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 709 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया था और इस बजट में उनके लिए 250 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान उसमें किया गया है। उसके साथ ही साथ में आप लोगों ने जो काम किया, उसके लिए महिलाएं आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी। (शेम-शेम की आवाज) ये जो बहुमत बता रहे थे न 71 का बहुमत है, 70 का बहुमत है 69 का बहुमत है। आपका बहुमत कहां चला गया?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप भी 15 में आये थे। 15 में इधर ही बैठते थे। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सब लोगों ने जिस प्रकार से छल, कपट और धोखा करके सरकार बनाया था, 5 साल में देखने के बाद में उन महिलाओं ने भी आपको देखा और इसलिए महिलाओं ने चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधान सभा के चुनाव हो, इस बात को उन्होंने बता दिया कि ऐसी सरकार जो धोखा देकर सरकार में और सत्ता में आयी और सत्ता में आने के बाद बात को पलट दे, छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार करती है, धैर्य रखती है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गरीब जनता न्याय चाहती है। गरीब जनता जिसने आपको जीताया है, जिसने आपको सत्ता में लाया है, वही जनता आपसे पूछ रही है कि 500 रूपये में सिलेंडर देने की बात हुई थी, 500 रूपये में सिलेंडर देने की घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, धरमलाल जी से अनुमति चाहूंगा। जिनके पैर के नीचे जमीन नहीं है, उनको आज भी यकीन नहीं। आइना भेजे थे दिल्ली, जनता ने इन्हें दिखा दिया। स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं। पच ही नहीं रहा है कि 5 साल में अत्याचारी, भ्रष्टाचारी अपनी सरकार खो चुकी है इनके हाथ से। ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम स्वीकार कर रहे हैं। जनता ने आपको चुना है। जनता की उम्मीद पर खरा उतरिए, यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी, और कितना समय लेंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल ही नहीं पाया हूं । मुझसे ज्यादा तो ये लोग ही बोल रहे हैं । मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, पृष्ठभूमि रखा हूं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अभी असत्य बोल रहे थे, अब सच बोलेंगे आप ।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी करिये आप ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाओ और उसके लिए उनके समूह के लिए उनको कम रेट पर लोन देकर सशक्तिकरण करें, उनको योजना से जोड़ें और इसके माध्यम से वे अपना व्यवसाय करें । इसी प्रकार नमो ड्रोन की बात है । उन महिलाओं को ड्रोन के माध्यम से सशक्त बनाना, लखपति दीदी बनाना और इसके माध्यम से हम उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बना सकें । उसके लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए हैं । मैंने कहा कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा जीरो से छः वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को टीकाकरण, रेडी-टू-ईट, गर्म भोजन के साथ ही साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देकर लाभान्वित करने का काम इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है । इसके साथ ही 104 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी के मान से भवनों के निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है, इस हेतु 12 करोड़ 48 लाख का प्रावधान इस अनुपूरक में रखा गया है । नियद नेल्लानार योजना, इस योजना के अंतर्गत आपका अच्छा गांव । आपका अच्छा गांव, जिसमें आप रहेंगे ।

समय
5.21 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री कवासी लखमा :- अभी चलो दिखाता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलेंगे, चलेंगे । इस योजना के अंतर्गत जो प्रावधान किये गये हैं । इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो गांव हैं । उन गांवों का समुचित रूप से हम कैसे विकास कर सकें । उसके लिए एक नई योजना नियद नेल्लानार के अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांवों में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, खेलकूद जैसी आवश्यक सुविधाओं एवं अन्य गतिविधियों से जोड़कर उनका विकास किया जाएगा । आज यह योजना सफल होती दिखाई दे रही है । नारायणपुर में नए आई.टी.आई. की स्थापना, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के साथ अधोसंरचना के विकास के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं । जिससे कि नक्सल प्रभावित लोगों और उनके क्षेत्रों का एक बार में कैसे विकास किया जा सके । उनकी समस्याओं के निदान के लिए इन योजनाओं को लागू किया गया है, जिसका लाभ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाईयों को मिल रहा है । सभापति महोदय, हमारे शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं । आप देख रहे हैं कि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है । नई-नई कालोनियां आती जा रही हैं, नई बसाहटें हो रही हैं । इन बसाहटों को हम कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं ? उनके लिए पार्क की योजना, उनके लिए पानी

की योजना, उनके लिए बिजली की योजना, बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान की योजना और इसके लिए पहले 700 करोड़ का प्रावधान किया गया था, अभी उसमें 200 करोड़ का प्रावधान और किया गया है । जिससे कि हम नए आबादी क्षेत्र को समुचित रूप से व्यवस्थित कर सकें और वे शहर की मुख्य धारा, विकास के क्रम में जुड़ सकें, इसके लिए व्यवस्था की गई है ।

मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, सभापति महोदय, इस योजना के अंतर्गत गांवों के लिए सामुदायिक भवन, सी.सी.रोड की व्यवस्था, पंचायतों की अन्य व्यवस्था, राशन दुकानें, मुक्तिधाम की व्यवस्था की जाती है । पिछले समय में इस योजना से गांवों को, पंचायतों को काफी लाभ हुआ है । मैं समझता हूं इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है । निश्चित रूप से विधान सभा को इसका लाभ मिलेगा और वहां के गांवों के विकास की गति तेज होगी। इसके साथ ही साथ नेटवर्किंग का विषय है, चाहे हमारे रेल का हो, हमारी सड़कों के विस्तार का हो, हमारी एयर कनेक्टिीविटी जोड़ने का हो। अभी बिलासपुर से प्रयागराज, जबलपुर, दिल्ली, कोलकाता को जोड़ने का काम हो रहा है। इसी प्रकार जगदलपुर से जबलपुर, दिल्ली कनेक्टिीविटी जोड़ने का है। इसी प्रकार अंबिकापुर हवाई पट्टी के विस्तार की योजना बनी है, इस प्रकार से एयर कनेक्टिीविटी के माध्यम से प्रदेश को जोड़ने के लिए एक नये विस्तार से उसका काम शुरू किए हैं। आने वाले समय में हम सबको उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, अभी उसमें 25 करोड़ रूपये का फिर से प्रावधान किया गया है।

वैश्विक स्तर के विशिष्ट पर्यटन केन्द्रों का विकास। यह हमारी भारत सरकार की योजना है, नवा रायपुर अटल नगर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना है। माननीय सभापति महोदय, बहुत समय से यह बातें आ रही है। जैसे हमारी राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म सिटी है, यहां पर भी फिल्म सिटी का पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप हो, उसके लिए वहां पर उसका भवन बनना चाहिए, वहां पर उसका गार्डन बनना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए स्थान होना चाहिए, सूटिंग के लिए जगह होनी चाहिए, इन सबके लिए 97 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत समय से छत्तीसगढ़ में यह मांग रही है लेकिन पिछले समय नाम आया, नाम आने के बाद उसमें कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी के द्वारा एक वृहद सोच हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए रही है, छत्तीसगढ़ की भाषा और छत्तीसगढ़ की कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ी में ज्यादा से ज्यादा हिंदी फिल्मों का निर्माण हो सके, वहां जो रेट है उससे कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके, इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जो फिल्म सिटी बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाने वाले निर्माता, निर्देशक, कलाकार और सारे साथियों को मिलने वाला

है। इससे यहां पर एक अच्छी फिल्मों का निर्माण होगा, इस प्रदेश की संस्कृति, इस देश की संस्कृति और कल्चर के हिसाब से लोगों के बीच में प्रशंसा भी मिलेगी और ख्याति भी प्राप्त होगी।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार। खास करके खाद्य में लगातार मिलावट की बात आती है, उसमें समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, उसमें हम लोगों को स्वस्थ पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो, इसके लिए इस बजट में 5 करोड़ 11 लाख का प्रावधान किया गया है जिससे इस मिलावट को रोकी जा सके और लोगों के बीच में हम अच्छे फूड दे सकें। प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मजबूत रिफरल सिस्टम के विकास के लिए प्रावधान किये गये हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना। इस योजना के लिए बजट में 1820 करोड़ की राशि का प्रावधान था, अभी 53 करोड़ 25 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने खेलो इंडिया के बारे में कहा। इसके अंतर्गत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बलौदाबाजार, बिलासपुर और साथ ही अन्य जिलों को शामिल किया गया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में और काम करके खास करके युवाओं को खेल के क्षेत्र में कैसे आगे ला सकें, उसके लिए काम कर रहे हैं। यूनिटी मॉल की बात आई है, एक जिला, एक उत्पादन। हमारे यहां प्रदेश में जो उत्पादन हो रहे हैं, उस उत्पाद को हम .....।

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में शामिल कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, एक जिला, एक फसल और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह जो यूनिटी मॉल बनाने की बात आई है, उसके माध्यम से हमारे हस्तशिल्प, लकड़ी के काम करने वाले, बर्तन के काम करने वाले और फसल का उत्पादन करने वालों को हम एक बाजार उपलब्ध करा सकेंगे। जिसके माध्यम से बाजार तक उनके माल की पहुंच हो सकेगी। लोग वहां पर आकर उस माल को खरीद कर ले जाते हैं। इस प्रकार के यूनिटी मॉल की व्यवस्था इस बजट में की गई है। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था। उनका जो पहला भाषण हुआ, उस भाषण में उन्होंने छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी-नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कहा था। मैंने उसी दिन मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा था कि भूपेश जी, आपके पहले जोगी जी भी मुख्यमंत्री थे। वह सफेद मूसली लेकर आये थे, लेकिन हम लोगों ने उस सफेद मूसली का भी हश्र होते हुए इसी विधान सभा में देखा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुफ्त में सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री को भी सलाह दे चुके हैं। इसलिए आप उनकी सलाह को मत मानिये और अपने हिसाब से काम करिये। लेकिन उन्होंने उन्हीं सलाहकारों की सलाह में चलने का प्रयास किया। मैंने उनके पहले भाषण में ही कहा था कि यह नरवा, गरवा, घुरवा, बारी-छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी और इसके आगे अब

चेप्टर क्लोज है, संगवारी। इसलिए आप आज से ही इसको बंद कर दीजिए। आने वाले समय में आपको इसका परिणाम दिखेगा। इन्होंने कहा कि हमने फूड पार्क बना लिया। दो जगहों पर तो बिजली की बात आई कि हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इनके जो गौठान हैं, उसपर एक बार नहीं, बल्कि इसी विधान सभा में हम लोगों ने कम से कम 10 बार इस बात को कहा है कि हम उस गौठान को देखना चाहते हैं। जिस गौठान में आप बिजली बना रहे हैं, जिस गौठान में आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या हुआ ? अब जब चुनाव आया तो स्लोगन देकर आप केवल एक बार सरकार ला सकते हैं, लेकिन असत्य स्लोगन के माध्यम से सरकार दोहरा नहीं सकते हैं। पांच साल के बाद जनता ने यह तय कर दिया कि जो छल-कपट के कारण सरकार आई है, वह सरकार नहीं चल सकती है और इसीलिए लोगों ने 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देखी है, उसी विश्वास के आधार पर जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई और विष्णु देव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। हम धरातल पर इस काम को कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विक्रम मण्डावी :- धरम भैया, आपने नारे लगाये थे कि हम सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धरम भैया, आप बहुत वरिष्ठ हैं। एक मिनट।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोगों ने फॉर्म भरवाये थे। आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे। उस समय आप लोगों को हमपर विश्वास नहीं हुआ।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- कलेक्टर के बाई को भी।

श्री धरमलाल कौशिक :- जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, उनको लाभ मिल रहा है। आपने अपने यहां फॉर्म नहीं भरवाये और फॉर्म भरवाने का विरोध किया और अब उसकी सिफारिश कर रहे हैं। हम लोगों ने तो उसी समय कहा था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को फॉर्म भरना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, यदि यह पोर्टल खोलवा देते तो हम लोग भी फॉर्म भर लेते।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, आज उन सभी को प्रतिमाह 1,000 रूपये मिल रहा है। इन लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, यह लोग भी फॉर्म भरे हैं।...(व्यवधान) आपने कहा था कि आप सालाना 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी भी कई लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वह उस पेपर को संदूक में रखे हैं। ...(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धरम भैया, आप सुनिये तो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आज भी कई लोग आपके दिये हुए फॉर्म लिए बैठे हैं। कई महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, आप संक्षेप कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप पोर्टल खुलवा दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- आप 35,000 शिक्षकों की भर्ती कर दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- आपने प्रतिमाह 3,000 रूपये के फॉर्म भरवाये थे। ...(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, हमारे युवा वित्त मंत्री जी के द्वारा यह जो अनुपूरक बजट लाया गया है, इस अनुपूरक बजट में केवल रिपीट करने का ही काम नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए और उनको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाह)

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, इसके बाद आपका नंबर है। आप अपने समय में बोलियेगा। आप जवाब दीजियेगा। श्रीमती अंबिका मरकाम।

श्री राजेश मूणत :- द्वारिकाधीश जी, माननीय धरमलाल जी ने जो बात बोली है, उसपर आप गंभीरता से चिंतन कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- राजेश भैया।

श्री राजेश मूणत :- आधा नारद जी, आप बीच में मत बोलिये। उन्होंने भूपेश बघेल जी के ऊपर जो बात बोली है, उसपर गंभीरता से चिंतन कीजिए। दादी, आप भी चिंतन कीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- राजेश भैया, मैं उनसे वही बात पूछना चाह रहा था। मुझे बोलने तो दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आप लोग आज तक चिल्लाते रहे कि दारू कब बंद होगा ? लेकिन आज यह दिन आ गया है कि रेस्टोरेन्ट में दारू बिकना शुरू हो रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय,

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, अंबिका जी बोल रही हैं। आप ही की तरफ से बोल रही हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप अभी सदैव धरातल की बात कर रहे थे। धरातल में जनता जानना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया कौन हैं ? सरकार कौन चला रहा है ? आप इसका धरातल बताईये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इनके दिनों में कौन था ? जो जेल में है या बेल मे है वह ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप इनसे धरातल की बात पूछिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जनक ध्रुव :- आपके समय में अंदर-बाहर था। यहां पूरे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहने वाले राजिम में प्रदेश में सबसे ज्यादा दारू बिक रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उसको भी बतायेंगे। कौन सरकार चला रहा है, वह भी बताऊंगा और आपके समय में कौन चला रहा था, उसको भी बता दूंगा। आप लोग चिंता मत करिये। कौन तनख्वाह बांटता था, कौन कैसे पांच-पांच लाख रूपये देता था, यह सब बता दूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने हमारे बारे में तो कई अवसर पर बताया। आप पांच साल तक बताये हैं। धर्मजीत भईया, अभी एक साल का बताईये। हमारे समय का तो कई अवसर में बताये हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यादव जी दिग्भ्रमित हैं। उनकी सरकार के समय कौन सरकार चलाता था, जो जेल में है वह या बेल में है वह, यह बता दें।

सभापति महोदय :- द्वारिका जी, इसके बाद आपकी बारी है। माननीय सदस्यगण आप लोग अपने समय में अपनी बात को रख लें। अंबिका जी, आप बोलिये।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिंहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस अनुपूरक के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। विष्णुदेव का सुशासन, मोदी जी गारन्टी, डबल इंजन की सरकार, ..।

श्री राजेश मूणत :- अंबिका दीदी, मोबाइल में देखकर तो मत बोलो।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- मैं कहां मोबाइल देखकर बोल रही हूं। भईया, मैं मोबाइल देखकर नहीं बोलती हूं।

सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात करती है। अभी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में अभी धरम लाल कौशिक भईया बोल रहे थे। जनमन योजना, कमार जनजाति के लिए विशेष रूप से योजना लागू की गई है। जनमन योजना में उनको आवास देना, उनके लिए सड़क बनाना, इन सारी चीजों के लिए यह योजना लागू की गई है। लेकिन उस योजना का लाभ पूरी तरीके से कमार जनजातियों को नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आदिवासी दिवस मनाया गया था, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री जी टंकराम वर्मा जी गये थे। गृह प्रवेश किए। ठीक है, उन्होंने गृह प्रवेश किया। लेकिन अभी हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि जिनके लिए आवास बनाना है, उसके लिए रेत नहीं मिल रहा है तो कैसे आवास बनेगा ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। आवास के लिए कमारों को, कमार जनजातियों को रेत नहीं मिल पा रहा है। आज धमतरी जिले से सैकड़ों गाड़ियां अवैध रूप से निकल रही है, जिसका माननीय मंत्री जी, आप परीक्षण करा सकते हैं। कांकेर का पीटपास लेकर धमतरी जिले से गाड़ियां निकल रही हैं, जिससे धमतरी जिले को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम यहां बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कमार जनजाति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनकी योजनाओं की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभी तक एक भी सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। सभापति

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इसको तत्काल शुरू कराया जाये, क्योंकि यह महत्वपूर्ण योजना है। सिर्फ कहने और बोलने से नहीं होता है। आज पूरे क्षेत्र की सड़कें खराब हो चुकी हैं। आपका भारत माला सड़क बन रहा है। भारत माला सड़क निर्माण से पूरे गांव की सड़कें खराब हो चुकी हैं। वहां ओव्हर लोडिंग गाड़ियां चल रही हैं। सभापति महोदय, आखिर इन सड़कों को कौन बनायेगा ? इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, कुरूद से मेघा जाने वाला 25 साल पुराना पुल है, जो ध्वस्त हो गया है। राजेश मूणत भईया सुनियेगा। यह आपका विभाग था। वह पुल नीचे से ध्वस्त हो गया है। अभी स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन वहां पर लोगों का आना-जाना बंद हो गया है। आना-जाना बंद होने से वहां पर रपटा बनाने के लिए बात की, कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मूणत जी बधाई हो, आपको दीदी पहले से मंत्री घोषित कर दी।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, मैं यह बताना चाह रही हूं कि उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कलेक्टर महोदय के द्वारा कहा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वहां पर तत्काल रपटा बनाया जाये, जिससे लोगों का वहां से आवाजाही शुरू हो। क्योंकि वह बहुत दूर से कुरूद से घूमकर आते हैं। इसी तरह धमतरी से आपका मुख्य नहर है, जो भिलाई की ओर आता है, जो महानदी का मुख्य पुलिया है, उसकी भी स्थिति जर्जर हो चुकी है, उसके लिये बजट में कहीं पर भी प्रावधान नहीं रखा गया है । सभापति महोदय, आज प्रदेश की स्थिति तो खराब है, लेकिन इसके साथ ही मेरे धमतरी जिले की हालत भी जर्जर हो चुकी है, इसके लिये ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे क्षेत्र की दो सड़क वित्त विभाग को गया था, मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मंत्री जी ने उसे वापस कर दिया है । मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि यह बहुत पुरानी सड़क है और बहुत दिनों के बाद बजट में आया है तो कुरूद-मेघा-मगरलोड सड़क को जरूर जोड़ा जाये । सभापति महोदय, अमलीडी-नवागांव-खिसोरा मार्ग और दूसरा परसागुड़ा-राजाडेरा-पठार मार्ग, यह दो सड़क बहुत महत्वपूर्ण है । सभापति महोदय, आज हम महिलाओं की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने माइक्रो फायनेंस पर स्थगन प्रस्ताव लगाया था, आज महतारी वंदन के नाम से लोगों को आप एक हजार रूपये दे रहे हैं । सभापति महोदय, आज महिला समूह का रोजगार बंद हो गया है, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब उनको गोबर खरीदी से और कंपोस्ड खाद बनाने से रोजगार उपलब्ध हुआ था, इससे पैसे मिल रहे थे । आज महिला समूह पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है । सभापति महोदय, महिलाओं को विभिन्न बैंकों से जो कर्ज दिया गया है, उसमें महिला समूहों की स्थिति इतनी खराब है कि वह कर्ज से लद चुकी है, कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, यह सोचने का विषय है । सभापति महोदय, महतारी वंदन के बारे में हमारी संगीता जी कह रही थी कि उनको 1500 रूपये देना था, लेकिन आप 1 हजार रूपये दे रहे हैं, वहां 500 रूपये

की कटौती क्यों कर रहे हैं ? यह भी चिंता का विषय है । सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना का खूब ढिंढ़ोरा पीटा गया, लोग बहुत खुश थे कि हमें 1000 रूपये महतारी वंदन और 500 रूपये निराश्रित के रूप में कुल 1500 रूपये मिलेंगे । अभी बहुत सारी महिलाओं को महतारी वंदन की राशि नहीं मिल पा रही है, जब हम लोग क्षेत्रों में दौरे पर जाते हैं तो महिलायें यह कहती है, लेकिन आपका पोर्टल बंद है। यदि आप पोर्टल खोल देते हैं तो जो महिलायें बची है, उनको भी लाभ मिलना चाहिये । सभापति महोदय, महतारी वंदन के नाम से क्षेत्र का विकास कार्य ठप्प पड़ा हुआ है, आज एक साल से कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं धान खरीदी के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे और भी सदस्यों ने कहा है कि इसमें एकमुश्त राशि देने की बात कही थी । वर्तमान में 2300 रूपये समर्थन मूल्य मिल रहा है और तौल में भी गड़बड़ी है, बोरे में भी बहुत गड़बड़ी है, आज कई सोसायटियॉ बंद होने के कगार पर है, वहां उठाव नहीं हो पा रहा है । सभापति महोदय, मैंने खुद सोसायटियों का निरीक्षण किया है, जहां पर यह देखने को मिला कि सड़े हुये बोरे को उठाने के लिये डालते हैं तो बोरा फट जाता है, इस तरह से उनको बोरा दिया जा रहा है, इसमें भी भ्रष्ट्राचार की बू आ रही है । सभापति महोदय, पिछले दिनों गंगरेल में धमतरी जिले से चंदा लेकर वहां बहुत बड़ा जल जगार कार्यक्रम हुआ । अभी किसानों को डबल फसल मिलना चाहिये, इसके लिये किसान चिंतित हैं कि उसके लिये कुछ राशि देना न पड़े । धमतरी जिला किसानों का जिला है, वहां पर धान का उपार्जन ज्यादा होता है और ज्यादा से ज्यादा धान लगाया जाता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये । अभी आश्रमों की स्थिति बहुत खराब है, एकलव्य छात्रावासों की स्थिति भी बहुत खराब है, जहां छात्रायें रहती हैं, वहां शौचालय नहीं है, वहां बाथरूम नहीं है, जब वहां जांच कमेटी जाती है तो बाहर में ताला लगा दिया जाता है । राजेश भईया, आप सुनिये । लोगों के द्वारा जांच कमेटी, वह भी महिलाओं की टीम, महिलाओं के हॉस्टल में कौन जायेगा, पुरूष नहीं जायेगा, बल्कि महिलायें जायेंगी, लेकिन वहां पर भी ताला लगा दिया जाता है । सभापति महोदय, जब हम लोग धरने पर बैठे, तब ताला खोला जाता है, यह कैसी व्यवस्था है ? यह तो विधायकों का अधिकार है कि हम छात्रावासों में, हॉस्टलों में, आश्रमों में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं । हम वहां पर कुछ करने नहीं गए थे, सिर्फ देखने गए थे ।

श्री राजेश मूणत :- अंबिका दीदी, आप पहली बार की विधायक तो नहीं हो, इसके पहले भी आप विधायक रह चुकी हैं । यह सब साल भर में इकट्ठा हो गया, उसके पहले कुछ नहीं था क्या ? इन्होंने स्वीकार कर लिया कि पहले शाला नहीं लगता था, अब लगना चालू हो गया तो डिमांड करो ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- पहले 15 साल में पांच साल था न । आपके समय में झलियामारी कांड हुआ, मोतियाबिंद कांड हुआ, नसबंदी कांड हुआ । कितना सारा कांड हुआ है ।

माननीय सभापति जी, स्कूलों का उन्नयन नहीं हो पा रहा है । स्कूलों में अहाता नहीं बन पा रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूं कि इस ओर आप ध्यान दें । बच्चों के स्कूलों का शौचालय पूरी तरीके से खराब हो चुका है, स्कूलों में नये शौचालयों का निर्माण कराया जाये । उनकी पानी की समुचित व्यवस्था हो, अहाता की व्यवस्था हो क्योंकि मैं दो-तीन स्कूलों में गई थी, जहां पर मीडिल स्कूल लग रहा है, सिहावा में पहाड़ी के किनारे है, जहां पर तेंदूआ का आतंक रहता है, बच्चे कभी भी घायल हो सकते हैं । ऐसी जगहों पर तत्काल नया मीडिल स्कूल का निर्माण कराया जाये, अहाता का निर्माण कराया जाये, इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं । हमारे बृजमोहन भैया थे तो वे कहते थे कि हम 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन उस पर भी रोक लग गई । शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, कई जगह एकल शिक्षक हैं ।

सभापति महोदय, अभी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी राशि को बढ़ायी जानी चाहिए, उनको कलेक्टर दर पर राशि दी जानी चाहिए, जो बहुत कम है । प्लेसमेंट कर्मचारियों के बिना पूरे मोहल्ले में कचरा पड़ा हुआ है, नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, नगरीय निकाय में प्लेसमेंट पिछली सरकार ने लागू किया, तब हमारी दीदी उनके वेतनमान की चिन्ता नहीं कीं । विपक्ष में बैठने के बाद बहुत बड़ी चिन्ता हो रही है ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सुशांत जी, आप हर बार खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी बोलने दीजिए ।

सभापति महोदय, बहुत खराब स्थिति है । हम स्कूलों के लिए इस तरह की बातें करते हैं । दूसरी बात, कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि जिसके कारण महिलाओं के साथ लगातार अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, चाकूबाजी हो रही है । मेरे विधान सभा क्षेत्र के एस.डी.ओ.पी. के आरक्षण को 200 रूपए के लिए लड़कों ने चाकू मार दिया । यह क्यों हो रहा है ? इसको सोचने की जरूरत है । नवयुवक नशे की ओर भाग रहे हैं । कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है । कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे वे नशे की ओर न भागें और इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें क्योंकि अभी एक घटना अंबिकापुर में हुई थी कि पुलिस के परिवार को, उसकी पत्नी और बच्चे को मार दिया गया । इस तरह जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जन कैसे सुरक्षित रहेंगे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, उस घटना में संलिप्त व्यक्ति कौन था, किस संगठन से संबंधित था, यह भी तो बताईए । वह किसके अन्याय, अत्याचार का हिस्सा था, कौन से संगठन का पदाधिकारी था, इसको भी आपको बताना पडेगा न । सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति जी, आदिवासी क्षेत्रों में धान खरीदी केन्द्रों में जो टोकन काट रहे हैं, उसमें आदिवासियों के पास स्मार्ट फोन नहीं होता, छोटा फोन होता है । च्वाईस सेन्टर में जाकर उनको टोकन कटाना पड़ता है । आपने 40 प्रतिशत आफ लाईन किया था, लेकिन जब तक ऑनलाईन का टोकन पूरा नहीं होगा, तब तक आफलाईन में उनका टोकन नहीं कट सकता । इस तरह की स्थिति है। किसान बहुत परेशान हैं, हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, लेकिन किसान कहीं पर खुशहाल नहीं है । इस तरह से व्यवस्थाएं हैं ।

सभापति महोदय :- अंबिका जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं । आप संक्षेप करिए ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो दो सड़क हैं, उसको वित्त विभाग में सम्मिलित कर लिया जाये । यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं । धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे बहुत ही काबिल, मेहनती और ईमानदार वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी के इस अनुपूरक अनुमान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस दिन वित्त मंत्री के रुप में ओ.पी. चौधरी साहब ने अपना विज़न इस सदन में रखा, उसी दिन ये बात समझ में आ गई थी कि अब वित्त विभाग की अनियमितताओं पर रोक लगेगी, हमारे विकास के कार्यों को पंख लगेंगे, हमारे विकास कार्यों को गति मिलेगी और वह इस एक वर्ष में दिखाई दिया। मैं इस विधान सभा में कई वर्षों से हूं। ये तो 800 करोड़ रुपए का बहुत छोटा सा अनुपूरक बजट है। इसके पहले और बहुत-बहुत डेढ़ हजार, तीन हजार करोड़ के भी अनुपूरक बजट पेश हुए हैं। इस बजट में नए कार्य जिन्हें जनहित में करना बहुत जरुरी है, उसके प्रावधान किए गए हैं। मैं उस किताब को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं सामान्य रूप से बात करुंगा। पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रथम वक्ता थे, उन्होंने पुलिस, कानून-व्यवस्था से शुरुआत ही की। ऐसा लग रहा था, जैसे इस प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता फैल गई हो।वित्त मंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी का ये ध्येय है और किसी भी राजनीति में किसी भी प्रदेश का ये प्रथम ध्येय होता है कि उस प्रदेश में शांति और व्यवस्था कायम रहे। अगर शांति का वातावरण नहीं है, वहां साफ सुथरा वातावरण नहीं है, तो आप करोड़ों रुपए की भी योजनाएं ले आएं, वह एक इंच भी खिसक नहीं सकतीं। मैं तो सोच रहा था कि उमेश पटेल जी कम से कम नक्सली वारदातों के बारे में तो आंकड़ें देते। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन के माध्यम से आपको बताते हुए खुशी है कि श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण इस एक साल में छत्तीसगढ़ में 223 नक्सली मारे गए 829 नक्सली गिरफ्तार किए गए, 975 का समर्पण हुआ और 500 -600 से ज्यादा हथियार बरामद हुए।(मेजों की थपथपाहट) गृह मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह बार-बार बस्तर आ रहे हैं। आजूबाजू के प्रदेशों का चाहे वह तेलंगाना, मध्य प्रदेश या

उड़ीसा हो, कमांडो फोर्सेस को आपस में मिलाकर एंटी नक्सल मूवमेंट के लिए पुलिस के सारे जवान झोंके जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा जवान उस बीहड़ जंगल में नक्सलियों की गोलियों का शिकार होता है और होकर जब उसके घर उसकी डेडबॉडी आती है, तो उसके परिवार के लोग कोहराम मचाते हैं, रोते, बिलखते और तड़पते हैं। ऐसे बहादुर जवानों के कारण ही हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उन बहादुर जवानों के बारे में आप प्रश्न उठाते हैं? छोटी-मोटी घटना कहां नहीं होती? होती है और अगर आपको याद नहीं है, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आपके एनएसयूआई का कार्यकर्ता इसी सरकार में जाकर एक थानेदार को मारा, तो क्या हमारी सरकार खराब हो गई? (शेम-शेम की आवाज) आपने बिगाड़कर रखा हुआ है और ऐसे बिगड़ैल लोगों को पद दिया हुआ है जो अपने पद के रौब में जाकर मारपीट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में एक व्यक्ति फॉसी पर सिर्फ इसलिए चढ़ गया कि उसे कॉग्रेस के दो बड़े नेता प्रताड़ित कर रहे थे। (शेम-शेम की आवाज) आप बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते हैं। बदले की भावना से तो आप कार्रवाई करते थे। जी.पी.सिंह जैसे आई.जी.पी. के पद पर बैठे हुए आदमी को आपने जेल भेज दिया और आपका एक भी आरोप, एक भी तर्क, एक भी तथ्य जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं टिका और वह रिस्टेट होकर आ गये! आपकी मर्जी से कोई न चले, तो उसे आप जेल भेज देंगे? जब आप आई.जी. तक को जेल भेज सकते हैं तो छोटे-मोटे कितने आदमियों को आज जेल भेजे होंगे, उसकी गिनती करना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कौन चला रहा है, यह आप बार-बार पूछ रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) यदि वह सज्जन है तो यह कोई जुर्म नहीं है। यदि वह गरीब आदिवासी परिवार से हैं, तो यह कोई जुर्म नहीं है। अगर वह जशपुर के बगिया गांव के रहने वाले हैं, तो वह जुर्म नहीं है। यदि वह भी शहरी ताम झाम, नटके, मटके झटके से सरकार चलाते तो शायद आपको सरकार चलाने का एहसास होता। अगर वह उसी नजरिये से सरकार चलाना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को तकलीफ हो जायेगी। इसीलिए जो सरकार चल रही है, उसमें..।

श्री राजेश मूणत :- धर्मजीत भैया, उनको मालूम था कि आप उनकी पोल खोलेंगे, इसीलिए पूरा मैदान साफ हो गया।

श्री लखेश्वर बघेल :- लेकिन हम लोग डटे हैं।

श्री राजेश मूणत :- हमको कोई तकलीफ नहीं है। 4-6 लोग तो चाहिए उठने के लिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, धर्मजीत भैया स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार कोई दूसरा चला रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, सरकार विष्णु देव साय चला रहे हैं और नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है (मेजों की थपथपाहट)। उनकी गारंटी के आधार पर चल रही है। यह वह सरकार नहीं है कि मेय फेयर में जाकर रेत माफियाओं के संग डील कर दी जाये (शेम-शेम की आवाज)। यह वह सरकार नहीं है कि कोरबा में जाकर कोयला खदान से 40 रूपये टन लेकर यह सरकार चलाये

(शेम-शेम की आवाज)। यह वह सरकार नहीं है जो 2500 करोड़ के शराब की अफता-तफरी करने में लगी रहे, जिसमें कई लोग जेल के अंदर है (शेम-शेम की आवाज)। यह लैंड माफियाओं की भी सरकार नहीं है। आपने लैंड माफिया, सेंड माफिया, कोल माफिया, दुनियाभर के माफियाओं को पनपा के रखा था। उनको यह सरकार ने दबोचने और अंकुश लगाने का काम किया है (मेजों की थपथपाहट)। इसीलिए हमारी पुलिस, हमारी सी.बी.आई., एंटी करप्शन ब्यूरो, ई.ओ.डब्ल्यू. ने कई लोगों को पकड़-पकड़कर जेल के अंदर भेज दिया है। अभी तो वे इस जेल में मत भेजिये, उस जेल में मत भेजिये करके हाई कोर्ट में जा रहे हैं। वे जमानत के लिए तरस गये हैं, इतना पुख्ता केस बन रहा है। यहां पर भी बहुत से विधायक बैठते थे, जो अभी नहीं आये हैं। इन विधायकों को सर्किट हाऊस में कौन, कैसे डील करता था, उसे मैं जानता हूं। किसको कैसे लिफाफा पहुंचता था, मैं वह भी जानता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। परंतु जो लिफाफा देता था, वह आज जेल के अंदर है।

श्री राजेश मूणत :- सीनियर को कितने का लिफाफा मिलता था ? वह बोलेरो जो फाईनेंस हुई थी, उसकी किस्त किसने दी थी ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं बता देता हूं। उसमें तीन श्रेणियां थी। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। अब यह तीनों पदक थे और जो जिस पदक के लायक था उसको उतना ही मिला।

श्री अमर अग्रवाल :- धर्मजीत जी, प्रोत्साहन पुरस्कार भी तो था ?

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रोत्साहन में सांत्वना पुरस्कार था। जब हमारी भाभी जी मंत्री थी।

श्री लखेश्वर बघेल :- हम लोगों को कौन सा पदक मिला था ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मैं किसी के सम्मान में कोई खराब बात नहीं बोलूंगा। आप अपने सीने में हाथ रखिये कि ऐसा होता था या नहीं ? यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे जो सजा देंगे, मैं मानूंगा। उस बात को छोड़िये। अब बोलना था तो मैंने बोला है।

सभापति महोदय, हमारी भाभी जी मंत्री थी और वे रेडी टू ईट को पूरा ईट गयी। हमारी माताएं-बहनें जो गांव-गांव में रेडी टू ईट बनाती थी, एक आदेश में सब खत्म हो गया। पता नहीं वह कौन पोंटी चड्डा, जो एक हाथ वाला था, वह ले गया। सरगुजा की हमारी माताओं, बहनों ने क्या जुर्म किया था, जो आप उनसे रेडी टू ईट का काम लूट लिये ? वह रेडी टू ईट कूट-कूट कर बनाती थी, बच्चों के लिए खाना बनाती थी। उसको बनने देना था ना। कोयला, लोहा, सोना और चांदी में तो आपका पेट भर ही रहा था। आपके पास माल पहुंचेगा भी नहीं, माल तो गायब हो जायेगा। आप याद रखियेगा।

श्री लखेश्वर बघेल :- अभी तो कम से कम उनको वह काम वापस दिलवा दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब हम देंगे ना। कोई काम हड़बड़ी में नहीं होता है। अभी तो हम चार साल राज करेंगे और उसके आगे भी राज करेंगे। विष्णु देव साय जी की शराफत, ईमानदारी और साफ दृष्टि को देखकर जनता उन पर विश्वास प्रकट करेगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिये (मेजों की थपथपाहट)। सभापति महोदय, इनके पांच साल के कार्यकाल में विधायकों का एक क्विंस क्लब बना था। वह क्विंस क्लब चोरी हो गया था। आप लोग जो नये सदस्य हैं, आप शायद उस क्विंस क्लब के बारे में नहीं जानते होंगे। हम लोग उसके शिलान्यास, उद्घाटन में गये थे। अमर भैया और हम लोग गये थे, शायद मूणत साहब भी गये थे। इन्होंने कहा कि वह विधायकों के लिये बनेगा, वहां इतनी छूट मिलेगी। कहां की छूट और कहां का विधायक ?

समय
6.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, उस होटल का चार बार नामकरण बदल गया। उसका अंग्रेजी में इतना कठिन-कठिन नाम रखते थे उसको हम बोल नहीं पाते थे और उसी के किनारे में हमारा घर था। हमारा आना-जाना दूभर हो गया। हमारा रास्ता बंद हो गया था। वहां पर शराब की बॉटले खुले आम बिकती थी। वहीं कोरोना में सबसे ज्यादा शराब बिकी थी। वहां पर शराब डम्प होता था और गोलियां चल गईं। वहां विधायकों के क्लब में एक लड़की और लड़कें के प्रेम प्रसंग में भी फायरिंग हो गई। मैंने वित्त मंत्री जी से पूछा कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारे क्विंस क्लब को खोज कर ला दीजिए, वह चोरी हो गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। वह कैसे आया, उसे किसने लिया था, उसे कौन ले गया था, मैं यह नहीं जानता। लेकिन वहां पर अभी क्विंस क्लब लिखा हुआ है। वहां क्विंस क्लब का बोर्ड तो लग गया है। कम से कम यह तो अब यह लगा कि हमारे अमर भईया, वित्त मंत्री जी, माननीय राजेश मूणत लोक निर्माण मंत्री जी और स्थानीय प्रशासन ने जिसका शिलान्यास किया था तो तो कम से कम वहां पर वह दिखाई तो दे रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज यहां पर सड़कों की बात कर रहे थे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी को यह लोग अब तो यह स्पष्ट है अरूण साव भ्रष्ट है। इन्होंने ऐसा सर्टीफिकेट बांट दिया। अब यह बताईये कि जहां पर हमारे जवानों को जाने के लिए जरूरी पुल था उसको बनाने के लिए कलेक्टर ने अनुमति दी । उस पुल में एक रूपये का भुगतान नहीं हुआ। फिर भी भ्रष्टाचार हो गया। आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शैतान बाईबिल पढ़ रहा है। हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी इतना सुन्दर भाषण दे रहे हैं। यहां पर सुनने वाले न वित्त मंत्री हैं, सुनने वाले न यहां के मुख्यमंत्री हैं। यह अपना भाषण किसको सुना रहे हैं? कोई और तीसरा मुख्यमंत्री आ गया क्या ?

श्री अमर अग्रवाल :- आप लोगों को सुनाना है। अभी तो 5 सालों का पुराना किस्सा चल रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां पर आप जैसे वरिष्ठ नेता आ गये तो मुझे बहुत ताकत मिल गई है। अब मैं और बढ़िया बोलने की कोशिश करूंगा और मैं इसलिए बोलूंगा । जब मैं यह पिछले 5 सालों की बात करता हूँ तो महंत जी, उसमें कहीं पर भी नहीं हैं। माननीय महंत जी बहुत साफ सुथरे तरीके से रहे हैं। माननीय महंत जी के ऊपर कोई दाग नहीं है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय महंत जी आसंदी से सब विधायकों को संरक्षण देते थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उतना चलता है, लेकिन यह बाकी सब काम, आपने इतना खौफ पैदा किया था कि मैं कई आई.ए.एस. अधिकारियों को फोन लगाकर, अपने क्षेत्र की बात करना चाहता था, मिलना चाहता था, उनसे टाईम लेता था तो आई.ए.एस. कई अफसर हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। उस समय फोन उठाना भी पसंद नहीं करते थे। उसका रिप्लाई देना भी पसंद नहीं करते थे, किसी से मिलने का टाईम भी देना पंसद नहीं करते थे। आज कल मैं भी उनको टाईम नहीं देता हूँ। हम भी सत्तारूढ़ पार्टी में हैं। इतना परिवर्तन भी मत लाने की कोशिश करिये। यहां पर सभी विधायक यह जीते हुए हैं। हम सबको विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों से काम पड़ेगा। आप भी जनप्रतिनिधि हैं। अगर आपका सम्मान नहीं होगा तो हमको दु:ख होगा और इस सरकार की मंशा है कि यहां सबका सम्मान हो। आपको बात करेंगे तो सब कोई बात करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में धान का 3100 रूपये दे रही रहे हैं। पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दे रहे हैं। हमारी सरकार ने कृषकों को बोनस दे दिया। प्रधान मंत्री आवास के लिए कर दिया । हम एक साल में इसको वाशिंगटन डी.सी. तो नहीं बना सकते। इसे अमेरिका बना दें? हमारे बस्तर में नकस्ली समस्या हल हो रही है। जिस दिन यह समस्या हल होगी हमारे यहां केरल से ज्यादा पर्यटक आएंगे। हमारा प्रदेश शांति का टापू बनेगा। वहां की संस्कृति, खानपान, रहन-सहन और सुरम्य वादियों को देखने के लिए लोग आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में हवाई सेवा में भी हमारी सरकार ने काम प्रारंभ किया है। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में बहुत तो पैसा मिला है, लेकिन हमारे बिलासपुर की एक समस्या है। आप बोल लीजिए ...।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह जगदलपुर से रायपुर तो शुरू करवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय बघेल जी, सब शुरू होगा। हम जब जगदलपुर जाएंगे तो आप हमारे दोस्त हैं, हमको लेने आना। जब आप बिलासपुर आएंगे तो हम आपको लेने आएंगे और आप बोलेंगे तो दोनों अंबिकापुर तक जायेंगे, मैनपाट घूमकर आयेंगे और रात को सारा इंतजाम रहेगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रार्थना और है कि बिलासपुर में night landing का काम दो साल पहले ही आपके समय में स्वीकृत हुआ था। इससे इंकार नहीं है। लेकिन उसे

पूरा करना है। उसके लिए दक्षिण कोरिया से जो मशीन आ रही है, वह मशीन को यहां लाना बहुत जरूरी है। बिलासपुर में night landing की सुविधा मिलने से वह एयरपोर्ट थोड़ा ठीकठाक हो जायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर एयरपोर्ट का विकास कर रहा है। राज्य सरकार के पास भविष्य में एयरपोर्ट होना आय का एक साधन भी बनेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेश की तरह अपने स्वयं की एयरपोर्ट विकास कंपनी का गठन करना चाहिए जिससे हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर निर्भरता कम हो। वर्तमान में महाराष्ट्र की कंपनी 5 एयरपोर्ट खुद संचालित कर रही है जिसमें शिरडी का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन के पास अपने 3 एयरपोर्ट होना हमारे भविष्य के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।

श्री रामकुमार यादव :- हवाई जहाज ला चलात हव और रेलवे ला बंद करथव जेमा गरीब मन चलत हन।

श्री धर्मजीत सिंह :- सब चल रहा है। आपको कौन सी ट्रेन में जाना है, तैं कौन सा ट्रेन में जाना है बता, हम टिकट करा के भेजब। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है। 70 हजार से ऊपर मितानिनों को डी.बी.टी. के तहत सीधे उनके खाते में पेमेंट दे रहे हैं। प्रदेश में चार मेडिकल कॉलेज मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा आदरणीय महंत जी का क्षेत्र, कवर्धा, दंतेवाड़ा में स्वीकृत कर टेंडर की प्रक्रिया हमारी सरकार ने इन एक वर्षों में लगाई है। योग और नेचुरोपैथी के क्षेत्र में भी 100 बिस्तर का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का भूमिपूजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक महीने पहले ही कर दिया है। मेडिकल कॉलेज को हमारी सरकार एम्स की तर्ज पर स्वायत्ता प्रदान करने का निर्णय ले रही है। इसके तहत पहले 25 हजार रुपये तक जो अधिकार था, उसे अब डीन और एम.एस. को 5 लाख रुपये तक वित्त कमेटी को अधिकार दे दिया गया है। कमिश्नर को 2 करोड़ रुपये तक अधिकार दिया गया है जिससे हमारे संस्थानों में दवाई की कमी मत हो। सरगुजा, बस्तर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को 46 प्रतिशत एवं मैदानी क्षेत्र के डॉक्टरों को 23 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया गया है ताकि वहां डॉक्टरों की कमी मत हो। हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमारे वित्त मंत्री ने जो पैसा दिया है, उसके आधार पर सरगुजा में मल्टी स्पेशलिटी..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय एक मिनट, आप आदरणीय हैं, मेरा कोई वैसा उद्देश्य नहीं है। आप स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी योजना की तारीफ कर रहे हैं। धरातल में स्थिति ये है कि हॉस्पिटलों के 2800 करोड़ रुपये भुगतान नहीं होने की वजह से, अगर सही है तो...।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति जी, लगता है कि आप ध्यानाकर्षण के समय नहीं थे। आप लोग ध्यानाकर्षण लगाये थे, क्लीन बोल्ड कर दिया हूं, चारो खाने चित्त हो गये हैं। मैं बता दिया कि क्या हुआ था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं नहीं था। माननीय मंत्री जी, अगर आप भुगतान कर दिये हैं तो इस बात की जांच करवाईये कि हॉस्पिटल गरीबों का ईलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलें तो मैं अपने क्षेत्र का आपको मिलकर लिखित में दे दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मिल कर बोल देना, अगर नहीं हुआ है तो कर देंगे न, क्या दिक्कत है?

श्री राजेश मूणत :- धर्मजीत भैया, एक मिनट, ये प्रश्न पूछने का अधिकार कम से कम है, अपनी सरकार में पूछिये कि स्मार्ट कार्ड क्यों बंद कर दिया था ? गरीब का आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनाया ? जिस पार्टी को फालो करते हैं, जरा उससे भी पूछ लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- राजेश भैया, यह सरकार बने हुए एक साल हो गये हैं, हम जो किये, क्या वह आप करेंगे ? आपको जनता के हित में काम करना है। क्या आप इधर आने की तैयार कर रहे हैं?

श्री राजेश मूणत :- जो कर्ज इनके ऊपर था।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, इसके बाद आपकी बारी है, आप अपनी बात बोलिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमने गलत किया तो वह क्यों कर रहे हैं? क्या आप इधर आने की तैयार कर रहे हैं?

श्री राजेश मूणत :- हम तो परमानेंट की तैयारी में हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ये मन के सरकार मा आंख के आपरेशव होवय तो आंख ही फूट जाये। आप मन पूरा आंखी ला बंद कर देय रहव। आ समय ला याद करव।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आंख फूटी होगी तो उसकी जांच हुई होगी। कोई घटना हो गई तो क्या उसी को लेकर पकड़कर रोते रहोगे? आप आगे सुनिये न जो मैं बता रहा हूं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सरगुजा में मल्टी सुपर स्पेशिलटी हॉस्पिटल के लिए वित्त मंत्री जी ने पैसा दिया है। बिलासपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल..।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा धरम भैया, एक मिनट । अगर टी.एस. बाबा वहां तारीफ कर देता है कि जो 5 साल तक वित्त मंत्री रहा, उपमुख्यमंत्री रहा उसके क्षेत्र में वह college नहीं खुला पाया और college की building अगर विष्णुदेव साय सरकार स्वीकृत कर देती है यानी उसकी तारीफ कर दे तो भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- मूणत जी, मैं यह बोल रहा था कि बिलासपुर में मल्टी-स्पेश्यलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ करने और सिम्स के लिए 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार ने दी है । (मेजों की थपथपाहट) मेकाहारा जो हमारे प्रदेश का एकमात्र बड़ा अस्पताल है, अतिरिक्त 700 बेड हॉस्पिटल के लिए 232

करोड़ का टेंडर हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) बस्तर का मल्टी सुपर-स्पेश्यलिटी हास्पिटल शीघ्र प्रारंभ करने के लिए M.O.U की प्रक्रिया जारी है और जब यह सब काम हो रहा है तो बिना पैसे के होता नहीं है और वित्त विभाग के बारे में मेरा यह कहना है कि जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय व्यक्ति के रूप में वित्त मंत्री को माना जाता है क्योंकि वह सख्ती करता है, वह रोक लगाता है और मैं एक उदाहरण भी बता देता हूं । आप थोड़ा दो मिनट समय दे दीजिएगा । माननीय रामचंद्र सिंहदेव जी इस प्रदेश के बहुत ही ईमानदार कर्मठ वित्त मंत्री थे । जब विभाग से कोई चीज़ आती थी तो वह file को रखते थे । मान लो पच्चीस A.C. लगाना है करके । यदि गर्मी में वह file आती थी तो वह उस file को आलमारी में रख देते थे और उसको जनवरी में निकालते थे, अभी इसकी क्या ज़रूरत है यह लिखकर उसको वापस भेज देते थे । यानी अब ठंड में A.C. की क्या ज़रूरत है ? आप क्या तर्क देंगे ? तो वित्तमंत्री जी को तलवार की धार में चलना पड़ता है ।

माननीय सभापति महोदय, हमको यह लग सकता है कि यह नहीं दिए, वह नहीं दिए । एक अनार और सौ बीमार, इन सौ बीमारों को अनार खिलाकर सुरक्षित रखना है । इस प्रदेश में हमारे सीमित संसाधन में असीमित काम करने की क्षमता अगर किसी में है तो ओ.पी. चौधरी में है क्योंकि वह यूथऑईकान हैं । (मेजों की थपथपाहट) वह यूथऑईकान हैं और मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि जो वित्त मंत्री खुद बोलते हैं कि आप अपने क्षेत्र का काम भेजो, अब काग़ज़ ही नहीं जाएगा तो वित्त मंत्री कहां से दे देगा भाई ? कागज तो बनकर डिपार्टमेंट से जाना चाहिए न तो सब अपना -अपना पेपर भिजवाइए, वह देंगे क्योंकि वह गांव के रहने वाले हैं उनके दिल में दर्द है । वे गांव के विकास की बात करना चाहते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं एक-दो बात और कहकर समाप्त कर रहा हूं । अभी मैं गरियाबंद गया था, सुपेबेड़ा के बारे में रोहित साहू जी और दूसरे एम.एल.ए. साहब बैठे हैं, दोनों मेरे साथ थे, आपकी party के भी और मुझे उनकी चिंता जायज लगी । अगर हो सके तो एक medical college का जब भी proposal आए तो गरियाबंद में ज़रूर खुलवाइएगा क्योंकि वह बॉर्डर में है । (मेजों की थपथपाहट) उससे उड़ीसा के लोग भी लाभान्वित होंगे । सुपेबेड़ा में जो मौत होती है वह रुकेगी और बार-बार सुपेबेड़ा के नाम से जो सरकार घिरती है चाहे इनकी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, हमारी सरकार हो इससे मुक्ति मिलेगी और यह रोहित साहू जी ने कहा है वह मेरे पास में बैठे हैं । वह बोल नहीं रहे हैं इसलिए मैं उनकी बात को अपने मुंह से बोल रहा हूं कि आप इस पर विचार करिएगा । मैं खेल-कूद के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं । खेल-कूद के बारे में भी हमारे वित्त मंत्री जी ने कितना अच्छा निर्णय लिया है । खेलो India योजना के तहत् बिलासपुर में मल्टी परपज इंडोर हाल के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपया का इस अनुपूरक बजट में प्रावधान है ।(मेजों की थपथपाहट) बलौदा बाज़ार के art and synthetic, athletic track निर्माण के लिए 3 करोड़ का प्रावधान है । (मेजों की थपथपाहट) अब हम हर क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं । बच्चे अगर खेलेंगे नहीं, अगर उनको सुविधा मिलेगी नहीं तो वे कैसे

Olympic में खेलेंगे? कैसे IPL में खेलेंगे? कैसे test team में जाएंगे ? कैसे India team में select होंगे ? कैसे hockey Indian team में select होंगे ? उनको सुविधा देने चूंकि उनमें talent तो है लेकिन अगर आपको अभिनय करने के लिए producer कोई film साईन नहीं करेगा तो आप कहां से अपनी acting दिखाओगे ? कहां से आप अपनी प्रतिभा दिखाओगे ? हम उन बच्चों को खेलने देना चाहते हैं ।

श्री व्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, खेलो इंडिया योजना केंद्र सरकार के द्वारा जांजगीर- चापा जिले के जांजगीर में भी प्रस्तावित है । डी.पी.आर. बना-बनाया पड़ा है परंतु जांजगीर-चांपा के उसको क्यों स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती? ऐसा भेदभाव क्यों ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है कि उसका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। अपनी सरकार के समय ध्यान नहीं दिये और अब कह रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार के समय डी.पी.आर. बना था। फिर यह बजट में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री, खेल मंत्री जी को भी बार-बार पत्र लिखता हूं। महोदय, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं इस बात को कहता भी हूं और हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं। वहां के खिलाड़ियों के लिए कृपा तो करें। पूरा बना बनाया है। बजट तैयार है, परंतु यहां से स्वीकृति का अभाव रुका हुआ है उसको भी शामिल कर लें। आपसे निवेदन है।

श्री रामकुमार यादव :- इसको देख लो कैसा अलग दिख रहे हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- बैठना भाई। दो मिनट बोलने देना भैया, दो आइटम और बच गया है। सभापति महोदय, एक B.Ed और D.Ed का बहुत झगड़ा चल रहा है। D.Ed के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ हुआ है, पर B.Ed वालों का भी ख्याल करिए। वे लोग भी टीचर की ट्रेनिंग लिए हैं, पढ़े हैं। उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। अगर उन B.Ed के लड़कों को भी ले लीजिए। अगर आपके पास इतनी सीट खाली है तो वित्त विभाग तो आपके पास है, उनकी व्यवस्था कर दीजिए और जो नौकरी में हैं, उनको ले लीजिए। आगे से जो नियम आपका कहता हो, वह करिएगा। तो इस पर जरूर विचार करिएगा। इस पर विचार करिये। B.Ed के लड़के भी हमारे छत्तीसगढ़ के बेटे हैं। इनके संग भी अन्याय होगा, ये ठीक बात नहीं है।

समय
6.16 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राइट टू एजुकेशन में मेरा कल क्वेश्चन था। करोड़ों रुपया का पेमेंट स्कूलों को बाकी है। राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों में जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका करोड़ों रुपया का भुगतान बाकी है। कल ही क्वेश्चन

में मुझे जवाब मिला है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन बच्चों के भविष्य का मामला है। स्कूल भी कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में उनको काम करना पड़ता है। अगर उस स्कूल में लाखों करोड़ों रुपया का भुगतान बाकी होगा तो स्कूल कहां से शिक्षा दे पाएंगे? या तो स्कूल बंद होगा या उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और छोटी मोटी राशि है। आप एक झटके में चाहे तो उनका कल्याण कर सकते हैं, उनको दे दीजिएगा। एक आखरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे तखतपुर में एक बजट में मैंने प्रावधान कराया है। बमबम घाट का पुल मनियारी नदी में है। ये बहुत पुरानी मांग है और मैं एक मात्र इसी पुल की मांग किया हूं। बम बम घाट तखतपुर में एक ब्रिज मनियारी नदी पर जो बरेला को मोहले जी के क्षेत्र से जोड़ेगा। मोहले जी के क्षेत्र से तखतपुर और तखतपुर से मोहले जी का बरेला को तत्काल वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि ये पुल बन सके और हमारे लोगों को जो हमारी मांग है, उसको हम पूरा कर सकें। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए वित्त मंत्री जी आपकी काबिलियत और क्षमता की दाद देता हूं। आपसे मेरा अनुभव यह है कि आपको हम जो भी काम बोले हैं, उसे आप करते हैं। बिना बोले भी आप मंगा कर करते हैं, आपकी तरफ से जानकारी भी आ जाती है, यही तो नया अनुभव है। न्यू एक्सपीरियंस विथ ओ.पी. चौधरी यही है। आप भी मिलिए, बात करिए। कहीं पर भी काम होगा तो छत्तीसगढ़ में काम होगा। वह काम किसी पार्टी के लिए नहीं होगा, किसी दल के लिए नहीं होगा, वह तो छत्तीसगढ़ के गरीबों को सुविधा देने का काम होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि श्री ओ.पी.चौधरी छत्तीसगढ़ की माटी का सपूत हैं। वे वित्त मंत्री के रूप में समग्र छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विचार करेंगे और ब्यास जी आप जांजगीर में जब बैठते है इन चार्ज मिनिस्टर के संग हम लोग भी बैठते आए हैं। कान में बात कर लीजिएगा और उसको कागज देकर आगे बढ़वा लीजिएगा, वह भी हो जाएगा। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत।

अध्यक्ष महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी, 5 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय मंत्री जी के साथ बैठने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, इस बात का तो हमें दुख है। अगर वे वहां बैठें, वहां आयें, जानकारी उपलब्ध करायें, केवल भा.ज.पा. के नेताओं के साथ बैठते हैं और निकल जाते हैं। भाई, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। हमारे साथ भी बैठें, हम भी सुझाव देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक बजट के प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इस बात के लिए है कि 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में माननीय वित्त मंत्री जी 28,000 करोड़ रूपये के कर्ज ले चुके हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, 1 मिनट। वित्त मंत्री जी एक बात और गुरु नानक जयंती के दिन छुट्टी रहती है और महर्षि कश्यप जयंती भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत धूम धाम से मनाते हैं। मैं आपसे

विनम्र आग्रह करता हूं कि उसमें सरकारी छुट्टी के रूप में उसको घोषित करिए। वह परमानेंट छुट्टी का दिन रहता है। अध्यक्ष महोदय से भी हमारे कवर्धा के सब कसौधन वैश्य समाज के लोग मिले हैं। आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर में उसे केवल महर्षि कश्यप जयंती लिखना है, उस पर विचार करिएगा । मेमोरंडम आपको दिलवा दूंगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, सरकार बनी, माननीय ओ.पी.चौधरी जी वित्त मंत्री बने तो प्रदेश की जनता और सभी को उम्मीद थी कि जैसे देश के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भी उनके कार्यकाल और उनकी विद्वता की प्रशंसा की थी । मुझे ऐसा महसूस हो रहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छोड़ ना ममा, कहां कहां के बात मा तैं पड़े हस ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- रूक तो जा भांचा । आपने एक घंटा बोला है और मामा को पांच मिनट सुनने के लिए तैयार नहीं हो । माननीय ओ.पी.चौधरी जी विद्वान हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उनकी विद्वता विभाग में नहीं दिख रही है । एक साल में 28 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया है । उसके बाद अगर सरकार की कोई भी योजना सही साबित होती तो 28 हजार करोड़ का कर्ज भी हमको स्वीकार्य था । सरकार की सबसे पहली योजना, चाहे चुनाव के दरमियान हो या आज सरकार की उपलब्धियों में शामिल है । आज सरकार बात की शुरूआत करती है तो महतारी वंदन से करती है । लेकिन महतारी वंदन के नाम पर जैसा बोला गया वैसा धरातल में नहीं हुआ । महतारी वंदन में चुनाव के समय केवल राज्य के नेता ही नहीं, दिल्ली के नेता, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेता ने यह भाषण दिया था कि महतारी वंदन में छत्तीसगढ़ की हर महतारी को लाभ देंगे । कलेक्टर की पत्नी को भी देंगे और आखिरी में कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी को भी महतारी वंदन का लाभ दिया जाएगा । लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लड़की की जिस दिन शादी होती है उस दिन वह महिला हो जाती है । आपकी सरकार बने एक साल हो गया लेकिन एक साल के अंदर जितनी शादियां हुई हैं, उनमें से एक भी महिला का इसका लाभ दिया गया होगा तो इसकी जानकारी अपने भाषण में देंगे? अध्यक्ष महोदय, सरकार बनाने के लिए किसानों को गुमराह किया गया कि किसानों का एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा । पंचायत में पैसा देंगे, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पंचायत में 3100 रूपया मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, एक-एक दाने की बात तो छोड़िए, आज परिस्थिति यह है कि किसान अपने धान को बेच नहीं पा रहे हैं, बेचने की बात तो दूसरी है, सबसे बड़े दुख की बात है कि जो किसान मेहनत से धान की पैदावार करता है लेकिन आज वह चिंतित है, रात में सो नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं सो पा रहा है कि मेरा धान बिकेगा या नहीं । ऐसी परिस्थितियां इसलिए बन रही है क्योंकि सरकार जिस रफ्तार से धान खरीदी कर रही है उससे नियत तिथि तक पूरा धान खरीदी संभव नहीं है । आज किसान का बेटा पढ़ा है वह आंकलन करता है, आंकलन में यह आता

है कि 50 लाख टन यदि बिना किसी असुविधा के प्रतिदिन धान खरीदी होती है तो भी 50 लाख मेट्रिक टन धान नहीं बिक पाएगा । अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की भी बहुत बात की है । दिल्ली में हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात हुई और छत्तीसगढ़ में एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुई । अभी-अभी मैं अखबार में उद्योग मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने तीन-चार दिन पहले भी कहा है कि हर साल एक लाख लोगों को रोजगार देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि एक साल में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है और माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार बनी तो पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने 35 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा इसी सदन में की थी । उन 35 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की अनुमति क्या वित्त विभाग से दे दी गई है या नहीं दी गई है ? तीसरी बात, आदरणीय धरमलाल कौशिक भैया, आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और सब पद में रहे हैं, आपको पर्याप्त अनुभव है, हालांकि इस टाईम आपके साथ अन्याय हुआ है, जिस बात का दुख हम लोगों को भी है। ऐसा कोई सत्र नहीं है जिसमें आपने किसानों की बात नहीं की होगी। एक ही बात केवल स्थाई कनेक्शन की होती थी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आज कई हजारों आवेदन स्थाई कनेक्शन के लिए पड़े हुए हैं लेकिन किसानों को स्थाई कनेक्शन दिया नहीं जा रहा है, अस्थाई कनेक्शन में भारी भरकम बिल वसूली की जा रही है, किसान परेशान है, किसान चिंतित है, पहले किसान के धान को व्यापारी तय करते थे, बहुत लंबे संघर्ष के बाद अब किसान अपनी फसल बेचने में निश्चिंत हो रहे थे। अभी वर्तमान सरकार की एक नीति से किसान परेशान हैं, किसान को अब यह भी आजादी नहीं है कि वह अपने खेत में कौन सी फसल लेगा, सरकार तय करने जा रही है, कई कलेक्टर मुनियादी करवा दिए, अगर रबी फसल में धान का फसल उगाया जाएगा तो बिजली बिल काट दिया जाएगा, 50 हजार रूपये जुर्माना कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं जवाब आना चाहिए, किसान धान बो सकते हैं या नहीं और जिन कलेक्टरों ने बगैर शासन के आदेश के अगर ऐसी मुनियादी करवाई है तो उसके उपर सरकार क्या कार्रवाई करेगी ? यह भी बात आनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी, आप विद्वान हैं, बजट सत्र में तो बात होती है, बजट बंटवारा भी हो रहा है, बजट व्यवस्था भी बन रही है लेकिन जब आप अपना भाषण देंगे तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पूर्व में जो बजट में प्रस्तावित कार्य हैं, उसमें कितने धरातल में स्वीकृत हो चुके हैं या प्रक्रियाधीन है। माननीय धर्मजीत भैया जो बात बोल रहे थे, वैसे व्यवहार की उम्मीद मुझे भी है, अगर वैसा करेंगे तो हम भी धन्यवाद देंगे। मेरे विधान सभा में अभी तक एक साल में केवल और केवल ढाई करोड़ की स्वीकृति हुई है, वह भी सत्र के कुछ दिन पहले मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट में सम्मिलित है, समूचे छत्तीसगढ़ का विकास हो, वह धरातल में दिखे, प्रशासकीय स्वीकृति के बदले केवल वह पुस्तक में छपकर न रह जाए। दूसरी बात, माननीय वित्त मंत्री जी मेरे क्षेत्र में मुनगासेर से रेवा एक मार्ग है जिसमें सड़क की

चौड़ाई कम होने की वजह से हर 8-10 दिन में एक दुर्घटना घट रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसको स्वीकृति जरूर प्रदान करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी, हमारी सरकार में 13 सड़कें मेरे विधान सभा में स्वीकृत थी, कुछ में टेंडर प्रक्रिया भी लग चुकी थी, जिस पर पुन: यह आदेश हुआ है कि वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ किया जाए। उसके लिए मैं निवेदन भी कर रहा हूं और आपसे मुलाकात करके संबंधित को दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- ममा, ले चल बईठ अब। बाजू वाले के चक्कर में झन रबे, ओ हा नोट के गड्डी देख के बेहोश होईस ते तीन दिन बाद होश अईस।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुनील सोनी जी। अपना पहला भाषण देने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पहली बार अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए, अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। विपक्ष ने जिस भाषण की शुरूआत की थी, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने अपराध और कानून व्यवस्था से शुरूआत की। उन्होंने पांच साल तक झांककर नहीं देखा कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो अपराध बढ़ा था, जनता उससे त्रस्त थी और उनमें आक्रोश था। मैं इस बात को कई बार कहता था कि अपराधियों को लग रहा था कि मेरी सरकारें छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य हैं। विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्री जी ने अपराध के ऊपर अंकुश लगाया है। जो अपराध करता है, वह जेल में जा रहा है। यह सरकार अपराध को संरक्षण देने का काम नहीं कर रही है, बिल्क अपराधियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। यदि नवजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पी.एस.सी. घोटाला हुआ तो उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वह जेल के अंदर जा रहे हैं। आने वाले समय में और बड़े लोग जेल के अंदर जाएंगे। आज सरकार की उपस्थिति दर्ज हो रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सोनी जी, सबको जेल में डाल दो और केवल आप लोग ही बाहर रहों।

श्री सुनील सोनी :- द्वारिकाधीश जी, मैं कभी टोकता नहीं हूं। मैं कभी टोका-टाकी नहीं करता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। आप जेल ही जेल बोल रहे हैं तो आप सबको जेल में डाल दीजिए और आप लोग बाहर रहिये।

श्री सुनील सोनी :- सब जाएंगे। आने वाले समय में वह भी जेल जाएंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- ओमे चंद्राकर जी के नाम घलो है।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनील जी, एक मिनट। रामकुमार जी और मामा जी, माननीय सदस्य वरिष्ठ भले हैं, परंतु इस विधान सभा में उनका पहला भाषण हो रहा है। चाहे पक्ष के सदस्य हों या

विपक्ष के सदस्य हों, जब वह मेडन स्पीच करते हैं तो उसमें टोका-टाकी नहीं होती है। आप उनको ध्यान से सुनिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जी।

श्री सुनील सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। उनको उनपर आरोप लगाने का क्या हक है ? आप कभी झांककर देखते कि रायपुर नगर-निगम के अंदर बूढ़ा तालाब के अंदर जहां पर काम स्वीकृत हुआ था, वह काम नहीं हुआ। उस टेण्डर को उठाकर एक मंत्री के घर के सामने काम कर दिया गया। मैं आपको ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। मैं नाम नहीं लेता हूं। मैं आरोप-प्रत्यारोप नहीं करता हूं। आपने जो काम किया है, वह भ्रष्ट आचरण पर काम किया है। मैं जब लोक सभा का सदस्य था और urban standing committee का सदस्य था तो हमने उस काम के लिए 3 बार कमिश्नर को तलब किया था। अजय चंद्राकर जी ने अभी इसी बात को कहा था। स्मार्ट सिटी के पैसे को लूटा गया। हम मर-मरकर सैकड़ों-करोड़ों रूपये इस छत्तीसगढ़ और रायपुर के लिए लाये। मैं यहां पर दो बार महापौर रहा हूं तो यहां पर कुछ विकास होना चाहिए। केन्द्र सरकार ने जितने सुझाव दिये थे और सलाहकार समिति का चेयरमेन होने के नाते मैंने जितने सुझाव दिये थे, उनको छोड़कर सारे काम हुए। आज चौक-चौराहों के अंदर लाखों-करोड़ों रूपये खर्च किये गये, जो टूट गये और बिखर गये। इसका जिम्मेदार कौन होगा ? मैंने माननीय मंत्री जी से यही आग्रह किया था कि इसकी स्पष्ट तौर पर जांच होनी चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है। 5 साल के अंदर जहां पर आप सदस्य हैं, वहां पर स्वयं देख लीजिए कि 5 साल में नगर-पंचायत, नगर-पालिका, नगर-निगम के अंदर टोटी लगाने और गड्ढा भरने का काम भी नहीं हुआ। मुझे तो विधायक बने 20-25 रोज हुए हैं। मैंने 100 करोड़ रूपये से अधिक के काम का भूमि-पूजन कर दिया है। हमारे पूर्व विधायक, जो लोक सभा के सांसद बन गये, उन्होंने उस काम को स्वीकृत कराया है। मुझे उस काम का भूमि-पूजन करने का अवसर मिल रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम हो रहा है। 5 साल तक काम रूके रहें। एक सदस्य बात कह रहे थे कि आपने कितना कर्जा ले लिया है। ओ.पी. चौधरी जी ने 28,000 करोड़ रूपये का कर्जा ले लिया है। आप याद करिये, आपके समय में सड़क तो नहीं बनी, लेकिन आपकी सरकार ने गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने (रिपेयरिंग) के लिए कर्ज लिया था। आपने अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया था। पी.डब्ल्यू.डी. के अंदर सैकड़ों करोड़ रूपये के काम हो रहे हैं। नई सड़कें बन रही हैं। कर्ज सरकार के ऊपर केवल बोझ नहीं होता है। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आम आदमी को लगना चाहिए कि मेरी सरकार है। अगर मोदी की गारंटी के आधार पर यह सरकार बनी है तो आज लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी सरकार है, मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरे मंत्री हैं और मेरे अपने विधायक हैं। बहुत लोग प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे। मैंने लोकसभा के अंदर इस बात को 3 बार उठाया था। एक

बार नहीं, 3 बार इस बात को उठाया था कि इस देश में केवल दो राज्य हैं एक बंगाल और दूसरा छत्तीसगढ़, जहां पर एक भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नहीं बना है। लोकसभा में बार-बार उठाने के बाद केन्द्र सरकार ने 11 हजार करोड़ रूपया दिया था, लेकिन वह पैसा लौट गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? हमारे छत्तीसगढ़ के हक का था, उस गरीब आदमी के हक का था। आप कल्पना करिये कि वह गरीब आदमी, जिसको आवास मिल जाता, जिसको एक छत मिल जाता, उसको एक घर मिल जाता, उसके घर के अंदर एक बल्ब लग जाता है, नल की टोटी लग जाती है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन का सपना पूरा हो गया है, सब कुछ मिलना चालू हो गया है। लेकिन उसमें भी सरकार की नीयत खराब थी।

मानतीय अध्यक्ष महोदय, आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा बजट जल जीवन मिशन के लिए था। 2.67 लाख करोड़ रूपये का बजट था। सन् 2019 में जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था तो 2.67 लाख करोड़ रूपये जल शक्ति मंत्रालय को दिया था। केन्द्र ने पैसा भेजा, योजना लागू नहीं हुआ। टेण्डर-टेण्डर खेले हैं। आपकी सरकार ने टेण्डर-टेण्डर खेला। लोकसभा के अंदर एक बार नहीं, कई बार इस बात को उठाया था। 3 बार नहीं, कई बार इस बात को उठाया कि एक ऐसा राज्य है, जहां पर केन्द्र सरकार द्वारा पैसा देने के बाद भी जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं हुआ है। जब मैं शुक्रवार को इस बात को उठाया तो हमारे केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत जी ने कहा कि सुनील बार-बार इस बात को उठा रहे हो, हम लोग छत्तीसगढ़ चलते हैं। केन्द्रीय मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में आकर यहां समीक्षा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साल बीतने के बाद मात्र 8 प्रतिशत काम हुआ था। दो साल बाद जब प्रहलाद पटेल जी केन्द्रीय मंत्री ने समीक्षा की तो 34 प्रतिशत काम हुआ था। आप टेण्डर-टेण्डर खेल रहे थे। उसके ऊपर अनियमितताओं का बड़ा पुलिन्दा इस सरकार को प्राप्त हुआ है। मैंने उस समय भी कहा था कि आप पाईप लाईन बिछा दिए हो, उसके बाद टंकी बना रहे हो, आपके पास जल के स्त्रोत नहीं है। यह सब विरासत में इस सरकार को मिला है। यह सरकार सुधारने का काम कर रही है। आप प्रश्न खड़ा करते हैं कि जल स्त्रोत कहां है ? इसमें गलती किसने की है ? आज इस बात की खुशी है कि यह मोदी जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। एक बहन उस दर्द को जानती है। वह सुबह उठती है, अपने बुजुर्गों की चिंता करती है, बच्चों की चिंता करती है, खाना बनाती है, पानी भरने का काम करती है, वह थक जाती है। जब थकने के बाद रात को सोती है तो वह सोचती है कि मेरा जीवन सिर्फ मेहनत करने के लिए है। अगर उसकी आवाज को किसी ने सुना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना। मैं विष्णुदेव जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस सरकार ने इस योजना को तेजी के साथ प्रारंभ किया। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। अगर सुरक्षा अधिकारियों के कहने पर उनके लिए पुल-पुलिया बन गया तो आपको किस बात की आपत्ति है ? आपने इतनी

अनियमितताएं की हैं, लेकिन नक्सलवाद समाप्त हो, उसके लिए हमारा जवान कहता है तो मैं तो इसका समर्थक रहता हूं। तो वह बनना चाहिए। अगर उस ठेकेदार का एक रूपये का भी भुगतान नहीं हुआ है, अगर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए। आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा भी नहीं लगता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं ? क्या यह छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त नहीं होना चाहिए ? हमारी सोच क्या है ? हमको इस सोच के आधार पर चलना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजीव मितान को लागू करके ओलंपिक खेल कराया। मैं किसी सदस्य का नाम नहीं ले रहा हूं। एक सदस्य ने कहा कि आप भा.ज.पा. कार्यकर्ताओं के लिए पैसा बांट रहे हैं। आपकी वह राजीव मितान योजना क्या थी ? अगर हमारे वरिष्ठ सदस्य ने पूछा तो 65-66 साल की महिला फुगड़ी खेल रही है, आप इसको गिना रहे हैं। यह बस्तर ओलंपिक आने वाले समय में खिलाड़ी तैयार करने के लिए किया है। अगर उसमें डेढ़ लाख से अधिक नवजवान भाग ले रहे हैं, उसके हाथ से बंदूक हटाकर नक्सल के रास्तें पर ना चले, इसकी चिंता करके, उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, हाकी की स्टिक है और फुटबॉल हाथ में दे रही है । यह सरकार तैयार कर रही है कि आने वाले समय के अंदर में ओलंपिक में हमारे बस्तर का नवजवान आगे बढ़ना चाहिये, वह खेल के अंदर में भाग लेना चाहिये, खिलाड़ी के रूप में पूरे विश्व के भीतर राजदूत बनना चाहिये, ताकि वह विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम पहुंचाये । अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने खेल विभाग के लिए एक बड़ा प्रयास किया है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां आकर उन सारे नवजवानों को प्रोत्साहित किया है, मैं आने वाले समय में और बताऊँगा कि किस प्रकार से आपकी सरकार चली है । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार यदि बजट ला रही है, अनुपूरक बजट ला रही है तो आम आदमी को सुविधा दिलाने के लिये ला रही है, लूटने के लिये नहीं ला रही है, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो । हमारे बहुत से सदस्यों ने बहुत सारी बातें की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं विपक्ष से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार अगर नक्सलवाद समाप्त करना चाहती है, अगर वहां पुल-पुलिया सड़क का निर्माण करती है, आपको कहीं पर लगता है कि यह गलत है, उसको सही रूप में रहना चाहिये । हमारा बस्तर जो है, वह छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है, वह पर्यटन का एक हिस्सा बनना चाहिये, इस सोच के आधार पर हम सरकार के साथ खड़े हों । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही आग्रह और निवेदन करते हुये जो पर्याप्त समय दिया है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद । पांच मिनट ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मै इस द्वितीय अनुमान अनुपूरक बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, बजट से सरकार का विजन दिखता है, सरकार की सोच दिखती है, कार्ययोजना दिखता है । अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें हमारा मूल बजट 1 लाख 47 हजार 440 करोड़ था और उसके बाद प्रथम अनुपूरक 10

हजार करोड़ था, यह कुल मिलाकर 1 लाख 57 हजार करोड़ यानी दो तिहाई से अधिक वित्तीय वर्ष बीत गया है, आपने कितना खर्च किया है, कहां किये, कैसे किये, यह आज भी समझ से परे है । अध्यक्ष महोदय, धरातल पर यदि चलकर देखें तो आपका लैंडमार्क केवल महतारी वंदन योजना को देखें, आप उसके बाद कोई योजना बता दें, जहां आपने इतनी बड़ी राशि का उपयोग किया हो और कोई कार्ययोजना प्रारंभ किया हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल बजट में 20 हजार किसानों के पम्प कनेक्शन के लिये बिजली का प्रावधान है । सदन में यह बातें बार-बार आती थी और वरिष्ठ माननीय सदस्य धरमलाल कौशिक जी इस बात को उठाते थे, लेकिन आज धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है । आप बता दीजिए कि कितने किसानों के बिजली पंप कनेक्शन स्थायी किये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पेपर में पढ़ा है, अडानी जी यहां बिजली के संबंध में बात करने के लिये आये थे, लेकिन उसका क्या हुआ, जब यहां से गये तो बिजली के दर में बढ़ोतरी हुई और आज देख रहे हैं कि जो 500 रूपये बिल का भुगतान करते थे, वह 1000 रूपये भुगतान कर रहे हैं और जो 1000 रूपये बिल का भुगतान करते थे, वह 2000 रूपये भुगतान कर रहे हैं और 2000 रूपये भुगतान करने वाले 3000 रूपये भुगतान कर रहे हैं । इस हिसाब से यहां बिजली की दर में वृद्धि हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, केवल कर्ज भर ले रहे हैं, लेकिन विकास काम कहीं पर भी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, माननीय वित्त मंत्री जी के तारीफ में कशीदे पढ़ रहे थे । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्योत्सव की जब बात आती है, इसमें स्थानीय कलाकारों की जो उपेक्षा हुई और बाहर से कलाकारों को बुलाकर जो जिसे पारितोष दिया गया था, उसका अंतर आप स्पष्ट देख सकते हैं । करोड़ों रूपए के यहां के स्थानीय कलाकारों को केवल हजारों तक सीमित रखा गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्थानीय कलाकार, बाहरी कलाकार को आप छोड़ो । आप माननीय अध्यक्ष जी से मिलिए । रजत जयंती वर्ष में क्या कार्यक्रम करोगे, यह बताओ । विधान सभा में कलाकार बहुत से लोग हैं । उसकी चर्चा यहां पर करिए । एक कलाकार को मिमिक्री में ऐसा सेट करना कि 500-500 की गड्डी लेकर मिमिक्री वाला रामकुमार के पास पहुंचे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अजय भैया, मैं उसमें भी अपनी बात रखूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी से वही बात कर रहा था । धमतरी में जल जगार वाला एक टेण्डर निकला था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै गम्मत बनाबे, ओ ह मिमिक्री ला नहीं समझिस । निषाद जी, ओ ह मिमिक्री ला नहीं समझिस । एक गम्मत बनाबे, ओमा 500-500 के गड्डी धरके जाए अउ ओ ह बेहोश हो जाए, अइसे वाला हो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वही बनही, वहू ला बनाबो । ओकर बर टंक राम भैया के जरूरत पड़ही, ओकरो बर बात करबो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेण्डर निकला था और उसमें जो मापदण्ड तय किए गए थे कि उसके समकक्ष कलाकार होने चाहिए । मैं कलाकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वे आज हमारे सदन में साथी हैं । ये कैसा टेण्डर है कि वही दो कलाकार छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड हैं, बाकी कलाकार शून्य है । जब विरोध किया गया तो फिर टेण्डर को निरस्त किया गया, लेकिन वहां इवेंट में जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया था, वह मुम्बई से आये थे, वह इवेंट की टीम मुम्बई की थी । क्या छत्तीसगढ़ में वैसे इवेंट कराने वाले नहीं थे ? जिस हिसाब से वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग आज बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो यहां की पद्मश्री और पद्म विभूषण से अलंकृत प्रख्यात पण्डवानी गायिका तीजन बाई 8 महीने से संस्कृति विभाग में अनुदान राशि के लिए आवेदन लगा रही थीं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई चिन्ता नहीं की थी । जब यह खबर मीडिया में छपी, आनन-फानन में विभाग के द्वारा कुछ पैसे दिए गए, लेकिन आज मैं समझता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर एक ऐसी महिला है, जिसे पद्मश्री तीजन बाई, जिसे पद्म विभूषण भी मिला है और आज उसकी बोलती बंद हो गई । जिसके स्वर, जिसके शब्द पूरे हिन्दुस्तान में और बाहर के देशों में गुंजते थे, लेकिन आज उसकी बोलती बंद हो गई, उसके बारे में सुध लेने वाला कोई नहीं है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तीजन बाई के लिए कलेक्टर महोदया ने स्वयं जाकर उनके लिए समुचित दवाई, नगद राशि और सारी व्यवस्थाएं की हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गजेन्द्र भाई, मैं वही बता रहा हूं कि लगातार मीडिया में आने के बाद उनके लिए व्यवस्था की गई ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा कहना है कि माननीय सदस्य जबरदस्ती बोलना है, कहकर आप कुछ भी [xx] मत बोलिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं [xx] नहीं बोलूंगा, मैं एक कलाकार हूं । मैं दर्द समझता हूं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- मैं जानता हूं कि आप कलाकार हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 8 महीने तक संस्कृति विभाग द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई । जब यह बात मीडिया में आई, उसके बाद आपने सुध लेने का प्रयास किया है, लेकिन जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से अलंकृत हैं, उनके लिए 50 हजार रूपए देना, आप क्या शान की बात कर रहे हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 हजार की बात नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गजेन्द्र भाई, आप ऐसी बात मत करें । [xx] बोलने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, [xx] बोलने का काम आप लोग कर रहे हैं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- आपने [xx] बोला है इसलिए तो आप उधर बैठे हैं भाई साहब ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [xx] बोलने का काम आप लोग करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [xx] मत कहो, असत्य कहो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अब आप लोग जो समझें । असत्य भी बोल सकते हैं, [xx] भी बोल सकते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [xx] शब्द विलोपित होगा । माननीय अध्यक्ष जी [xx] शब्द को विलोपित करेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर साहब, कतको कुछ बोल लौ, तोला मिलही बाबा जी के ठुल्लू । तोला कुछु नहीं मिलने वाला हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [xx] शब्द असंसदीय है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यहां पर फिल्म सिटी की बात आ रही है । हम उसका स्वागत करते हैं, फिल्म सिटी का निर्माण बिल्कुल होना चाहिए । यहां के स्थानीय कलाकार को उसका मान मिले, सम्मान मिले । क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [xx] तो सेंसर बोर्ड से पास हुआ है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैंने भी 20 साल तक उस विधा में काम किया है । मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के कलाकार को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परम्परा को उस फिल्म सिटी में सम्मान मिले, ताकि मुम्बई से आये कलाकार यहां पर प्रस्तुति न दें, यहां के स्थानीय कलाकारों को तराश कर हम उस स्तर तक खड़ा करें, हमें भी पता चले कि छत्तीसगढ़ में भी रामो जी फिल्म सिटी टाईप का एक संस्था यहां पर है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय उप राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ के दौरे में आये थे, तो यहां के कलाकारों को प्रस्तुति देने के लिए 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन वह प्रस्तुति नहीं दे पाए और उपराष्ट्रपति जी चले गए। उस जगह, उस मंच पर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कलाकार का सम्मान हुआ है। अभी माननीय सुनील भैय्या बहुत अच्छी बात किए। अमृत मिशन की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गुंडरदेही और नगर अर्जुन्दा में अमृत मिशन-2 का टेंडर लगा है। राजस्थान की कंपनी श्रीहरि इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड को दिया गया है और जहां पर टंकी का निर्माण करना है, वहां पर अभी धान की फसल लगी हुई है और तीन करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। वह किसान कब्जा किया हुआ है। मैं बोलता हूं कि कहां पर निर्माण होगा, कैसे पैसे स्वीकृत हुए और किस प्रकार से दे दिए गए, इस पर भी जॉच होनी चाहिए। सुनीन भैय्या, पाईप लाईन का विस्तार हो रहा है। जब 30-32 करोड़ रुपए की पाईप लाईन का विस्तार हो रहा है, जब वहां पर 35 किलोमीटर पाईप लाईन का विस्तार होगा, तो उसमें कोई बेस नहीं, कोई मापदंड नहीं, उसमें गड्ढा खोद

रहे हैं, पाईप को घिसटाते लाते हैं, उस पाईप के अंदर मिट्टी डली है या क्या डला है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं स्वयं अपने घर का देखा हूं, अगर आप चाहें तो एक जॉच समिति बना लें और मेरे घर के पास पाईप लाईन बना है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। कोई बेस का काम नहीं है, ऐसा काम चल रहा है। मैंने फोन के माध्यम से प्रमुख सचिव जी से बात की, मैंने पत्र भी वाट्सअप किया है कि इसकी जॉच होनी चाहिए। दूसरे दिन उन्होंने स्वीकृति दी कि जॉच होगी लेकिन तीसरे दिन फिर फोन आ जाता है कि अभी नहीं आ रहे हैं, बाद में आयेंगे। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो है, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए ताकि जो 30-30, 60-60 करोड़ की बात करते हैं, प्रधान मंत्री जी के स्वप्न की बात करते हैं, प्रधान मंत्री जी के योजनाओं की बात करते हैं, इसलिए इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गौठान पर बहुत बड़ी-बड़ी बात हुई। सब लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन ये भूल गए कि उस योजना से हजारों परिवारों चाहे वे महिला हों या युवा हो, रोजगार मिल रहा था और खासकर गौपालक को इसमें सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा था। आज इस योजना के बंद होने से हजारों परिवारों के ऊपर रोजगार का संकट आ गया है। आपने कहा है कि गौ अभयारण्य बनायेंगे और उसका संरक्षण करेंगे, लेकिन हम सालभर से देख रहे हैं कि कहीं पर भी इस योजना के संबंध में कोई भी गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। आप इसे चालू करें, हम इसका स्वागत करेंगे कि आप भी गौमाता की सेवा के लिए तत्पर हैं और उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं, जो पूर्व में स्वीकृत हो चुके थे, जिसका भूमिपूजन हो चुका था, आपके सांसद और हम दोनों लोग संयुक्त रूप से किए थे, लेकिन अप्रारंभ लिखकर उसकी राशि को वापस कर दिया गया। मैं इसके लिए भी निवेदन करता हूं। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से दो-तीन बार आग्रह भी किया, पत्र भी दिया है कि जितने भी अप्रारंभ कार्य हैं, जिन्हें आपने अस्वीकृत किया है, उसे तत्काल स्वीकृत करें, क्योंकि जिसका भूमिपूजन हो गया, ऐसे बहुत से काम थे, जो आज भी अपनी बाट जोह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद:- अध्यक्ष महोदय, मैं बस दो बात कहना चाहूंगा। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा के भाठागांव-बी गए थे। वहां आदिवासी कंवर समाज के द्वारा एक बड़ा आयोजन रखा गया था। वहॉ 64 साल से एक स्कूल संचालित है- नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला और श्रीराम विद्या मंदिर अनुदान प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शाला, जिसके शासकीयकरण की बात हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंच से घोषणा की है कि कैबिनेट की बैठक में रखेंगे और बजट में प्रावधान रखेंगे और आपका हो जाएगा लेकिन मैं इस बजट में देख रहा हूं कि कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्री जी वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में गए थे, समाज के प्रमुखों ने मांग रखी थी और उनके समाज के द्वारा संचालित

ये विद्यालय है, इसलिए जरूर उसे सम्मान मिले, ताकि आदिवासी परिवार जिन्होंने एक निष्ठा, एक विश्वास के साथ उस विद्यालय को संचालित किया था और अनुदान प्राप्त केवल एक शिक्षक के भरोसे वह हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हो रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय विभागीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप लोग जरूर जो स्वीकृत काम हैं, जिन्हें आप लोगों ने निरस्त किया है, उसे प्रारंभ करेंगे। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री, ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने सब के विचार सुने। इस सदन में जितने लोग बैठे हैं, उनमें से लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित है। 85 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की आय का श्रोत कृषि है। सरकारें आयीं और गयीं लेकिन कभी किसी ने चिंता नहीं की कि छत्तीसगढ़ में कृषि के आधार पर आधारित कृषि भाइयों का भला कैसे हो। राजनीतिक लोगों ने चिंता करनी चालू की तो उनके ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि किसी का विजन, किसी की सोच, किसी की कल्पना को मूर्त रूप देना और उसको आकार में खड़ा करना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। एक गांव का निकला हुआ नौजवान जब आई.ए.एस. की परीक्षा में पास होने के बाद कलेक्टर का पद छोड़कर समाज की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ता है तो हमें ऐसे साथी का हौसला बढ़ाना चाहिए और हमें आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। कलेक्टर को क्या सुविधाएं नहीं मिलती है ? कलेक्टर का पद छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक कलेक्टर, एक जिला का राजा होता है। उसके अधीन सब कुछ होता है लेकिन उसने देखा कि मैं छत्तीसगढ़ की इस माटी का बेटा हूं, यहां पर रहता हूं, यहां का पला-बढ़ा हूं, यहां का खेला हुआ हूं, यहीं जवान पैदा हुआ हूं, उसके कारण वे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का संकल्प लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आये। आज उसी विजन के साथ यदि उन्होंने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है, तो वह विषय महत्वपूर्ण है। अनुपूरक बजट में वह चीजें आती हैं। यदि सामान्य रूप से केंद्र सरकार की कोई योजना आयी और उस योजना में कुछ अंशदान देना होता है, तो वह अनुपूरक बजट में आता है। यदि किसी का घाटापूर्ति करना होता है तो अनुपूरक में उसका अंशदान आता है। लेकिन अनुपूरक बजट के अंदर यदि 60 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आवश्यकता की पूर्ति करने का बजट आता है ,तो एक विजन आता है, एक सोच आती है, एक कल्पना आती है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम दो दिनों से धान के विषय में चर्चा सुन रहे हैं। यह चिंता स्वाभाविक है क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान धान पैदा करता है और बेचता है। उसकी मूल कमाई वही है। यदि उसमें कहीं कमी बेशी है तो उसको ठीक करने के लिये वह सरकार पर डिपेंड है और सरकार के संज्ञान में लाना विपक्ष का काम है। लेकिन केवल संज्ञान में लाना ही नहीं, उनको इम्पलीमेंट करने वाले लोग यहां बैठे हैं । पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। यह चुनी हुई पहली सरकार है, जो 2 महीने

के अंदर धान खरीदती है और 100 प्रतिशत पेमेंट देती है, तो सरकार का विजन वहां समझ में आना चाहिए (मेजों की थपथपाहट)। हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा और प्रति क्विंटल 3100 रूपये दिया। यदि कुछ लोग समझना चाहते हैं तो मैं उनको आंकड़ों में समझा देता हूं। मैं मुंहजबानी नहीं बोल रहा हूं।

श्री विक्रम मंडावी :- राजेश भैया, 3100 रूपये एकमुश्त कहां दिया गया है ?

श्री राजेश मूणत :- पहले सुन तो लीजिये। मैंने कहा न कि ऊंगली उठाने के पहले तीन ऊंगलियां अपनी तरफ होती है। वर्ष 2019-20 में कांग्रेस पार्टी ने जो धान खरीदी का भुगतान किया है और जो धान खरीदा है, उसकी भी तुलना कर लीजियेगा। 56 करोड़ 27 लाख रूपये। दूसरा, 55 करोड़ 53 लाख रूपये। 70 करोड़ 5 लाख। आपने कुल 23 करोड़ 77 लाख धान खरीदी की। अब उस समय का 197 करोड़ 50 लाख 68 हजार रूपये पुराना भुगतान बाकी है। अभी तक इन्होंने आपके लिये जो एक रिकॉर्ड बना दिया, उस रिकॉर्ड में हितग्राहियों की संख्या सुन लीजिये।

समय
7.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, यह 28 करोड़ 22 लाख 66 हजार है। यह हितग्राही हैं जिनसे धान खरीदा गया। मैंने आपको कृषकों की संख्या बतायी है। वर्ष 2024 यानी आज तक 1 लाख 32 हजार 88.99 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। अब कुछ आंकड़ों में फेर-बदल है। जब माननीय ओ.पी. जी उत्तर देंगे तो आपके पास बचा हुआ डिटेल आ जाएगा। अब यह जो है वर्ष 2024 में किसान का पूरा का पूरा पेमेण्ट हुआ। आपने उनसे कितना खरीदा, आपने उनको कितना दिया । आज जो पेमेण्ट है आप यह सोचिए । पूर्व में आप 2500 में धान के समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे। आज 3100 रूपये में धान खरीदी हो रही है और प्रदेश के किसानों से 1 लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसमें 600 रूपये का न्यूनतम अंतर है। जो आप धान खरीदते थे उससे हमने ज्यादा खरीदा है तो क्या यह हमारे प्रदेश के किसानों के खाते में नहीं गया ?15 से लेकर 21 व्यवस्था में सुधार हुआ। यह सरकार सुधार के लिए कटिबद्ध है। हमारे सुझाव अमूल्य हैं। सरकार द्वारा उसका क्रियान्वयन होगा। हमारे इस साय-साय सरकार में सांय-सांय काम होते हैं और इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ। अभी सब लोग बात कर रहे थे। माननीय महंत जी बैठे हैं, वह बड़े नेता हैं। यहां नक्सली समस्या पर बात होती है। दादी, कवासी लखमा जी बैठे हैं। इन 1 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के 5 सालों में गृहमंत्री जी का इतिहास उठा लीजिएगा। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व गृहमंत्री रहे, उनका इतिहास उठा लीजिएगा कि उन्होंने बस्तर में जाकर नक्सल समस्या के संबंध में मिटिंग कितनी बार की और केन्द्र में कितनी बार गये। वहां पर कितनी बार टोला करके आये। अभी नक्सल के संबंध में कोई चिंता ही नहीं थी। जब बस्तर के नक्सल क्षेत्र में हमारे युवा ओलम्पिक करके, जो बच्चे लौटकर आ गये। वहां पर एक अनुकूल वातावरण

बनाने के लिए ओलम्पिक की तर्ज पर ओलम्पिक का आयोजन होता है । जब वहां पर अबूझमाड़, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर का लड़का खेलता है तो आप यह सोचिए कि एक सही दिशा, एक लक्ष्य है जिसमें वह आगे बढ़ने का काम कर रहा है। वहां पर तीरनदाजी बहुत अच्छी होती है। वहां बस्तर के रहने वाले भाई हैं वहां पर मुर्गा लड़ाई कितनी अच्छी होती है। अगर वहां पर जाकर हम ओलम्पिक खेलों का आयोजन करवा रहे हैं जिसमें देश का गृहमंत्री आते हैं और तीन दिनों तक वहीं रहते हैं वहां उनसे रूबरू होता है उनसे नक्सल समस्या के संबंध में बात करते हैं। वहां पर विस्थापित परिवार से बातचीत करते हैं तो भी उनके अंदर दर्द होता है। दादी, एक बार आपको भी जाकर मिल लेना था। आप तो बस्तर की आवाज हैं।

श्री कवासी लखमा :- हमें वहां बुलाया ही नहीं।

श्री राजेश मूणत :- इसमें बुलाना क्या ? वह बस्तर क्षेत्र हमारा है आप अपने आपको वहां के नेता मानते हैं तो आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। उनसे यह कहना चाहिए कि सर, आप यहां बस्तर आयें, यहां पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी भी इस बस्तर में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं हैं, इस पर आप विचार जरूर करें। उसे जनप्रतिनिधि कहते हैं। एक जनप्रतिनिधि रहता है तो कोई मंत्री जाता है, कोई विधायक जाता है, कोई सांसद जाता है तो अपने पास का व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता है या नहीं आता है। हर समाज, वर्ग जाति, आपको तो वोट की राजनीति पड़ी है। वहां की समस्या का समाधान होना, कभी यह आपका उद्देश्य नहीं रहा है। अभी मैं इस बात को और इसलिए कह रहा हूँ । माननीय ओ.पी. चौधरी जी बस्तर के दंतेवाड़ा के कलेक्टर रहे हैं अगर दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब बन सकता है तो यह कल्पना कोई नहीं कर सकता था क्या ?

श्री कवासी लखमा :- वहां सड़क चालू थी उसको बंद कर दिया गया।

श्री राजेश मूणत :- वहां उस क्षेत्र में सड़क बनाने वाला इधर खड़ा है।

श्री कवासी लखमा :- वहां उस सुदूर क्षेत्र तक सड़कें नहीं गयी हैं।

श्री राजेश मूणत :- आप क्या बात करते हैं। वहां पर कहां तक सड़कें नहीं गईं। वहां आप भी तो मेरे साथ घूमे हैं फिर क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं ? अगर वहां पर प्रयास जैसी बड़ी संस्था प्रारंभ हो सकती है। वहां पर बस्तर के बच्चों को पायलेट ट्रेनिंग की सुविधा मिल सकती है। अगर उनको एयर होस्टेज की ट्रेनिंग की सुविधा मिल सकती है, एयर होस्टेस ट्रेनिंग की सुविधा मिल सकती है तो क्या बस्तर का बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बस्तर के बच्चों के लिए 5 साल में कोई विजन बनाया हो तो बता दीजिए। बस्तर में एक मेडिकल कॉलेज खोला हो, बस्तर में कोई एक नया काम किया हो तो बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज भी डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में बस्तर में बना। आपने कभी कल्पना नहीं की। वहां के अस्पताल की क्या हालत थी?

श्री कवासी लखमा :- हमारी सरकार ने दंतेवाड़ा में घोषणा की थी, उसको चालू करिये न। कांकेर में चालू किया है।

श्री राजेश मूणत :- आप घोषणावीर की बात ही मत करिये।

श्री कवासी लखमा :- जगरगुण्डा में अभी बिल्डिंग बना रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, बीजापुर में हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब सब डॉक्टर भग गये। वह लोग आन्ध्रा चले जा रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- जिला बनाया, सर्किट हाउस बनाया। सुकमा में रूकने तक की जगह नहीं थी, सर्किट हाउस बनाने वाला मै हूं। दादी, आप क्या बात करते हैं ? वह सर्किट हाउस में सोने के लिए जो रूम मिल रहा है, वह अध्यक्ष जी की पूर्व मेहरबानी समझिये।

श्री रामकुमार यादव :- देश को आजाद हमन कराये हन।

श्री राजेश मूणत :- यादव जी, अभी रूक जाईए, एक-एक आ रहा है।

श्री कवासी लखमा :- बीजापुर, भोपालपट्टनम में पूरे बाजार बंद थे, बसें बंद थीं, किस्टाराम-मेमेलागुंडा में बस चल रही है। 05 साल पहले भेज्जी बाजार बंद था, अब बाजार लग रही है। उसको वहां जाकर देखना।

श्री राजेश मूणत :- दादी, अब मैं आपका उत्तर दूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। हम शहीद नेताओं की बात करते हैं। मैं माफी चाहते हुए कहता हूं, मेरे मन में कभी-कभी दर्द होता है। आप जगदलपुर में जाना, जगदलपुर में आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक स्मारक बनाया, वह स्मारक को एक बार देखकर आना, यहां जितने बैठे हुए हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं। उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढा दिये। पूरा पैसा खा गये, उसके अंदर 3 करोड़ रुपये खर्च हुआ। मैं महंत जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ी-बड़ी बात करने वाले, महेन्द्र कर्मा जी शेर थे, शेर रहेंगे। नंदकुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी नेता थे, शर्मा जी नेता थे, वह छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे थे, हमेशा रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। हमारे लिए वह वोट की राजनीति के कभी नहीं रहेंगे। आपके यहां प्रापर जगदलपुर में आपने शहीद के नाम पर स्मारक बनाया, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मैं खुद जा करके देख करके आया हूं। आप क्या बात करते हो, किसकी बात करते हो ? आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है ? आप बस्तर में चाहते कि नक्सलवाद पनपे और आपकी नेतागिरी चलती रहे। शहरी नक्सली और ग्रामीण मिल करके धंधा पानी चलाते रहें। अगर बस्तर के अंदर जा करके दो पुल बना देते हैं, वहां पर उस पुल की जिले के कलेक्टर के लिए आवश्यकता है, वहां सेना को जाने के लिए आवश्यकता है तो हम भ्रष्टाचार कर दिये। दादी, आपके राज में क्या-क्या हुआ, पूरा 05 साल का इतिहास गिनाऊं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मूणत जी, आप इस बात को इस सदन में मेरे हिसाब से तीसरी बार बोल चुके हैं कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- मेरे भाई, 300 करोड़ रुपये का नहीं, आप पहले सुन तो लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप जांच क्यों नहीं करवाते, कार्रवाई क्यों नहीं कराते ? आप केवल ध्यान को बांटने का काम कर रहे हैं। यह हकीकत नहीं है। यदि हकीकत है तो आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते ? आप इस सदन में इस बात को तीसरी बार बोल चुके हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय राजेश भैया, आपके शब्दों में बार-बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बने हुए एक साल हो गये हैं। आप ऐसे सभी मामलों की जांच करिये और कार्रवाई करवाईये, आपको कौन रोक रहा है ? आप बार-बार इस तरह से बात कर रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- मैं उसमें भी आऊंगा। मैं एक-एक बात बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर बस्तर से प्रेम है और उन नेताओं के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हो तो जिनके नाम पर आपने स्मारक बनाया, वह स्मारक भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ा ? जिनने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ? (शेम-शेम की आवाज) मेरा उतना ही है, आप सुन तो लीजिए। आपकी सरकार के कार्यकाल में बना।

श्री विक्रम मंडावी :- पहली बात तो आप यह तय करिये कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री राजेश मूणत :- हुआ है।

श्री विक्रम मंडावी :- यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप कार्रवाई करिये। आपको किसने रोका है ? आप पहले तय तो करिये। आप तय ही नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- हम करेंगे। आप रूकिये न। क्या आप उसमें इनवॉल्वमेंट हैं ? क्या उसमें आपका कुछ है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अगर उनका रहता तो वे कार्यवाही की मांग क्यों करते ?

श्री राजेश मूणत :- मेरे मित्र, सुन तो लो । भैया यादव जी मैं आपके साथ चलूंगा । हम आज रात को ही दोनों भाई बस की टिकट कटवा लेते हैं । वह अगर गलत है...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, वह ठीक है । मैं जाने के लिये तैयार हूं लेकिन आप केवल सदन में इस बात को लाते हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि जांच क्यों नहीं हो रही है ?

श्री राजेश मूणत :- सब हो जायेगी । जिनके जेब के अंदर सबूत रखे थे, वह सबूत कहां चले गये ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उनकी बात छोडिए न । आप अपनी बात बताईये न। (व्यवधान) अपनी बात बोलिए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अभी आप भ्रष्टाचार से अब सबूत में आ गये । (व्यवधान) सबूत कहां से आ गया ?

श्री राजेश मूणत :- जिनकी जेब में सबूत थे वह सबूत कहां चले गये ? हमारी सरकार में काम होगा । मैंने बस्तर की तीन चीजों में जल, जंगल और जमीन । यह तीनों बस्तर के भाईयों की है, रहेगी, यह हमारा वचन है, कटिबद्ध है । साय सरकार के अंदर काम की गति बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता । मैंने इस बात को इसलिए कहा है कि बस्तर का vision है जिसे complement करके आगे बढ़ना चाहते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं । मैं नेताजी के भी ध्यान में लाना चाहता हूं । ये Infrastructure की बात करते हैं, अभी Infrastructure के लिए सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, खम्भा लगाने के लिए पैसा दिया । पूर्व सरकार ने सड़क विकास निगम में 5000 करोड़ रूपये का लोन लिया । कितना 5000 करोड़ रूपये का लोन लिया, डेढ़ हजार करोड़ रूपये केवल ब्याज में ही पटा दिया । काम क्या हुआ ? ओ.पी. चौधरी जी रायपुर के कलेक्टर थे। अगर रेल की पटरी उखड़कर डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में और भाजपा सरकार में एक्सप्रेस वे बन सकता है तो काम इसे कहते हैं कि कुछ करके दिखाओ । (मेजों की थपथपाहट) अगर केनाल रोड बन सकती है तो विज़न चाहिए, सोच चाहिए, कल्पना चाहिए, कुछ करने की इच्छा-तमन्ना चाहिए । डेढ़ करोड़ रूपये खाली ब्याज में, पी.डब्ल्यू.डी विभाग क्या करेगा ? सड़क विकास निगम में जितने भी टेंडर हैं उसे सड़क विकास निगम में करो । उसका setup ही नहीं है, उस विभाग में कुल 15 या 20 आदमी काम कर रहे हैं, सड़क विकास निगम में और मूल विभाग चुपचाप बैठा है। सर्वे वह करेगा, एस्टीमेट वह बनायेगा, टेंडर कौन बुलायेगा सड़क विकास निगम । यह भी हिंदुस्तान में एक देखने लायक चीज़ मिली ।

श्री रामकुमार यादव :- स्काईवाक ला तो तुमन बनाये रहेओ काय साहब ?

श्री राजेश मूणत :- अरे सुन तो लीजिये, मैं सब बताउंगा ।

श्री रामकुमार यादव :- आज ले ओ मुड़ मा जाहा ता डर लागथे कि गिर झन जही करके ।

श्री राजेश मूणत :- सुनना भाई । आपकी सरकार में 5 साल में स्काईवॉक की जांच करा ली है । वह थाने में लिखकर भेज भी दिये थे, ई.ओ.डब्ल्यू. में जांच के लिये भी भेज दिये थे, 5 साल कुछ नहीं कर पाये । मैं डंके की चोट में राजनीति करता हूं, विचार और सिद्धांत की करता हूं, व्यक्तिगत राजनीति नहीं करता । जब हम बात करें विकास की, development की तो आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है । आज की स्थिति भी यही करके रखी है । आप स्मार्ट सिटी के ऊपर बातचीत हुई । 15 सालों में रायपुर में कांग्रेस पार्टी का राज है । करीब साढ़े 700 करोड़ रूपये स्मार्ट सिटी में खर्च हुआ है और मैं एक उदाहरण स्परूप बता दिया कि एक भी तालाब, माननीय महंत जी भी रायपुर में घूमते हैं, कवासी भाई भी रायपुर में घूमते हैं, अनिता भाभी भी यहीं रायपुर में घूमती हैं । तीन बार पाथ-वे बना, लाईट लगी, खम्भा लगा, 37 करोड़ रूपये केवल उमसें खर्च । नगर-निगम में अलग खर्च ।

अब आप कहोगे कि आरोप लगा रहे हैं । वहां का पैसा मंत्री के बंगले में खर्च यानी क्या चल रहा है ? शासन क्या प्रशासन ? मैं वह आरोप नहीं लगाऊंगा कि 25 रूपये टन कौन लेता था, मैं वह आरोप नहीं लगाऊंगा कि Congress के विधायक दिल्ली गए थे और ticket किसने कटवाई थी उसका cheque number तक मेरे पास है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप द्वितीय अनुपूरक तक सीमित रहें ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस यहीं तक रहूंगा । मैं इसीलिए उसमें जाऊंगा ही नहीं लेकिन यह चीज़ कहना चाहता हूं कि जिस vision के साथ में चौधरी जी ने कुछ चीज़ें कही हैं । हमें आने वाले छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए जो कमोबेशी होगी उसको ठीक करना हमारा काम है । लेकिन एक डेवलपमेंट विजन के साथ में काम करना, अगर हमारी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आप सोचें तो भैया आपका भी समय था, आपने क्यों नहीं कर दिया? आपने भी तो चुनाव में घोषणा किया? फॉर्म भी भरवाये। आप भी देश में कई प्रांतों में जाकर 2100 रूपये, 2500 रूपये तक के फॉर्म भराये। कांग्रेस पार्टी पर जनता को विश्वास नहीं है और इसीलिए विश्वास था तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 700 करोड़ रूपया डाले और हर बहन के खाते में जाते हैं और बिचौलियो का काम खत्म हो गया। डायरेक्ट एस.एम.एस. होता है। (मेजों की थपथपाहट) ये चिंता नहीं है क्या? लोग कहते हैं उसको नहीं मिल रहा है, आप दीजिए। आप जन प्रतिनिधि हैं, आप उसको सहयोग कराइए, वह बहन आपकी तारीफ करेगी कि इसके कहने पर मुझे मिल रहा है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा और अपनी विधान सभा में नहीं चाहिए तो लिखकर दे दीजिए कि हमारी विधान सभा में नहीं चाहिए। हमारा कार्यकर्ता बनाएगा, लेकर आएगा, हम करवा देंगे। चिंता क्यों करते हैं? लेकिन ये राजीव मितान क्लब टाइप का नहीं होगा। राजीव मितान क्लब खड़े कर दिये। अब राजीव मितान क्लब में क्या था? मैंने इसी हाउस में प्रश्न पूछा था, माननीय नेता जी, आपको भी पता होगा। राजीव मितान क्लब का एक सम्मेलन हुआ। 3 करोड़ रूपये की टी शर्ट, टोपी खरीदी। ना तो टेंडर हुआ। ना कुछ हुआ। राहुल गांधी जी आए, टी शर्ट पहनाकर बैठा दिए। भाषण करवा दिए। वे चले भी गए। फोटो भी ले लिए। लेकिन उसके बाद वह बेचारा आदमी दर-दर घूमता फिरता है कि साहब मेरा पैसा कौन देगा? ना तो वर्क ऑर्डर दिए। तो भैया उस पर भी कुछ बोल देना। दादी, आप नहीं बोलो तो ही अच्छा है। आपने तो बताया ना, धर्म भैया बता दिये मंथली फिक्स था इतना क्या लगाये हो? आप तो केवल हमारे तस्वीर हैं। बचा होगा तो जिसको काम करना था, वह खनक वाली आवाज कहां चले गई? मैं तो नहीं जानता, वह अजय चंद्राकर जी जानते हैं। लेकिन यह बात तो इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की कहानी को लिखना है तो ऊंगली उठाने के पहले तीर मेरी मेरी तरफ भी आती है। व्यवस्था में सुधार, काम की प्रगति, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। यह छत्तीसगढ़ राज्य आपका अपना हमारा सबका है, हम सबने मिलकर इस राज्य की रचना की है। इसको आगे बढ़ाने का काम जब एक

अच्छा नौजवान साथी काम कर रहा है तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए और उसके काम को गति देने के लिए सहयोग करना चाहिए। मैं माननीय चौधरी जी को तीन चार सुझाव देना चाहता हूं। आवास पर्यावरण मंत्री हैं। मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम मास्टर प्लान की कल्पना करते हैं। शहर को विकसित प्लानिंग के साथ में बसाने के लिए मास्टर प्लान बनाते हैं। एक विजन होता है कि 20 साल के बाद में शहर के अंदर कितनी आबादी बढ़ेगी, कितना बड़ा क्षेत्र होगा? क्या-क्या आवश्यकता होनी चाहिए? खेल मैदान होना चाहिए कि वहां पर गार्डन कितने होना चाहिए, वहां पर रोड की चौड़ाई कितनी होना चाहिए, सब विजन के साथ मास्टर प्लान बनता है कि कुल कितनी आबादी आएगी? पूर्व सरकार नियमितीकरण के नाम पर तो इस शहर के अंदर खेल खेलकर चले गये, साहब। 2000 स्क्वेयर फीट का प्लाट नहीं है। अंडरग्राउंड पार्किंग दे दी और पार्किंग को नियमितीकरण कर दिया और सड़क के ऊपर पूरी गाड़ियां खड़ी हो गईं। ये पूरे प्रदेश का इतना बड़ा मामला है कि शहर के रोड की चौड़ीकरण करें तो कहां से पैसा लाओगे? शहर के रोड कैसे बनाओगे? ये मास्टर प्लान के अंदर जिस प्रकार की धज्जियां नियमितीकरण के नाम पर उड़ी है। आज आप एक संकल्प लेकर आए हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि आप रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, यह शहर रहेगा। इस साल के अंदर जिस विजन और उत्सुकता के साथ शहर का डेवलपमेंट हुआ है, जरा निर्णय करने के पहले दूरगामी परिणाम पर जरूर विचार करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे युवा ओलंपिक हुआ, आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर भी ओलंपिक टाइप का होना चाहिए। जिले के अंदर खेलकूद होना चाहिए। इसका साल भर का कैलेंडर बनना चाहिए कि इस महीने इनका एडमिशन होगा। एडमिशन होगी तो पढ़ाई होगी और उसके बाद हफ्ता/पन्द्रह दिन के लिए खेल टाईप का होना चाहिए ताकि स्कूल की प्रतिभा निकलकर जिले में आए और जिले के बाद प्रांत स्तर पर खेल आयोजन होना चाहिए और खेल मंत्री को भी मैं धन्यवाद् दूंगा जिन्होंने पांच साल से रूके हुए अलंकरण को समारोह आयोजित कर प्रदान किया, जिसे आपने रोककर रखा था । खेल मंत्री, वित्त मंत्री और विष्णुदेव साय सरकार ने वापस अलंकरण समारोह के माध्यम से करोड़ों रूपए उनको इनाम में वापस दिया और उनकी नौकरी सुनिश्चित की । यह कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं था, आप कैसे नहीं कर पाए आज तक ? इसीलिए यह विज़न है, अध्यक्ष जी मेरे पास विषय बहुत है लेकिन मुझे मालूम है समय कम है लेकिन आप सब इन बातों से सहमत हैं । पूर्व में माननीय सदस्यों ने विषय रखे, मैं उन विषयों को रिपीट नहीं करना चाहता । माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है लेकिन मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग सरकार का नोडल एजेंसी विभाग है । आजकल हर विभाग अपने मूल काम को छोड़कर निर्माण करने लग गया है । शिक्षा वाला भी कर रहा है, उच्च शिक्षा भी कर रहा है, स्वास्थ्य वाला भी कर रहा है, इरीगेशन वाला भी कर रहा है, नगर निगम भी कर रहा है । नगर निगम

का काम होता है रोड की सफाई, नाली की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो, प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो । मूल काम को छोड़कर बचे हुए सब काम कर रहे हैं । मेरा आग्रह है कि जब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आपके पास विद्‌वान इंजीनियर, विद्‌वान टीम और सरकार का स्वयं का विभाग बना हुआ है तो इस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, जिस विभाग के अंदर स्पेशलिस्ट लोग हैं, जिस विभाग की जिम्मेदारी है, उसको यह काम करना चाहिए । इस बात का आग्रह मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्‌वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर शेष चर्चा दिनांक 19.12.2024 को भी होगी । माननीय नेता प्रतिपक्ष द्‌वारा अपनी बात रखी जाएगी, उसके पश्चात् वित्त मंत्री जी जवाब देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित् ।

(सायं 07 बजकर 23 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 28, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधन सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
17 दिसम्बर, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं